दैनिक जागरण

आशा का एक दीया ही जीवन को प्रकाशित करने में सक्षम है

पाकिस्तान का छलावा

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय संगठन एफएटीएफ की अगले माह होने वाली बैठक के पहले जिस तरह भारत में वांछित आतंकी सरगना मसूद अजहर पर इनामी राशि 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की, वह मनी लांड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर लगाम लगाने वाली इस संस्था के साथ-साथ विश्व की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ही है। पाकिस्तान की धोखेबाजी का परिचय इससे मिलता है कि उसने कुछ समय पहले यह अफवाह फैलाई थी कि जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान में कहीं छिपा है। अफगानिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार वह पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर इनामी राशि बढ़ाने के साथ आतंकियों की जो नई सूची जारी की, उसमें अनेक नाम ऐसे हैं, जो भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान ने आतंकियों की नई सूची में से कई के फोटो हटा दिए हैं और उनका आतंकी संगठनों से संबंध भी छिपा लिया है, जबकि पहले की सूची में उनके फोटो और इसका विवरण भी था कि वे किस आतंकी संगठन के लिए काम करते हैं। पता नहीं एफएटीएफ पाकिस्तान के छलावे को भांप सकेगा या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि वह कठोरता का परिचय नहीं देता तो आतंक से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकेगा। एफएटीएफ ने 2022 में पाकिस्तान को इसलिए अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया था, क्योंकि यह लग रहा था कि वह अपने यहां के आतंकी ढांचे को खत्म कर रहा है, लेकिन ऐसा होते ही वह फिर से आतंकियों को पालने-पोसने में जुट गया।

पाकिस्तान में जैश और लश्कर सरीखे आतंकी संगठन पहले की ही तरह न केवल सक्रिय हैं, बल्कि फल-फूल भी रहे हैं। वे चंदा इकट्ठा करने के साथ ही आतंकियों की भर्ती भी करते रहते हैं। चूंकि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को अपनी सुरक्षा नीति का हिस्सा बना लिया है, इसलिए वहां आतंकी संगठनों की सक्रियता खत्म होने का नाम नहीं लेती। वह आतंकियों को पालकर भारत ही नहीं, अन्य देशों के लिए भी खतरा बन रहा है। विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी एफएटीएफ इसकी अनदेखी कर रहा है। इसका कारण यह है कि इस संगठन में प्रभावी कुछ देश पाकिस्तान के हितैषी बने हुए हैं। इनमें प्रमुख है अमेरिका। जो अमेरिका पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से पीड़ित रहा, वह इससे मुंह फेरे है कि इस देश में किस तरह आतंकवाद फल-फूल रहा है। पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद वैश्विक जिहाद को खाद-पानी दे रहा है और यह जिहाद अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकता है। इसमें संदेह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखें खुलेंगी, लेकिन एफएटीएफ में शामिल अन्य देशों को पाकिस्तान से उभर रहे खतरे का संज्ञान लेना चाहिए। वे ऐसा करें, इसके लिए भारत को इस संगठन में अपनी उपस्थिति का उपयोग करना होगा।

अवसरों का विस्तार

उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों में सीटों की बढ़ोतरी से नए अवसर मिलेंगे, पर इसके सापेक्ष सरकारी मेडिकल कालेजों की सीटों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि का नहीं होना निराश करता है। सरकारी मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को फीस कम भरनी पड़ती है, वहीं भारी फीस के कारण निजी मेडिकल कालेजों में पढ़ाई करना सबके वश की बात नहीं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नीट-2026 के माध्यम से होने वाले प्रवेश के लिए एमबीबीएस की 1,200 सीटें निजी संस्थानों में बढ़ाई गई हैं। शासन इस बात की पड़ताल कराए कि सरकारी मेडिकल कालेजों में आखिर सीटें नहीं बढ़ने के कारण क्या हैं? चिकित्सा विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन्हें आगे बढ़कर इसकी चिंता होनी चाहिए। गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सरकारी संस्थानों की सीमित सीटें अब भी बड़ी बाधा बनी हुई हैं। पढ़ने वालों की दिलचस्पी और प्राथमिकता भी सरकारी मेडिकल कालेजों में नामांकन की होती है। ऐसे में यहां सीट बढ़नी ही चाहिए। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में एक भी सीट नहीं बढ़ी। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रथम विकल्प चुनते हैं। आवश्यक है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय सीटें बढ़ाने का दावा करें और जो कमियां रह गईं हैं, उन्हें दूर कर अगले सत्र में सीटें बढ़वाने का प्रयास करें।

> चिकित्सा शिक्षा में अवसरों का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब उसकी पहुंच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सुनिश्चित हो

ब्रिक्स सम्मेलन के बीच भारत-चीन संबंध

आनंद कुमार

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा यही दर्शाती हैं कि दोनों देश संबंधों में एक नई स्थिरता तलाश रहे हैं, पर इसे अंतिम सफलता मानना सही नहीं

नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वां ब्रिक्स सम्मेलन केवल एक बहुपक्षीय आयोजन नहीं था। यह बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और उसके कूटनीतिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण संकेतक भी रहा। सम्मेलन में वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते रणनीतिक महत्व तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। हालांकि भारत के लिए इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष चीन के साथ संबंधों में स्थिरता के रूप में भी दिखा। सम्मेलन के दौरान भारत का जोर इस पर रहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों का सबसे अधिक सामना करता है, लेकिन वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उसकी भूमिका अभी भी अपेक्षाकृत सीमित है। इस क्रम में नई दिल्ली घोषणापत्र का सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना भी महत्वपूर्ण है। विस्तारित ब्रिक्स में ऐसे देश शामिल हैं, जिनके बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, रूस और पश्चिम के बीच गंभीर टकराव है तथा ईरान के पश्चिमी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं। इसके बावजूद ब्रिक्स देश वैश्विक शासन, विकास, तकनीक और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने में सफल रहे। यह बताता है कि ब्रिक्स किसी एक विचारधारा या किसी विशेष देश के विरोध का मंच बनने के बजाय विभिन्न शक्तियों में सहयोग का मंच बनने की क्षमता रखता है।

भारत-चीन संबंधों में आई नई हलचल को भी देखा जाना चाहिए। 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर गिरावट आई थी। ऐसे में शी चिनफिंग की सात वर्ष बाद भारत यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दोनों देश संबंधों को पूरी तरह टकराव के रास्ते पर जाने से रोकना चाहते हैं। मोदी और शी की बैठक में दोनों नेताओं ने संबंधों को दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टि से देखने पर जोर दिया। भारत ने यह स्पष्ट किया कि सीमा पर शांति और स्थिरता व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए आवश्यक है। चीन की ओर से भी भारत-चीन संबंधों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने और साझा विकास पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह भाषा अपने आप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन लंबे समय तक चले तनाव के बाद संवाद की वापसी का संकेत जरूर है। भारत-चीन संबंधों के मौजूदा चरण को 'समझौते' से अधिक 'स्थिरीकरण' कहना उचित होगा। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अनेक मतभेद अभी भी कायम हैं। चीन के साथ संबंधों में स्थिरता का अर्थ यह नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों को कम कर दे। भारत की रणनीति तो यह होनी चाहिए कि सीमा पर मजबूत सैन्य स्थिति बनाए रखते हुए राजनीतिक और राजनयिक संवाद को निरंतर जारी रखा जाए।

अवधेश राजपूत

ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी, शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों को कुछ लोग भारत-रूस-चीन के किसी नए रणनीतिक त्रिकोण के संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ऐसा निष्कर्ष जल्दबाजी होगा। तीनों देशों के हित और रणनीतिक प्राथमिकताएं काफी अलग हैं। भारत के अमेरिका के साथ भी संबंध हैं। चीन भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धी है और रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता ने भारत-रूस-चीन त्रिकोण की पुरानी प्रकृति को बदल दिया है। ब्रिक्स ऐसा मंच है, जहां देशों को अपने सभी द्विपक्षीय मतभेद समाप्त किए बिना भी साझा मुद्दों पर सहयोग करने का अवसर मिलता है। भारत और चीन सीमा पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक शासन सुधार, विकास, जलवायु परिवर्तन, तकनीक और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग भी कर सकते हैं। यही बहुपक्षीय कूटनीति की वास्तविक शक्ति है। भारत की विदेश नीति के लिए यह लचीलापन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर सकता है, रूस के साथ पारंपरिक संबंध बनाए रख सकता है, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों से संपर्क बढ़ा सकता है और साथ ही चीन के साथ स्थिर संबंधों की कोशिश कर सकता है।

भारत-चीन संबंधों में आर्थिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन भारत के लिए व्यापार घाटा, बाजार पहुंच, तकनीकी निर्भरता और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता के विषय हैं। यह न भूला जाए कि राजनीतिक संबंधों में सुधार तभी टिकाऊ होगा जब आर्थिक संबंधों में भी अधिक संतुलन और पारदर्शिता आए। भारत को चीन के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण भी जारी रखना होगा। भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद बने रहेंगे। वास्तविक चुनौती यह है कि इसे ऐसे संतुलित किया जाए कि वे सैन्य संकट में न बदलें। इस क्रम में सात वर्ष बाद शी चिनफिंग की भारत यात्रा, मोदी से बातचीत, सीमा पर चीनी सैन्य तैनाती में कमी और विभिन्न संवाद तंत्रों की सक्रियता इसके संकेत हैं कि दोनों देश संबंधों में एक नई स्थिरता तलाश रहे हैं, लेकिन इसे अंतिम सफलता मानना उचित नहीं। यदि आने वाले महीनों में भारत और चीन सीमा पर तनाव को नियंत्रित रखते हुए सैन्य और राजनयिक संवाद जारी रखते हैं, आर्थिक मुद्दों पर व्यावहारिक बातचीत करते हैं और नेतृत्व स्तर पर नियमित संपर्क बनाए रखते हैं, तो दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को अधिक पूर्वानुमेय बनाया जा सकता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी उपयोगी होगी, क्योंकि इससे वह अपने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत के हित में इससे बेहतर स्थिति फिलहाल कोई दूसरी नहीं हो सकती।

(लेखक मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में एसोसिएट फेलो हैं)

response@jagran.com

पंजाब में बिछने लगी चुनावी बिसात

राजकुमार सिंह

सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच होने से रोकने के लिए भाजपा-अकाली गठबंधन जरूरी लगता हैं

भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाने से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच अंतर्कलह थामने में कांग्रेस आलाकमान को कितनी सफलता मिलेगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने ही पंजाब के चुनावी समर में अपनी कमान राजस्थानी सेनापतियों को सौंप दी है। पायलट की तरह भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया भी राजस्थान के ही हैं। पंजाब में सत्ता के सभी खिलाड़ी अपने दांव बड़ी सावधानी से चल रहे हैं। दिल्ली की सत्ता से बेदखल आम आदमी पार्टी के पास अब पंजाब की सत्ता ही बची है तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद कांग्रेस को भी वहां सत्ता में वापसी की संभावनाएं दिख रही हैं। पंथक राजनीति करने वाला शिरोमणि अकाली दल खुद को पंजाब की सत्ता का स्वाभाविक दावेदार मानता है तो देश के दो-तिहाई राज्यों की सत्ता पर काबिज भाजपा को भी इस सीमावर्ती संवेदनशील राज्य की सत्ता चाहिए। भाजपा-अकाली मिल कर कई बार पंजाब पर राज कर चुके हैं, पर फिलहाल रास्ते अलग-अलग हैं। 'वारिस पंजाब दे' अपने अलगाववादी एजेंडा को उभारने की फिराक में हैं।

बेशक विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में हैं, लेकिन चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। सात राज्यसभा सदस्यों के दलबदल से जहां आप को झटका लगा है, वहीं भाजपा के हौसले बुलंद हुए हैं कि सत्तारूढ़ दल छोड़कर इन सांसदों ने उसका दामन थामा। अपने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दूसरी बार पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत से भी भाजपा के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पंजाब में सत्तारूढ़ आप का छात्र संगठन दूसरे और सत्ता की प्रबल दावेदार कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआइ तीसरे स्थान पर रहा। जुलाई में जंतर-मंतर पर 'जेन-जी' आंदोलन से बदले माहौल में यह जीत भाजपा के लिए और भी राहतकारी है। शिरोमणि अकाली दल के छात्र संगठन सोई द्वारा एबीवीपी को समर्थन के भी चुनावी अर्थ निकाले जा रहे हैं। ध्यान रहे

चुनाव से पहले भाजपा-शिअद गठजोड़ की चर्चा। फाइल

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल परिसीमन विधेयक के समर्थन का एलान भी कर चुके हैं। इस घटनाक्रम को भाजपा-अकाली गठबंधन की संभावना के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सत्ता संघर्ष आप और कांग्रेस के बीच सिमटने का जोखिम भाजपा और अकाली दल नहीं उठाना चाहेंगे।

विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों की दशकों पुरानी दोस्ती टूट गई। आप के अप्रत्याशित उभार ने अकाली दल और भाजपा को राज्य की राजनीति में तीसरे और चौथे स्थान पर धकेल दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में 'वारिस पंजाब दे' के नाम पर अमृतपाल सिंह की जीत ने भी खासकर भाजपा और अकाली दल की चिंताएं बढ़ाई हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव पंजाब की राजनीतिक दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सत्तारूढ़ आप को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस चुनौती दे सकता है, लेकिन दोनों में अंतर्कलह कम नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अपना चुनावी खेल खुद बिगाड़ लेने वाली कांग्रेस ने इस बार प्रदेश प्रभारी बदल कर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के बीच अंतर्कलह थामने की कोशिश की है। दलित कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने चन्नी को पिछली बार मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वह दोनों विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। दोनों ही इस समय लोकसभा सदस्य हैं। बड़ी संख्या में दलित कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस चन्नी को यथासंभव संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है।

मायावती की बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का एलान भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं। 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन कर 20 सीटों पर लड़ी थी और नवांशहर की सीट जीत भी गई थी। संस्थापक काशीराम का गृह राज्य होने और देश में सबसे ज्यादा 32 प्रतिशत दलित आबादी होने के बावजूद बसपा का पंजाब में कभी बड़ी राजनीतिक ताकत न बन पाना एक राजनीतिक पहेली है। भाजपा की सारी उम्मीदें पंजाब में बहुकोणीय चुनावी मुकाबले की संभावना पर टिकी हैं, लेकिन उसका लाभ मिलने की कोई गारंटी नहीं। सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच होने से रोकने के लिए भी भाजपा-अकाली गठबंधन जरूरी लगता है। सभी 117 सीटों पर अकेले दम लड़ने की हुंकार भरनेवाली भाजपा 40-45 सीटों से कम पर शायद ही माने। सीमावर्ती संवेदनशील राज्य के रूप में पंजाब की बहुआयामी चुनौतियों के मद्देनजर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को राज्य के व्यापक हित में माननेवाले भी कम नहीं। सुखबीर सिंह बादल का अकाली दल जहां मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं भाजपा शहरी क्षेत्रों और हिंदू समुदाय का। इसीलिए माना जाता है कि दोनों के बीच गठबंधन की बहाली से पंजाब में राजनीतिक के साथ-साथ सामाजिक एकता भी मजबूत होगी। पंजाब आतंकवाद की अंधेरी सुरंग से तो निकल आया है, लेकिन अभी भी अनेक विघ्नसंतोषी तत्व फिर माहौल बिगाड़ने के खतरनाक मंसूबे पाले हुए हैं, जिन्हें नाकाम करना सामूहिक जिम्मेदारी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

क्षमावाणी

संवत्सरी के दिन जैन समाज एक वाक्य दोहराता है- 'मिच्छामि दुक्कड़म्।' यह वाक्य किसी अदालत में दिया गया माफीनामा नहीं है, न ही सामाजिक शिष्टाचार की औपचारिकता। यह एक स्वीकृति है कि मनुष्य अपूर्ण है और यही अपूर्णता उसे विनम्र बनाती है। क्षमा का अर्थ केवल दूसरों से माफी मांगना नहीं, अपने भीतर झांकना भी है। संस्कृत की एक प्राचीन उक्ति है-'क्षमा वीरस्य भूषणम्' अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। इसका गहरा अर्थ यह है कि क्षमा का सर्वोच्च रूप तभी प्रकट होता है, जब प्रतिशोध की शक्ति होते हुए भी मनुष्य संयम को चुनता है। इतिहास में स्थायी शांति वहीं जन्मी है, जहां किसी पक्ष ने अपनी पूर्ण विजय की आकांक्षा से ऊपर उठकर समझौते का साहस दिखाया।

महावीर ने अहिंसा को दार्शनिक आधार दिया। गांधी ने भारतीय अहिंसा की इस परंपरा से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह को राजनीतिक कर्म में बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की गहरी कड़वाहट झेलने के बाद भी बदले का रास्ता नहीं चुना। सत्ता में आते ही उन्होंने 'सत्य एवं सुलह आयोग' बनाया, जहां अपराधी अपना अपराध स्वीकार करते और बदले में समाज उन्हें क्षमा देता। मंडेला ने महावीर के दर्शन की आधुनिक राजनीतिक संभावना दिखा दी।

युद्ध सिर्फ सीमाएं नहीं बदलते, वे लोगों की यादों में बदले की ऐसी आग छोड़ जाते हैं, जो अगली पीढ़ियों तक जलती रहती है। क्षमा उस आग में घी को बुझाने का साहस है। हमारी सभ्यता ने दुनिया को अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और क्षमा जैसे विचार दिए हैं। इन्हें आज की दुनिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संवत्सरी का दीया मंदिर की देहरी तक सीमित क्यों रहे? यदि उसकी लौ व्यक्ति से समाज, समाज से राजनीति और राजनीति से कूटनीति तक पहुंचे तो क्षमावाणी केवल एक पर्व नहीं रहेगी, एक आचरण बनेगी।

अनुरोध ललित जैन

चिंताजनक है पैसिव स्मोकिंग का बढ़ता दायरा

अली खान

क्या आप जानते हैं कि बिना सिगरेट छुए भी आप उसके जानलेवा धुएं के शिकार हो रहे हैं? क्या आपके आस-पास किसी और द्वारा उड़ाया गया धुआं आपकी जिंदगी के कीमती साल कम कर रहा है? चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका 'द लैंसेट' के हालिया वैश्विक अध्ययन 'ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज 2023' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पैसिव स्मोकिंग यानी परोक्ष धूमपान (दूसरों के धुएं के संपर्क में आना) के कारण होने वाली मौतों की तादाद में 1990 की तुलना में साल 2023 में लगभग 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आंकड़े बताते हैं कि जहां 1990 में परोक्ष धूमपान से देश में 2,17,700 मौतें हुई थीं, वहीं 2023 में यह खौफनाक आंकड़ा बढ़कर 3,25,600 तक पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर स्थिति और भी भयावह है, जहां करीब 2.71 अरब लोग इस समस्या से घिरे हुए हैं, जिनमें 14 साल तक के 76.70 करोड़ मासूम बच्चे भी शामिल हैं।

> भारत में पैसिव स्मोकिंग यानी परोक्ष धूमपान के कारण होने वाली मौतों की तादाद में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई हैं

पैसिव स्मोकिंग का असर केवल फेफड़ों और सांस की बीमारियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के कई अंगों पर लंबे समय तक बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यह धुआं रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कोरोनरी धमनी रोग (हृदय रोग) और स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थितियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वयस्कों में यह फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, तो वहीं बच्चों में इसके परिणाम और भी संवेदनशील होते हैं।

बच्चों में यह अस्थमा के दौरे, श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण और कमजोर फेफड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस धुएं का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। कुछ देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के इसके संपर्क में आने की दर 1.8 गुना अधिक देखी गई है, जो सीधे तौर पर उनके घरेलू और सामाजिक परिवेश में सुरक्षा के अभाव को दर्शाता है।

इस अदृश्य और घातक महामारी से निजात पाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर एक मजबूत साझी रणनीति तैयार करनी होगी। सबसे पहले, सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान-निषेध के कानूनों को और अधिक सख्त बनाना होगा तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रविधान जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। सरकार को स्वास्थ्य विज्ञापनों के जरिये पैसिव स्मोकिंग के खतरों को प्राथमिक शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना चाहिए। केवल कानूनी बंदिशों से इस सामाजिक बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमें अपने घरों और निजी वाहनों को पूरी तरह से 'धूमपान मुक्त' क्षेत्र बनाना होगा, ताकि हमारे बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रह सकें।

(लेखक शिक्षक हैं)

मेलबाक्स

अराजकता से बचना आवश्यक

'स्वतंत्रता और अराजकता में अंतर करे न्यायपालिका' शीर्षक से प्रकाशित हरबंश दीक्षित का आलेख उस बहुसंख्यक जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जो समाज को व्यवस्थित एवं देश को प्रगतिशील देखना चाहती है। दुर्भाग्य से राजनीति का खेल उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बजाय लगातार कमजोर कर रहा है। बहुत ही दुखद है कि वर्तमान परिदृश्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अराजकता को स्थान दिया जा रहा है और अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच का भेद धुंधला होता जा रहा है। यह परिस्थिति सुशासन और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती है। जब अभिव्यक्ति की आड़ में हिंसा भड़काने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी की मानहानि करने को अधिकार मान लिया जाता है, तब वह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अराजकता बन जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने या बोलने का लाइसेंस कभी नहीं हो सकता। न्यायपालिका का यह रुख बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि विचारों का मतभेद स्वीकार्य है, लेकिन उस मतभेद की आड़ में कानून को हाथ में लेना या सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करना अपराध की श्रेणी में ही आएगा। एक सशक्त और समृद्ध भारत के लिए यह अनिवार्य है कि हम रचनात्मक आलोचना का स्वागत करें, लेकिन अराजकता पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएं। न्यायपालिका एवं सरकार द्वारा आपसी सहमति से इस रेखा को स्पष्ट रूप से खींचना ही सुशासन और आम जनता के साथ सशक्त भारत की संरचना को सुनिश्चित कर सकता है।

डा. राम श्रीवास्तव, हिसार

स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर

अशोक कुमार का आलेख ''चिंतित करने वाला फैसला'' आज की लोक व्यवस्था के संदर्भ में सटीक विश्लेषण है। संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार परम नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति या समूह की गतिविधियों से दूसरे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हों, लोक व्यवस्था बाधित हो अथवा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचे। किसी भी निर्णय का मूल्यांकन करते समय इन सभी पहलुओं को समग्र रूप से देखना आवश्यक है। जिलाधिकारी के रासुका के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई पर भी हाई कोर्ट के जज/ रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली सलाहकार बोर्ड की संस्थागत निगरानी का प्रविधान है। अगर किसी भी सक्षम कोर्ट को यह लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो वह जिलाधिकारी के निर्णय की जांच करा सकता है। अपील या रिट के दौरान मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाली टिप्पणियां लोकतंत्र में घातक हो सकती हैं, यह भी तब जब न्यायपालिका की गतिविधियों के संबंध में लोकधारणा कोई अच्छी नहीं हैं।

डा. राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जयपुर

हिंदी की लोकप्रियता

'सिनेमा ने हिंदी को बनाया जन की भाषा' शीर्षक आलेख में रागिनी नायक ने हिंदी की लोकप्रियता में सिनेमा के योगदान का सही चित्रण किया है। ये हिंदी सिनेमा ही है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से महाराष्ट्र, गुजरात तक हिंदी को लोकप्रिय और आमजन की भाषा बनाया है। हिंदी फिल्मों के गीत देश की सीमाओं को पार कर विदेशों मे भी अपार लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। राज कपूर की फिल्म आवारा के गीत आवारा हूं को सरहदों के पार बेहद प्यार मिला। 1988 में हिंदी का एक गैर फिल्मी गीत आया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और अपार प्रसिद्धि हासिल की। हिंदी भाषा अपने आंगन में ही पराई हो रही है से सहमत नहीं हुआ जा सकता। हिंदी आज भी देश के भाल पर बिंदी के समान शोभायमान है और सदैव रहेगी।

राजीव वार्ष्णेय, पुरानी पैंठ, चंदौसी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

50 हजार से भी अधिक अवैध पीजी का संचालन हो रहा है दिल्ली में, जिनमें पांच लाख से अधिक छात्र-पेशेवर रहते हैं। इन पीजी में प्रत्येक व्यक्ति का किराया प्रतिमाह औसतन 15-20 हजार रुपये तक है।

आजकल

मजबूरी व मुनाफे के बीच पीजी कारोबार

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हाल ही में एक पांच मंजिला मकान के ढहने से सात छात्रों व मजदूरों की जान चली गई, जबकि इससे कहीं अधिक छात्र घायल हुए। इस मकान में अवैध रूप से पीजी का संचालन किया जा रहा था और कमाई बढ़ाने के लिए बेसमेंट में भी निर्माण कार्य हो रहा था। इस मकान के ढहने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में पीजी से जुड़े तमाम चिंताजनक पहलू सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में संबंधित सरकारी एजेंसियों को गंभीरता से विचार करते हुए इसके समाधान की दिशा में निर्णय लेना होगा

मनु त्यागी
manu@nda.jagran.com

दिल्ली के सत्य निकेतन में ढहे मकान ने राजधानी में संचालित पीजी की दुर्दशा को सार्वजनिक कर दिया है। फाइल

लालच के मलबे में तब्दील होता हमारा समाज। इस वाक्य को पढ़कर आपको विचलित होना चाहिए कि आप और हम सभी इसी समाज का हिस्सा हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, मुनाफे की इसी अंधी दौड़ ने समाज के ही बड़े वर्ग को मौत के मुंह धकेल दिया है। सत्य निकेतन में पीजी हादसे में पांच छात्रों सहित सात की मौत हमारे सिस्टम के मुंह पर ही तमाचा है। वह बात अलग है कि हम उसे किस दृष्टि से देख पा रहे हैं, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि ऐसे हादसे भी सरकारी व्यवस्था, एजेंसियों को चेता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बार-बार इन घटनाओं के बाद सामाजिक शोर, सरकारी दिलासाएं, विभागों की कथित कार्रवाई के साथ फाइलें बंद हो जाती हैं।

लेकिन क्यों? और ऐसा कब तक? इस सवाल को समाज के प्रति जिसकी जिम्मेदारी है, जो सिर्फ वोट के आधार पर सत्तासीन हो जाते हैं, उनसे पूछना होगा। सत्य निकेतन के जिस इलाके में हादसा हुआ, वह देशभर से आने वाले उन छात्रों के भविष्य बनाने वाला 'आशियाना' है, जो अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने संजोकर देश की राजधानी में आते हैं। लेकिन यहां जिस तरह से घटना हुई, उसने सामूहिक चेतना को हिला दिया है। यह हादसा सिर्फ एक आपदा या तकनीकी चूक नहीं थी, बल्कि यह हमारे समाज के उस जर्जर सच की गवाही है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते आ रहे हैं।

अतिरिक्त कमाई : मुनाफे की अंधी दौड़ और इंसानी जान की कीमत इस हादसे का सबसे पहला और वीभत्स सच यह है कि मकान मालिकों और ठेकेदारों के लिए मासूमों की जिंदगी से ज्यादा प्यारी 'अतिरिक्त कमाई' बन चुकी है। जिस इमारत को केवल दो मंजिल बनाया जा सकता था, उस पर अवैध रूप से पांच मंजिलें खड़ी कर दी गईं। इतना ही नहीं, जर्जर हो चुकी इस पुरानी इमारत के बेसमेंट की दीवारों को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया, ताकि वहां नई दुकान या मुनाफा कमाने के और रास्ते बनाए जा सकें। सत्य निकेतन जैसे और भी ठिकाने हैं, दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी हैं। तंग गलियों की बहुमंजिला इमारतों में दड़बेनुमा कमरों में ठूसे गए छात्रों व युवाओं वाली इस व्यवस्था को पीजी का नाम दे दिया जाता है। लूट खसोट के इस मकड़जाल में छात्रों और युवाओं की मजबूरी की नींव पर खड़ा पीजी का यह कारोबार दिल्ली में ही 15 से 20 हजार करोड़ से अधिक का है। एनसीआर के शहरों को भी जोड़ लें तो यह 25 से 30 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाता है।

दिल्ली में 50 हजार से अधिक अवैध पीजी संचालित हो रहे हैं, जिनमें पांच लाख से अधिक बेड होंगे। प्रत्येक बेड का प्रति माह किराया 15-20 हजार रुपये तक है। यह स्थिति एनसीआर के शहरों के पीजी में भी है। गुरुग्राम में ये चार हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि ग्रेटर नोएडा में नालेज पार्क जैसी एक ही लोकेशन में ये कमाई महीने की एक हजार करोड़ तक पहुंच जाती है। इसमें राजनेताओं की मिलीभगत और अधिकारियों का संरक्षण जैसे आरोप भी कहीं न कहीं सच्चाई ही लिए होते हैं। यह विशुद्ध मुनाफे जैसा ही है, क्योंकि जब काम ही अवैध तरह से हो रहा है तो कमाई भी मुनाफे की ही हुई और मुनाफे की ब्लैक मनी पर भला सरकार को क्या टैक्स जा रहा होगा? लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि जब सरकार को इसका टैक्स नहीं जा रहा तो, बगैर हादसे हुए सरकार क्यों नहीं जागती है। ऐसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तो उसकी ही जिम्मेदारी है। यदि देश की राजधानी में सरकारी व्यवस्था की ऐसी दशा है तो अन्य राज्यों की स्थिति का अंदाजा अनायास ही हो जाता है। एक तरीके से पीजी के नाम पर पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों का शोषण हो रहा है। मजबूरी और मुनाफे के बीच बढ़ता ये अवैध कारोबार बड़े स्तर पर पांव पसार चुका है।

शिक्षा का घटता बजट : दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधन पर तो आरोप लग रहे हैं कि साल 2012 के बाद से यहां एक भी छात्रावास नहीं बना है। हां, अभी जब सवाल उठे तो मामूली राहत का बयान डीयू प्रबंधन की ओर से भी आ गया कि बहुत जल्द हास्टल की 5500 सीट बढ़ाई जाएंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी अपनी पुरानी इमारतों के द्वार छात्रों के हास्टलों के लिए खोलने की घोषणा कर रहा है। हालांकि ऐसी घोषणाओं का जमीनी जुड़ाव बहुत कम होता है, क्योंकि ये कागजों तक ही सीमित होती हैं। ऐसा नहीं है कि देश के पास संसाधनों की कमी है, बस शासन की प्राथमिकताओं में शिक्षा, शिक्षक और छात्र नहीं हैं। शिक्षा के बजट को लगातार घटाया जा रहा है। मांग होती रही है कि शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च होना चाहिए, परंतु केंद्रीय बजट का यह अब लगभग ढाई प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2013-14 में शिक्षा मद में कुल बजट की 4.6 प्रतिशत राशि आवंटित हुई थी, वह घटते-घटते 2026-27 में 2.6 प्रतिशत रह गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित कालेजों के लिए 2023-24 में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2025-26 में घटकर 325 करोड़ रह गए। इसी तरह, दिल्ली विश्वविद्यालय का भी बजट घटा दिया गया।

पीपीपी पर पीजी क्यों नहीं : इस समय आप देख लें, देश में अधिकांश व्यवस्था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल यानी पीपीपी पर जा रही हैं तो फिर पीजी क्यों नहीं? इसके लिए सब नियम तय क्यों नहीं हो सकते। सरकारी तंत्र और मुनाफाखोरों की मिलीभगत की आड़ में युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ भी बंद होगा और राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल सकेगा। पारदर्शिता का माडल स्थापित होगा। यह काम तो विश्वविद्यालय और राज्य अपने स्तर पर कर ही सकते हैं। कोई पहल तो करे, देश के लिए नजीर पेश हो सकती है। वे निजी छात्रावासों के मानक, मापदंड और किराये भी तय कर सकते हैं तथा निगरानी का अधिकार भी रख सकते हैं।

आज जब छात्र दड़बेनुमा कमरों में अस्वस्थ वातावरण में रहने को मजबूर हैं, तब उन्हें स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण कैसे मिलेगा? बहुत से पीजी में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होता है। अगर हम नई पीढ़ी को उचित वातावरण नहीं देंगे, तो कैसे देश के उज्ज्वल भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं? सरकार यदि शिक्षा पर ईमानदारी से ध्यान दे और देश भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में शिक्षा व सुविधाओं में सुधार करे, तो दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बाहर के छात्र आएंगे ही क्यों? यह केवल दिल्ली का सवाल नहीं है, हर जगह पीजी के नाम पर छात्रों का शोषण हो रहा है। आज जो छात्रावास व्यवस्था है, उस पर न विश्वविद्यालय और न ही सरकार का नियंत्रण है।

देशभर से जाने कितने युवा छात्र ऐसी जगहों पर आते हैं और खस्ताहाल ठिकानों पर जीते हैं। इससे हमें शर्म महसूस होनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि एक देश और समाज के रूप में हम क्या कर रहे हैं? हम अगली पीढ़ी को कैसी संस्कृति सौंप रहे हैं? क्या संदेश दे रहे हैं? क्या यही कि भारत में जिंदगी ऐसी ही होती है? अवसरों की इस कमी के इर्द-गिर्द एक पूरा बिजनेस-इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। जिस युवा शक्ति के बूते 2047 के विकसित भारत के सपने देखे जा रहे हैं, अब उसकी मजबूरी, हताशा किसी के लिए एक उद्योग बन गया है। अब आप इसे मानवीयता कहेंगे, समाज कहेंगे या मुनाफा कमाने वाले 'यमराज'। यह आप ही को तय करना है कि आपके भीतर से आपकी चेतना कब जागेगी। हालांकि हादसों से इतर एक स्याह पक्ष यह भी है कि यही युवा यहां से निकल कर अपना भविष्य बनाते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने दशकों से चले आ रहे इस पीजी माफिया साम्राज्य पर, भ्रष्टाचार के इस दलदल से मुक्ति पाने का प्रयास किया? इसे खत्म करने का संकल्प लिया? ऐसी नजीर का समाज इंतजार करता है, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे।

सरकारी एजेंसियों की व्यवस्था पर नियंत्रण

जनमानस में प्रायः यह तीखा सवाल पूछा जाता है कि जब आवासीय इलाकों में बिना पिलर के पांच-पांच मंजिला अवैध इमारतें खड़ी हो जाती हैं, कमर्शियल बेसमेंट में बिना वेंटिलेशन और फायर एनओसी के मौत के जाल बिछ जाते हैं या सार्वजनिक पार्कों की जमीनों पर रातों-रात दुकानें सज जाती हैं, तब म्युनिसिपल इंस्पेक्टर या जेई कहां होते हैं? क्या उन्हें अपनी आंखों के सामने आकार लेता यह कंक्रीट का अपराध दिखाई नहीं देता? इसी वर्ष दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के हुए पीजी हादसों और अब दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी वाले घटनाक्रम तक एक खुले भ्रष्टाचार की गवाही ही तो हैं। और इस अनदेखी का अपना एक बाकायदा 'सुव्यवस्थित अर्थशास्त्र' है।

दिल्ली-एनसीआर में भ्रष्टाचार का चरित्र अन्य शहरों से गुणात्मक और संरचनात्मक रूप से पूरी तरह भिन्न है। यहां का भ्रष्टाचार एक बहु-स्तरीय, संस्थागत तरीके से फलने-फूलने वाला एक ऐसा सिंडिकेट है, जहां कोई एक संस्था कभी भी संपूर्ण रूप से दोषी सिद्ध नहीं की जा सकती। और हर हादसे के बाद मौत का ठीकरा एक विभाग दूसरे पर मढ़कर सुरक्षित बच निकलता है। यह इस बात का अकाट्य साक्ष्य है कि जब तक हम इस बीमारी के मूल ढांचे और उसकी आर्थिक रीढ़ को नहीं तोड़ेंगे, ऊपरी तौर पर की गई सीलिंग या बुलडोजर की कार्रवाई केवल मवाद को त्वचा के नीचे दबाने जैसी अस्थायी, दिखावटी राहत जैसी दिखती रहेंगी और मासूम नागरिकों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। वैसे भी देश में कब से सिंगल विंडो सिस्टम, सरकारी एजेंसियों के एकीकरण की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की दिशा में हुंकार भरी जा रही है, लेकिन जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश को सबसे पहले सरकारी एजेंसियों की व्यवस्था पर नियंत्रण की जरूरत है, उस दिशा में सिर्फ सुझावों का ही दौर दशकों से चला आ रहा है।

(मनु त्यागी)

खरी-खरी

अंग्रेजी के नाथ और हिंदी अनाथ

सूर्यदीप कुशवाहा

चौदह सितंबर आते ही देश का वातावरण शुद्ध साहित्यिक हो जाता है। कार्यालयों में अलमारियों पर जमी धूल झाड़ी जाती है, हिंदी की मोटी-मोटी फाइलें बाहर निकलती हैं और नेता जी कुर्ता-पायजामा पहनकर मंच से दहाड़ते हैं कि हिंदी हमारी मां है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए! भाषण खत्म होता है, तालियां बजती हैं। नेता जी मंच से नीचे उतरते हैं और अपने सचिव के कान में फुसफुसाते हैं कि सुनो, जरा चेक करना कि मेरे बेटे का उस कानवेंट स्कूल में एडमिशन हुआ या नहीं? कहीं वो इस डाउनमार्केट हिंदी के चक्कर में पिछड़ न जाए।

बस, यही इस देश की कड़वी हकीकत है। हम एक ऐसे अद्भुत समाज में रह रहे हैं जहां अंग्रेजी नाथ यानी मालिक बनकर सिंहासन पर बैठी है और हिंदी अपनी ही चौखट पर अनाथ खड़ी अपनी पहचान की भीख मांग रही है। आज के दौर में अंग्रेजी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमानी का सर्टिफिकेट और ऊंचे सामाजिक स्तर यानी स्टेटस सिंबल का लाइसेंस बन चुकी है। यदि आप टूटी-फूटी अंग्रेजी में भी कोई बकवास बात कहें, तो लोग आपको बड़े ध्यान से सुनेंगे और कहेंगे कि वाओ, व्हाट एन इंटेलेक्चुअल पर्सन!

हमारी मानसिकता का दिवालियापन तो देखिए! आज की पीढ़ी को ए फार एप्पल तो याद है, लेकिन क से कबूतर बोलते ही उनकी जीभ लड़खड़ाने लगती है। माता-पिता अपने बच्चों की इस अज्ञानता पर शर्मिंदा होने के बजाय बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे हमारी पिंकी को तो हिंदी समझ ही नहीं आती! अपनी मातृभाषा न बोल पाना आज इंसल्ट नहीं, बल्कि प्राउड मोमेंट बन गया है।

समय आ गया है कि हम इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ें। अंग्रेजी को रोजगार और ज्ञान के माध्यम के रूप में जरूर सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा की बलि चढ़ाकर नहीं। जब तक हम स्वयं अपनी भाषा पर गर्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक दुनिया की कोई सरकार या कोई कानून हिंदी को उसका खोया हुआ सम्मान नहीं दिला सकता।

X पोस्ट

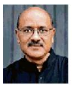

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की हर समीक्षा से पहले वही तमाशा। नई समीक्षा से पहले पाकिस्तान ने जैश सरगना मसूद अजहर को सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की सूची में डाला और उस पर इनाम की राशि बढ़ाई।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

पहले उन्होंने प्रेस किट को लेकर विवाद खड़ा किया, फिर नान-वेज भोजन न परोसने पर। अब नया विवाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उन स्नैक्स को खाने पर है, जो खाने के लिए ही रखे गए थे। अगर ब्रिक्स को लेकर सरकार पर निशाना साधने के लिए उनके पास बस यही बातें हैं, तो इससे पता चलता है कि यह सम्मलेन जबरदस्त सफल रहा है।

मोनिका वर्मा@TrulyMonica

राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिन आलीशान होटलों में ठहरे, वहां उन्हें मनपसंद का हर तरह का खाना उपलब्ध रहता है। देश के करोड़ों लोग शाकाहारी हैं। जो नहीं थे, वे भी सेहत के लिए शाकाहारी बन रहे।

आलोक मेहता@alokmehtaeditor

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या ब्रिक्स के माध्यम से भारत अपने हितों को आगे बढ़ाने में सफल रहा?

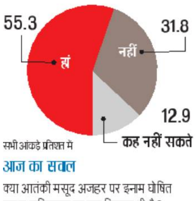

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या आतंकी मसूद अजहर पर इनाम घोषित करना पाकिस्तान का एक दिखावा ही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

मांसाहारी भोज हित उठे पेट में पीर,
हजम न होती 'बास' को बिल्कुल पूड़ी-खीर।
बिल्कुल पूड़ी-खीर चाहिए मुर्ग मुसल्लम,
बिरयानी में बीफ साथ में बकरे का दम!
रखते हैं वे खून चूसने की तैयारी,
पक्के 'दत्तात्रेय' मगर हैं मांसाहारी!!

-ओम प्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

मांसाहार की आंच पर उबली सियासत

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल की राजनीति में इन दिनों 'भोग' एक बार फिर बहस का केंद्र बन गया है। यह बहस केवल खानपान की नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, पहचान और राजनीतिक विमर्श के जटिल संगम की कहानी है। कालीघाट मंदिर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा मछली का भोग ग्रहण करने की घटना ने उस विवाद को नया आयाम दे दिया है, जिसकी शुरुआत बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर) के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने दुर्गापूजा के दौरान मांसाहार से परहेज की अपील की थी। इसके बाद से ही बंगाल में मांसाहार की आंच पर सियासत उबल रही है।

बंगाल की सांस्कृतिक संरचना को समझे बिना इस विवाद की तह तक पहुंचना संभव नहीं है। यहां धर्म और भोजन के बीच वह दूरी नहीं है, जो देश के कई अन्य हिस्सों में देखने को मिलती है। शाक्त परंपरा में देवी काली को मछली और पशुबलि अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है, और यही भोग बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कालीघाट जैसे मंदिरों में यह कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा का हिस्सा है। यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री ने कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कालीघाट मंदिर में पूजा के बाद मछली का भोग ग्रहण किया, तो इसे केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश के रूप में भी समझा गया। यह संदेश दो स्तरों पर काम करता है- एक ओर यह बंगाल की पारंपरिक आस्था के समर्थन का संकेत देता है, तो दूसरी ओर यह उस धारणा का प्रतिवाद करता है कि भाजपा उत्तर भारत की 'एकरूप' सांस्कृतिक दृष्टि को बंगाल पर थोपना चाहती है।

दरअसल, विवाद की जड़ में वह कथन है, जिसमें बागेश्वर बाबा ने बंगालियों को दुर्गापूजा के दौरान मांसाहार छोड़ने की सलाह दी थी और ऐसा न करने वालों को 'पाखंडी' तक कह दिया था। यह बयान बंगाल की सामूहिक चेतना में हस्तक्षेप जैसा प्रतीत हुआ। यहां दुर्गापूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें भोजन की विविधता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे में बाहरी 'आदेश' या 'नैतिक आग्रह' को सहज स्वीकार कर लेना बंगाली समाज के स्वभाव के विपरीत है। शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर जिस तरह संतुलन साधने की कोशिश की, वह राजनीतिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। एक ओर उन्होंने बागेश्वर बाबा के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों के खानपान का निर्णय करे। उनका यह कथन कि 'लोग अपने भोजन और धार्मिक आचरण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं' संविधानिक मूल्यों की पुनः पुष्टि करता है।

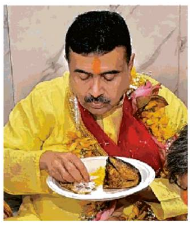

कालीघाट मंदिर में शुभेंदु अधिकारी। फाइल

यह संतुलन केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए, जिन्होंने विरोध के नाम पर उग्र प्रदर्शन किया और तस्वीरें जलाईं। यानी एक तरफ सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा, तो दूसरी ओर कानून-व्यवस्था पर सख्ती- यह दोहरी रणनीति वर्तमान शासन की कार्यशैली को भी दर्शाती है।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू भाजपा की राजनीतिक रणनीति है। पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह बंगाल की स्थानीय परंपराओं के साथ खड़ी है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कालीघाट में मछली भोग ग्रहण करने को 'बंगाल की आस्था और जीवनशैली के सम्मान' से जोड़ा। यह उस पुराने आरोप का जवाब भी है, जिसमें कहा जाता रहा है कि भाजपा 'एकरूप सांस्कृतिक एजेंडा' को बढ़ावा देती है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथोंहाथ लिया है। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वाम दलों ने इसे बंगाल की संस्कृति पर 'हमले' के रूप में पेश करने की कोशिश की।

दरअसल, यह केवल भोजन की बहस नहीं, बल्कि 'कौन बंगाल की असली पहचान का प्रतिनिधित्व करता है'- इस सवाल की लड़ाई है। बंगाल में भोजन का सवाल हमेशा से राजनीतिक रहा है। मछली यहां केवल आहार नहीं, बल्कि पहचान का प्रतीक है। यह नदी, जमीन और जीवनशैली से जुड़ा हुआ है। दुर्गापूजा में मांसाहारी भोग की परंपरा इसी सांस्कृतिक निरंतरता का हिस्सा है, जहां धर्म और दैनिक जीवन के बीच कोई कृत्रिम दीवार नहीं खड़ी की जाती। यही वजह है कि यहां शाकाहार बनाम मांसाहार की बहस अक्सर बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखी जाती है।

यह विवाद हमें यह याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। यहां एक ही धर्म के भीतर अनेक परंपराएं, मान्यताएं और आचार-व्यवहार मौजूद हैं। बंगाल का शाक्त परंपरा आधारित मांसाहारी भोग उसी विविधता का उदाहरण है। इसे स्वीकार करने में ही राजनीतिक परिपक्वता है। भोग की थाली से उठी यह बहस फिलहाल थमने के संकेत नहीं दे रही, लेकिन यह निश्चित है कि इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है- क्या राजनीति आस्था को निर्देशित करेगी, या आस्था राजनीति को संतुलित करना सिखाएगी?

मंथन

संवाद से ही संगठन की समझ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो कहा जाता है, उसे सुनना आवश्यक है, परंतु संघ के साथ काम करने वाले मुसलमानों को भी सुनना जरूरी है। इससे संघ को समझा जा सकता है

डा. शाहिद अख्तर
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग

अमेरिकी शहर न्यूयार्क के मेयर जोहरान ममदानी ने बीते दिनों आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बोलने का विरोध किया। ममदानी का कहना था कि आरएसएस के सोच में कुछ लोगों को बाहर रखने की भावना दिखाई देती है। उन्होंने इसे उस बहुलतावादी और पंथनिरपेक्ष भारत के सोच से अलग बताया, जिसे वे बचपन से मानते आए हैं।

हालांकि ममदानी की बात अपनी जगह है, लेकिन मैं इस विषय को एक अलग नजरिये से सामने रखना चाहता हूं- एक भारतीय मुस्लिम के रूप में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में और आरएसएस तथा मुस्लिम समाज के बीच लंबे समय से चल रहे संवाद में शामिल व्यक्ति के रूप में। मैं ममदानी पर हमला नहीं कर रहा हूं और न ही यह कह रहा हूं कि आरएसएस की आलोचना नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल केवल इतना है कि किसी संगठन के बारे में राय बनाने से पहले उस संगठन के साथ काम करने वाले लोगों का अनुभव भी सुना जाना चाहिए। किसी भी विचार या संगठन को समझने के लिए केवल उसके विरोधियों की बात सुनना पर्याप्त नहीं हो सकता।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एमआरएम की शुरुआत दिसंबर, 2002 में मुस्लिम बुद्धिजीवियों, सामाजिक प्रतिनिधियों और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत से हुई थी। इसका मकसद सीधा था- मुसलमान और आरएसएस एक-दूसरे के बारे में दूसरों से सुनने के बजाय सीधे आपस में बात करें, गलतफहमियों को बातचीत के जरिये दूर किया जाए और एक-दूसरे को समझने की कोशिश की जाए। इसके बाद दो दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान मुस्लिम शिक्षक, धार्मिक विद्वान, महिलाएं, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता इस संवाद से जुड़े और इसे आगे बढ़ाते रहे। यह कोई एक दिन या एक कार्यक्रम की कहानी नहीं है। यह वर्षों से चल रही बातचीत और सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया है।

मेरे लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े मुसलमान अपनी पहचान छोड़कर नहीं आते। वे अपने मत, अपने विश्वास और अपने विचारों के साथ इस संवाद में हिस्सा लेते हैं। मेरे इतने वर्षों के अनुभव में मुझसे कभी यह नहीं कहा गया कि मैं इस्लाम छोड़ दूं या अपनी धार्मिक पहचान को कम करूं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि आरएसएस की सभी आलोचनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए।

यह बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में किसी भी संगठन से सवाल पूछना गलत नहीं है। आलोचना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक है कि आरएसएस के साथ सीधे काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी सुना जाए।

वस्तुतः भारत की पहचान उसकी विविधता में है। यदि अलग-अलग विश्वास और विचार रखने वाले लोग एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, तो यही लोकतंत्र और भारतीय समाज की वास्तविक ताकत है। मेरा आग्रह यह नहीं है कि लोग आरएसएस की जांच-पड़ताल बंद कर दें। मेरा आग्रह केवल इतना है कि जांच और चर्चा में उन मुसलमानों की आवाज भी शामिल हो, जिन्होंने आरएसएस के साथ सीधे काम किया है। आखिर यह जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा कि आरएसएस मुसलमानों के साथ व्यवहार में कैसा संवाद करता है? उन लोगों से पूछना भी जरूरी होगा जिन्होंने यह अनुभव स्वयं किया है।

हो सकता है कुछ लोग मेरी बात को इसलिए खारिज कर दें, क्योंकि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हूं। लेकिन मैं इसे कमजोरी नहीं मानता। मैं जिस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, उसमें मेरी सीधी भागीदारी ही मेरे अनुभव को समझने का आधार देती है। भारतीय मुसलमानों को किसी एक राजनीतिक समूह के रूप में देखना सही नहीं है। देश के मुसलमानों का सोच, राजनीति और सामाजिक नजरिया अलग-अलग हो सकता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी पूरे भारतीय मुस्लिम समाज की ओर से बोलने का दावा नहीं करता। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े मुसलमानों का एक अनुभव जरूर है कि उन्होंने आरएसएस के साथ बैठकर बात की है, सामाजिक काम किए हैं और असहमति के बावजूद संवाद जारी रखा है। इसलिए किसी मुस्लिम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सकारात्मक अनुभव होना कोई विरोधाभास नहीं है। यह भी भारत की विविधता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

जोहरान ममदानी से मैं सम्मानपूर्वक आग्रह करता हूं कि वह भारत आएं और इस संवाद को स्वयं देखें। उन मुस्लिम शिक्षकों, धार्मिक विद्वानों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलें, जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। भारत की खूबसूरती ही यही है कि यहां मतभेदों के बावजूद साथ रहने की गुंजाइश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो कहा जाता है, उसे सुनना जरूरी है। लेकिन आरएसएस के साथ काम करने वाले मुसलमानों को भी सुनना उतना ही जरूरी है। किसी संगठन की पूरी तस्वीर केवल उसके आलोचकों से बात करके नहीं मिल सकती, बल्कि उस संगठन के साथ काम करने वालों के अनुभव भी उस तस्वीर का हिस्सा होते हैं।

पिछले दिनों अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत। फाइल

(लेखक के विचार निजी हैं)

2020 से अब तक 147 कोयला खदानों की नीलामी

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 2020 से अब तक 147 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। सरकार के अनुसार, कोयला क्षेत्र में मजबूत सुधारों के चलते अब तक इस दौरान 44 नई कंपनियों ने नीलामी जीती है। यह खदानें नौ राज्यों में स्थित हैं जिनसे करीब 47,00 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व, 55 हजार करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश और 4.9 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। (आइएएनएस)

एआइ लेनदेन को अधिक व्यक्तिगत और सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से भुगतान में सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन का महत्व कम नहीं होगा।
- विकास बंसल, सीईओ, एमेजोन पे इंडिया

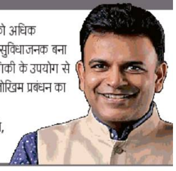

एक नजर में

ओमनिया होल्डिंग्स को खरीदेगी सोलर इंडस्ट्रीज

नई दिल्ली: सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका की ओमनिया होल्डिंग्स लिमिटेड को लगभग 13,000 करोड़ रुपये में खरीदेगी। ओमनिया होल्डिंग्स एक विविधीकृत वैश्विक समूह है, जो खनन, कृषि और रसायन क्षेत्रों में कार्यरत है। इस अधिग्रहण को लेकर दोनों कंपनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह पूरा सौदा नकद लेनदेन पर आधारित है। सोलर समूह के प्रबंध निदेशक मनीष नुवाल ने 2027 के मध्य तक सौदा पूरा हो जाएगा। (प्रेट्र)

2030 तक आठ गीगावाट होगी डाटा सेंटर क्षमता

नई दिल्ली: वर्ष 2030 तक भारत की स्थापित डाटा सेंटर क्षमता आठ गीगावाट तक पहुंच सकती है जो अगस्त 2026 तक 1.57 गीगावाट है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, अभी डाटा सेंटर क्षेत्र में करीब 70 अरब डालर के चल रहे निवेश और 90 अरब डालर की परियोजानाएं घोषित की जा चुकी हैं। भारत का डाटा सेंटर सफर ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के साथ विकसित हुआ है। नागरिकों की आनलाइन सेवाओं की बढ़ती अपेक्षाएं डाटा सेंटर की मांग को बढ़ा रही हैं। (आइएएनएस)

500 रुपये घटा सोने का मूल्य, चांदी स्थिर रही

नई दिल्ली: वैश्विक बाजार में बिकवाली बढ़ने से सोमवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में इसके मूल्य में 500 रुपये की गिरावट आई है और अब इसका मूल्य घटकर 1,55,400 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डालर में तेज बढ़ोतरी से वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही है। (प्रेट्र)

खाद्य पदार्थों के मूल्य में तेजी से खुदरा महंगाई बढ़ी

पिछले महीने 4.82 प्रतिशत रही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर

- आधार वर्ष 2024 वाली नई सीरीज लागू होने के बाद से सबसे अधिक महंगाई
- ग्रामीण इलाके में 5.23 तो शहर में 4.31 प्रतिशत की महंगाई दर दर्ज की गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के चलते अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई 4.45 प्रतिशत थी। आधार वर्ष 2024 वाली नई सीरीज जनवरी से लागू होने के बाद से अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति सबसे अधिक है। सरकार ने दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ आरबीआइ को खुदरा महंगाई चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है।

अगस्त में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 5.95 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। जुलाई में यह दर 5.52 प्रतिशत थी। अगस्त में गांवों में शहरों से अधिक महंगाई देखी गई। ग्रामीण इलाके में 5.23 तो शहर में 4.31 प्रतिशत की महंगाई दर दर्ज की गई। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर सबसे अधिक महाराष्ट्र में 8.10 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 8.07 प्रतिशत, तमिलनाडु में 7.96 प्रतिशत, कर्नाटक में 7.58 प्रतिशत तो तेलंगाना में 7.33 प्रतिशत दर्ज की गई।

खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी जारी रहने से आरबीआइ की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी की चर्चा चल पड़ी है। कच्चे तेल के दाम 105 डालर होने से सितंबर माह में भी खुदरा महंगाई दर में राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अगर अगले दो महीनों तक यह सिलसिला जारी रहा तो दिसंबर में केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में अदरक के खुदरा भाव में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 74 प्रतिशत, प्याज में 48 प्रतिशत तो लहसुन में 44 प्रतिशत का इजाफा रहा। हालांकि आलू के खुदरा दाम में इस अवधि में 13.14 प्रतिशत, टमाटर में 31 प्रतिशत, भिंडी में 5.5 प्रतिशत तो परवल में 3.60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में बढ़ोतरी चिंता विषय है, क्योंकि घरों की खपत में खाद्य पदार्थों की मजबूत हिस्सेदारी होती है, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाके के परिवार का अधिक खर्च खाने-पीने पर ही होता है। ऐसे में इस मद में खर्च बढ़ने पर अन्य सेक्टर के लिए उनकी खरीदारी क्षमता प्रभावित होगी।
-मनोरंजन शर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, इंफार्मेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग लिमिटेड

राज्यवार महंगाई (% में)	
बिहार	4.22
हरियाणा	3.92
हिमाचल प्रदेश	3.85
उत्तर प्रदेश	5.09
पंजाब	4.45
दिल्ली	2.61
मध्य प्रदेश	5.51
तेलंगाना	6.27

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अगस्त में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 9.92 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र: खाद्य उत्पादों, ईंधन और मैन्यूफैक्चरिंग वस्तुओं के दाम बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 9.92 प्रतिशत पर पहुंच गई। जुलाई में यह 9.78 प्रतिशत के स्तर पर थी। अगस्त की मुद्रास्फीति दर 2022-23 को आधार वर्ष मानकर तैयार नई थोक मूल्य सूचकांक सीरीज में दूसरी सबसे अधिक है। अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.05 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.65 प्रतिशत थी। मैन्यूफैक्चरिंग वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 8.37 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई, जो जुलाई में 8.29 प्रतिशत थी। ईंधन और बिजली में थोक मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 22.93 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 20.05 प्रतिशत थी। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में फिर बढ़े तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हाल की तेजी थोक महंगाई पर दबाव बनाए रखेगी।

इस सप्ताह एनएसई समेत पांच कंपनियां लाएंगी अपना आइपीओ

24,335 करोड़ रुपये जुटाएंगी यह कंपनियां शेयर बेचकर

22,568 करोड़ रुपये जुटाएगा एनएसई शेयर बिक्री से

प्राथमिक बाजार यानी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) गतिविधियों में इस सप्ताह भी तेज हलचल रहेगी। सप्ताह के दौरान कुल पांच कंपनियां अपना आइपीओ लेकर आएंगी। इसमें नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई), हीरो मोटर्स लिमिटेड, एसएस रिटेल लिमिटेड, जिंदल सुप्रीम इंडिया लिमिटेड और सोनासेलेक्शन इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। आइपीओ के जरिये शेयर बेचकर यह कंपनियां 24,335 करोड़ रुपये जुटाएंगी। आइए जानते हैं इन आइपीओ से जुड़ी प्रमुख बातें...

आइपीओ का आकार (करोड़ रुपये)	आवेदन तिथि	न्यूनतम निवेश	शेयर आवंटन	शेयर सूचीबद्ध होने की तिथि
हीरो मोटर्स लिमिटेड				
1,000	16-18 सितंबर	14,062	21 सितंबर	23 सितंबर
एसएस रिटेल				
500	16-18 सितंबर	14,105	21 सितंबर	23 सितंबर
जिंदल सुप्रीम इंडिया				
124.88	16-18 सितंबर	14,168	21 सितंबर	23 सितंबर
नेशनल स्टाक एक्सचेंज				
22,568.94	17-21 सितंबर	13,600	22 सितंबर	24 सितंबर
सोनासेलेक्शन इंडिया				
141.57	17-21 सितंबर	14,100	22 सितंबर	24 सितंबर

(नोट: शेयर आवंटन और सूचीबद्ध होने की तिथि में बदलाव संभव है।)

तीन एसएमई आइपीओ भी खुलेंगे

इस सप्ताह स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एसएमई) प्लेटफार्म से जुड़े तीन आइपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इसमें वामा वूवनफैब लिमिटेड, क्वांटो एग्रोवर्ल्ड लिमिटेड और शक्ति पालीट्रैप लिमिटेड का आइपीओ शामिल हैं। आइपीओ में तीन कंपनियां शेयर बेचकर 107.96 करोड़ रुपये जुटाएंगी।

जागरण इन्फो

मोबाइल पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत की जाए : आइसीईए

नई दिल्ली, प्रेट्र: मोबाइल एंड इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के सबसे बड़े संगठन ने सरकार से मोबाइल फोन पर जीएसटी को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग की है। मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के चलते घरेलू मांग में कमी के बीच यह मांग की गई है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन (आइसीईए) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दो सितंबर को लिखे पत्र में कहा कि भारत अब आकार के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और मोबाइल फोन वित्त वर्ष 2025-26 में देश का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है। मोबाइल फोन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संगठन ने कहा कि घरेलू मांग मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। हैंडसेट की खपत कम हुई है और फोन बदलने की अवधि ज्यादा हो गई। इसके साथ किफायती स्मार्टफोन सेगमेंट दबाव में है। आइसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने पत्र में कहा कि यह असंतुलन मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि के अगले चरण को सीमित कर देगा। इसलिए आइसीईए सरकार से मोबाइल फोन पर जीएसटी को 18% से घटाकर पांच प्रतिशत करने और मोबाइल-फोन कलपुर्जों के लिए संबंधित दरों को तर्कसंगत बनाने को कहा है।

मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों के चलते घरेलू मांग में गिरावट के बीच उद्योग जगत ने सरकार को पत्र लिखकर लगाई गुहार

भारत-कनाडा के बीच चौथे दौर की व्यापार समझौता वार्ता शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत और कनाडा ने सोमवार को यहां प्रस्तावित कांप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत के चौथे दौर की शुरुआत की। दोनों देश इस साल बातचीत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पांच दिन (14-18 सितंबर) तक चलने वाली इस बातचीत में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, उनमें सामान और सेवाओं का व्यापार, 'रूल्स आफ ओरिजिन' (जहां पर उत्पाद का निर्माण हुआ) और तकनीकी व्यापार बाधाएं शामिल हैं। इससे पहले तीसरा दौर की वार्ता ओटावा में हुई थी।

वहीं, मर्कोसर और भारत ने भी सोमवार को मौजूदा व्यापार समझौते का दायरा बढ़ाने के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। मर्कोसर लैटिन अमेरिका में एक व्यापारिक ब्लाक है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे और पैराग्वे शामिल हैं।

एआइ एक अवसर, पर मानवीय निगरानी जरूरी : ट्राई चेयरमैन

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के प्रबंधन एवं खतरों का पता लगाने के तरीके को एआइ बदल सकती है, लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ सुरक्षा उपाय और मानवीय निगरानी जरूरी है।

अनिल कुमार लाहोटी

उद्योग संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआइ) के एक कार्यक्रम में ट्राई प्रमुख ने कहा कि संचार नेटवर्क में एआइ का प्रयोग बढ़ रहा है, ऐसे में दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कंपनियों को जिम्मेदार एआइ में निवेश करने, जोखिम का आकलन करने, फैसलों का रिकार्ड रखने और इस्तेमाल से पहले माडलों का निरीक्षण करने की जरूरत है। ट्राई चेयरमैन ने कहा कि नेटवर्क के लगातार अधिक स्वायत्त होते जाने के बावजूद मानवीय निगरानी, आडिट की क्षमता और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने की क्षमता महत्वपूर्ण बनी रहेगी। एआइ का जिम्मेदार इस्तेमाल हो, नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए और प्रौद्योगिकी के जरिये हर नागरिक को सशक्त बनाया जाए।

वोडाफोन के खिलाफ शिकायतों की करेंगे जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर आने के लिए वोडाफोन आइडिया पर कथित तौर पर प्रोत्साहित करने के आरोपों के बीच ट्राई चेयरमैन लाहोटी ने कहा है कि वह इस बारे में दूरसंचार कंपनियों (जियो और एयरटेल) से मिलीं शिकायतों की जांच करेंगे।

राष्ट्रीय फलक

'बीमार कैदियों की जमानत नकारने से पहले 'न्याय की रीढ़' दिखाएं जज'

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- पांच साल से जेल में बंद बुजुर्ग आरोपित को अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार कैदियों की जमानत याचिकाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत खारिज करने से पहले संबंधित न्यायाधीश में 'न्याय करने की रीढ़' होनी चाहिए। न्यायालय को बुजुर्ग अवस्था और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर सहानुभूति और चिंता के साथ विचार करना चाहिए और जमानत न देने के कारण स्पष्ट रूप से आदेश में में दर्ज करने चाहिए।

जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस हरमीत सिंह देओल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी धन शोधन मामले में पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद 76 वर्षीय आरोपित देव को अंतरिम जमानत देते हुए की। उसके खिलाफ ईडी ने फतेहगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। आरोपित की ओर से बताया गया कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वह निजी जरूरतों तक की देखभाल करने में असमर्थ है। खंडपीठ ने कहा कि अस्वस्थ वृद्धावस्था अपने आप में एक अभिशाप है। ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इन्कार करना अमानवीय हो सकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बार-बार अपराध करने वाले या अत्यंत जघन्य अपराध के आरोपितों के मामले अलग हो सकते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके बीमार और कमजोर बुजुर्ग बंदी के मामले में जेल में रखने का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

खराब खाने पर एएमयू की छात्राओं का हंगामा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

खराब खाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की छात्राओं ने सात घंटे तक जमकर हंगामा किया। सोमवार को वीमेंस कालेज के अब्दुल्ला हाल की छात्राओं ने कालेज के दोनों मुख्य गेट बंद कर धरना दिया और प्रदर्शन किया। कक्षा चार से 10वीं तक की परीक्षा देने पहुंचीं छात्राओं को रोकने पर विवाद और बढ़ गया। प्राक्टर टीम व छात्राओं में धक्कामुक्की भी हुई। इस दौरान डिप्टी प्राक्टर गिर गए। छात्राओं ने प्राक्टर टीम पर धक्का मारने का आरोप लगाया है। शाम को छात्राओं ने कुलपति प्रो. नईमा खातून से मुलाकात की।

छात्राओं के साथ धक्कामुक्की के विरोध में एएमयू में छात्रों ने देर शाम को मार्च निकाला। छात्राओं का आरोप था कि खाने की गुणवत्ता को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। समस्या का समाधान न होने पर वह धरना देने को मजबूर हुईं। सुबह सात बजे छात्राओं ने प्रदर्शन व धरना शुरू किया। दोनों गेट पर ताला लगा देने से कोई न बाहर निकल सका और न अंदर जा सका। सबसे ज्यादा परेशानी परीक्षा देने पहुंची छात्राओं को हुई। प्राक्टोरियल टीम ने छात्राओं को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। प्राक्टोरियल टीम किसी तरह ताला खुलवाने में सफल हुई, मगर छात्राओं ने परीक्षा देने पहुंची स्कूली छात्राओं को रोक दिया, जिससे वह रो पड़ीं। इस बीच धक्कामुक्की भी हुई। डिप्टी प्राक्टर डा. नैयर की कमर में किसी छात्रा द्वारा नुकीली वस्तु चुभने की बात सामने आई। इससे वह दर्द से जमीन पर गिर पड़े।

प्राक्टर प्रो. नवेद खान के अनुसार कुलपति ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1,400 रुपये प्रतिमाह में छात्राओं को नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यानी करीब 46 रुपये में तीनों वक्त का खाना दिया जा रहा है। छात्राएं डाइनिंग फीस बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

एएमयू के वीमेंस कालेज में प्रदर्शन करतीं छात्राएं। जागरण

चीनी की खुदरा कीमत चौथे दिन औसत 60 रुपये प्रति किग्रा से कम

- त्योहारों से जुड़ी मांग के कारण कुछ क्षेत्रों में बना है कीमतों पर बढ़ने का दबाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार के कई उपायों के बाद सोमवार को देशभर में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम रही। हालांकि, त्योहारों से जुड़ी मांग के कारण कुछ क्षेत्रों में कीमतों पर बढ़ने का दबाव बना हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीनी की औसत खुदरा कीमत सोमवार को 59.57 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो एक दिन पहले 58.99 रुपये प्रति किलोग्राम थी। शुक्रवार को चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे आ गई थी और पिछले तीन दिनों में इसमें और नरमी आई है। औसत खुदरा कीमत अब भी 58.23 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है। 21 अगस्त को यह कीमत इतनी थी, जब केंद्र ने पहली बार चीनी के आयात की अनुमति दी थी और मिठास देने वाली इस वस्तु की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अन्य कदम उठाए थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को अधिकतम खुदरा कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही, जबकि न्यूनतम कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में खुदरा कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि तमिलनाडु और केरल में मामूली गिरावट दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में औसत खुदरा कीमत सोमवार को बढ़कर 55.56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई जो 21 अगस्त को 49.58 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

प्रतीकात्मक

बदलना होगा पर्यटन माडल और सीमा पार सहयोग

प्रथम पृष्ठ से आगे

आइसीआइएमओडी के महानिदेशक पेमा ग्यात्सो का मानना है कि खतरे सीमाओं को नहीं मानते और कोई भी देश अकेले इस संकट से नहीं निपट सकता। रिपोर्ट में 10 प्राथमिकता वाले बदलाव सुझाए गए हैं, जिसमें ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ग्लेशियरों की निगरानी बढ़ाना और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में साल भर आने वाले करीब 40 करोड़ पर्यटकों के कारण पर्यटन के माडल को भी बदलना होगा, ताकि अधिकतम संख्या के बजाय स्थानीय स्तर पर मूल्य सृजन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा सके। यदि इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और आजीविका दोनों दांव पर लग जाएंगे।

5600 करोड़ रुपये की ठगी में मनी लांड्रिंग, आइटीसी चोरी और हवाला नेटवर्क पर निगाह

जागरण संवाददाता, कानपुर

कानपुर और उन्नाव में फर्जी स्लाटर व स्क्रैप कारोबार के नाम पर पंजीकृत 77 कंपनियों के जरिये हुए 5,600 करोड़ रुपये के साइबर फर्जीवाड़े में पुलिस अब मनी लांड्रिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) चोरी और हवाला नेटवर्क की जांच कर रही है। शुरुआती सत्यापन में पुलिस को कई कंपनियों के दिए गए पते गलत मिले हैं, जिससे इनके फर्जी होने की पुष्टि हो रही है। पुलिस का मानना है कि पकड़े गए सरगना शाहजेब, सलमान और इखलाख समेत 14 आरोपित सिर्फ मोहरा हैं और उनके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें कुछ वकीलों के शामिल होने की भी आशंका है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को 17 ऐसे बैंक खाते मिले हैं जिनमें 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन हुआ है। ये खाते आइसीआइसीआइ, एचडीएफसी, एसबीआइ और बैंक आफ बड़ौदा समेत 14 प्रमुख बैंकों में खोले गए थे। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के एसीपी नीरज चौधरी ने बताया कि ठग अक्सर गरीब लोगों के नाम या चोरी के पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर ऐसी फर्जी कंपनियां बनाते हैं, जिनका जमीन पर कोई व्यापार नहीं होता। लोगों से ठगी गई रकम सीधे इन बोगस कंपनियों के खातों में जमा कराई जाती है और फिर जांच से बचने के लिए इसे कई अन्य खातों, क्रिप्टोकरेंसी या हवाला के जरिये विदेश में मुख्य आरोपितों तक पहुंचा दिया जाता है। कानून में आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए काले धन को सफेद करना मनी लांड्रिंग कहा जाता है। चूंकि साइबर ठगी में संगठित रूप से फर्जी फर्मों का उपयोग होता है, इसलिए इसमें मनी लांड्रिंग व संगठित अपराध की धाराएं लगाई जाती हैं।

पहचान बदल कर 30 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाला गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : गुजरात से 56 साल के एक ठग को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए विग पहनी और तीन अलग-अलग नामों का इस्तेमाल किया। उसने शेयर बाजार घोटाले के जरिये निवेशकों से 30 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारी ने बताया कि आरोपित रोशन भूषण सेठ ने इस धोखाधड़ी से मिले पैसों से आलीशान फ्लैट, महंगी कारें और महंगी घड़ियां खरीदीं और शानदार जिंदगी जी। उसने महाराष्ट्र और गुजरात में 42 लोगों को निवेश पर हर महीने पांच प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर ठगा। एक अधिकारी के अनुसार, ईओडब्ल्यू ने सेठ को जुलाई में गुजरात के वलसाड की एक रिहायशी इमारत से गिरफ्तार किया।

पिछले वर्ष की थी स्वतंत्र जांच की मांग

प्रथम पृष्ठ से आगे

सतीश सालियान ने वर्ष 2025 में बांबे हाई कोर्ट का रुख कर मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। उन्होंने याचिका में आदित्य ठाकरे समेत कुछ प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने और सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी। बता दें कि इस मामले में शुरुआत से ही आदित्य ठाकरे की ओर अगुलियां उठती रही हैं। आदित्य ठाकरे पहले ही इन आरोपों को खारिज करके याचिका को झूठा, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। इसलिए अब सीबीआइ की जांच में सामने आने वाले साक्ष्य ही आगे की दिशा तय करेंगे।

हाई कोर्ट बोला, पुलिस जांच ने सवाल अधिक खड़े किए : सतीश सालियान की याचिका पर हाई कोर्ट ने दो सितंबर, 2026 को मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि करीब छह वर्ष तक चली पुलिस जांच ने सवालों के जवाब देने के बजाय और अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने लंबे समय तक किसी मामले की जांच बिना किसी ठोस निष्कर्ष के नहीं खिंचनी चाहिए। अदालत ने पुलिस की उस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया, जिसमें संज्ञेय अपराध की एफआइआर दर्ज किए बिना जांच की गई। हाई कोर्ट ने इसे अपर्याप्त व असंतोषजनक बताया और सभी संबंधित दस्तावेज व सामग्री सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया था।

जांच के कई बिंदुओं पर उठाए थे सवाल : हाई कोर्ट के सामने पुलिस जांच से जुड़े कई बिंदु आए, जिन पर अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा। रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल का पंचनामा काफी देर से किए जाने को लेकर भी सवाल उठे। अदालत ने यह भी गौर किया कि गवाहों के रक्त निकलने की बात कहने के बावजूद घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी बरामद होने का उल्लेख नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छह बाहरी चोटों के साथ खोपड़ी में फ्रैक्चर व पसलियों में कई फ्रैक्चर दर्ज होने की बात सामने आई। अदालत ने चोटों और कथित ऊंचाई से गिरने की परिस्थितियों के बीच भी सवाल उठाए थे।

वाराणसी में पायलट ने फिर विमान उड़ाने से किया इन्कार, यात्रियों का हंगामा

जासं, वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सप्ताह में दूसरी बार इंडिगो पायलट ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर सोमवार को विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया।

इससे वाराणसी से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान करीब सवा पांच घंटे प्रभावित रही। बेंगलुरु से सुबह 11:30 बजे 143 यात्रियों को लेकर इंडिगो का विमान (6ई 6558) वाराणसी पहुंचा था। इसी विमान को उड़ान संख्या 6ई 6559 बनकर सुबह 11:55 बजे 178 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु रवाना होना था। यात्री विमान में बैठ गए थे। तभी पायलट ने कान में दर्द और तबीयत खराब होने की बात कहते हुए उड़ान भरने से मना कर दिया। पता चलने पर यात्रियों ने हंगामा किया। दिल्ली से दूसरा पायलट आने पर विमान शाम 5:18 बजे सभी यात्रियों को लेकर बेंगलुरु रवाना हुआ। बीते गुरुवार को भी मुंबई से वाराणसी पहुंचे इंडिगो पायलट ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया था।

प्रेरणा

सामान्य लोग समय काटने की सोचते हैं। महान लोग इसका उपयोग करने पर एकाग्र रहते हैं। - ब्रूस ली

संपादकीय

ब्रिक्स के समूह में चीन को और उदार होने की जरूरत है

नई दिल्ली में दो-दिवसीय ब्रिक्स सम्पन्न हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा कि मिनरल्स और टेक भू-राजनीतिक औजार बनें तो दुनिया का विकास रुकेगा। इशारा चीन की ओर था। वैश्विक समस्याओं पर कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट जारी रखते हुए संयुक्त घोषणा-पत्र जारी हुआ। सभी नेताओं ने ब्रिक्स की महत्ता बताने के लिए पीपीपी आधार पर ग्लोबल जीडीपी में इस ब्लॉक का हिस्सा 40% बताया। हालांकि सही होता अगर नॉमिनल के आधार पर बताया जाता, जो 28% है। इसमें से भी अगर चीन को हटा दिया जाए तो यह मात्र 8% रह जाएगा। एक संगठन तब मजबूत होता है, जब सदस्य देश एक-दूसरे को मदद देकर आगे बढ़ाएं। क्या यह चीन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह भारतीय निर्यात के द्वार खोले, ताकि बढ़ता ट्रेड-असंतुलन कम हो सके? ट्रम्प से पहले का अमेरिका क्या वर्षों तक इस भूमिका में नहीं रहा है? क्या चीन के द्वारा ब्रिक्स सदस्यों को अपने टेक-उत्पाद की जगह टेक-कौशल बगैर किसी सौदे के देना समीचीन नहीं होता? अगर चीन से सटी उत्तरी-पूर्वी सीमा पर भारत जैसे निम्न आय वर्ग के देश को रक्षा पर अरबों रुपये सालाना खर्च करना पड़ें तो ब्रिक्स के साझा घोषणा-पत्र तो निष्प्राण ही रहेंगे। चीन, भारत के पक्ष में ट्रेड को और आगे बढ़ाए, यही ब्रिक्स की दीर्घकालिक सफलता का पैमाना रहेगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

अपने व्यक्तित्व को निखारने की कला का नाम ही विवेक है

अगर विवेक जाग जाए तो किसी की भी वाणी सुखदायक, गंभीर और कोमल वचन वाली हो जाएगी। काकभुशुंडि जी ने राम जी की वाणी के लिए कहा था- सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास। मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमानिवास राम सुखदायक, गंभीर और कोमल वचन बोले। राम कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते, बहुत अर्थपूर्ण बोलते थे। उनकी वाणी की यह तीन विशेषताएं थीं, क्योंकि उनका विवेक जागा हुआ था। संयोग से गणेशोत्सव आरम्भ हो चुके हैं। सरस्वती बुद्धि की देवी हैं और गणेश जी विवेक के देवता हैं। हम अपने भीतर विवेक जगाने के लिए कुछ सरल प्रयास कर सकते हैं। जैसे अपनी कमजोरियों को दूसरों को बताने में पूरी ईमानदारी बरतें और अपनी कमजोरियों को संवारने में, ठीक करने में खूब परिश्रम करें। जितना लोगों से ओपन फीडबैक हम अपने लिए लेते रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारने में उतनी सुविधा ही होगी और इसी को विवेक कहते हैं।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • यूपी और पंजाब पर विशेष नजरें जमी हैं

आगामी चुनावों में हर राज्य में एक-दूसरे से भिन्न समीकरण हैं

सियासत

नीरजा चौधरी

वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार

neerja_chowdhury@yahoo.com

दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के सम्मिलित होने को असल में अगले साल यूपी, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर और गोवा में होने जा रहे चुनावों का 'कर्टेन रेजर' माना जा सकता है। प्रधानमंत्री यूं तो देश की राजधानी में एक छात्र-समूह को संबोधित कर रहे थे, लेकिन यह चुनावों में युवाओं, जेन-जी और यहां तक कि जेन-अल्फा की अहमियत को भी मान्यता देने जैसा था। मोदी भलीभांति समझते हैं कि देश की चुनावी राजनीति में इन युवाओं ने क्या अहमियत हासिल कर ली है। आज कोई पार्टी इन्हें नजरअंदाज करने का जोखिम उठा नहीं सकती। यही वजह है कि राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एसआरसीसी के आयोजन में गए।

चुनावी राज्य बड़ा हो या छोटा, लोकसभा चुनावों पर उसके प्रभाव के चलते सत्ताधारी दल और विपक्ष, दोनों के लिए उसका महत्व है। आगामी चुनावों में भाजपा के लिए अपेक्षाकृत बहुत कुछ दांव पर लगा है। बंगाल की जीत ने भाजपा के पक्ष में खूब माहौल बनाया था, लेकिन जेन-जी के प्रदर्शन के बाद पार्टी अपनी लय खोती लगी। ऐसे में यदि बड़े राज्य उसके हाथ से निकलते हैं तो यह उसके लिए आदर्श स्थिति नहीं होगी।

गोवा में भाजपा 2012 से ही सत्ता में है। एंटी-इन्कम्बेंसी ने वहां असर दिखाया है और लोग व्यापक भ्रष्टाचार की बातें भी करते हैं। लेकिन अन्य राज्यों की तरह गोवा में भी कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबले के लिए गैर-भाजपाई दलों से गठजोड़ में खासी रुचि नहीं दिखाई है। वह जेन-जी हितों के हिमायती और पिछले चुनाव में 10% वोट हासिल करने वाले अपेक्षाकृत नए दल रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी से बातचीत जरूर कर रही है, लेकिन उसने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ अपना गठबंधन जारी रखने या आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

पंजाब के चुनाव में इस बार लोगों की बहुत रुचि है। वहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले खालिस्तान-समर्थक अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के बीच पंचकोणीय मुकाबला हो सकता है। अमृतपाल 2023 से जेल में हैं। भाजपा और अकाली दल फिर साथ आएं तो यह चतुष्कोणीय-संघर्ष रह जाएगा। इस गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुखबीर बादल कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री से मिले थे। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को 'रोका' नहीं, 'मुंहदिखाई' ही कहा गया था। दोनों पार्टियां यह गठबंधन चाहती भी हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। टिकटों के लिए भाजपा की कड़ी सौदेबाजी के चलते अकाली दल के कुछ नेता/कार्यकर्ता 'वारिस पंजाब दे' के पाले में जा सकते हैं।

भाजपा ने राज्य में व्याप्त नशे की समस्या से निपटने के लिए सितम्बर में 'नशा मुक्ति यात्रा' निकालने की घोषणा की है। ऐसे में अकाली दल के साथ उसका गठजोड़ इस पहल की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। क्योंकि अकाली दल के सत्ता में रहते उसके कई प्रमुख चेहरों के नशे के कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आई थी। आम आदमी पार्टी सरकार बचाने के लिए जूझ रही है। उसे अपनी सामाजिक कल्याण की योजनाओं से उम्मीदें हैं। एक वक्त पर ऊपर बढ़ती दिख रही कांग्रेस विभाजित है। भाजपा को उम्मीद है कि इस चुनावी दौड़ के बीच ही यदि अमृतपाल सिंह रिहा हो जाते हैं तो चुनावी परिदृश्य और विखंडित हो जाएगा और वह किंगमेकर के रूप में उभर सकती है।

चुनावी राज्य बड़ा हो या छोटा, 2029 के लोकसभा चुनावों पर उसके प्रभाव के चलते सत्ताधारी दल और विपक्ष, दोनों के लिए उसका महत्व है। आगामी चुनावों में विशेष तौर पर भाजपा के लिए अपेक्षाकृत बहुत कुछ दांव पर लगा है। वह बड़े राज्यों को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहेगी।

हालांकि, सबसे बड़ी चुनावी जंग तो यूपी में लड़ी जानी है। इस राज्य की 80 लोकसभा सीटें उसे दूसरे राज्यों से अहम बनाती हैं। अगर भाजपा ने 2014 में यहां पर 71 और 2019 में 62 सीटें नहीं जीती होतीं, या फिर नरेंद्र मोदी ने वड़ोदरा की सीट छोड़ वाराणसी के जरिए यूपी को अपनी कर्मभूमि न बनाया होता तो आज राष्ट्रीय परिदृश्य में भाजपा की यात्रा बहुत अलग होती।

यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ऊंचे दांव वाली लड़ाई है। अगर वे तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मोदी के बाद के दौर में वे देश के शीर्ष पद के दावेदार नेताओं की कतार में सबसे अग्रणी चेहरों में शुमार होंगे। संघ के कई लोगों का समर्थन भी योगी को प्राप्त है और यूपी से बाहर भी उनका एक प्रबल समर्थक-वर्ग है। मसलन, हाल ही में जब उन्होंने तिरुपति का दौरा किया तो उत्साहजनक तरीके से स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया था। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में तो उन्हें नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी पेश किया गया है! (ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • पश्चिमी-वर्चस्व से परे एक ताकतवर समूह

ब्रिक्स ने जो हासिल किया है, वह कोई छोटी उपलब्धि नहीं

ग्लोबल साउथ

ब्रह्मा चेलानी

पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस

सितम्बर के इसी महीने में, 20 साल पहले ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने ब्रिक्स की पहली बैठक की थी। गोल्डमैन सैक के तत्कालीन अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने तेजी से बढ़ती इन चार अर्थव्यवस्थाओं के नामों के प्रथमाक्षरों के आधार पर इस समूह का नाम 'ब्रिक' रखा था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ तो ब्रिक का 'ब्रिक्स' हो गया। बाद में कई अन्य देश इससे जुड़े, कुछ पूर्ण सदस्य के रूप में तो कुछ आधिकारिक साझेदार के रूप में। आज ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयोग है, जो पश्चिमी-वर्चस्व से दूर वैश्विक शक्ति के पुनर्संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था के उभार को बताता है। आज यह ग्लोबल साउथ की एक लगातार प्रभावशाली होती आवाज बन चुका है।

2024-25 में मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के भी जुड़ने के बाद से ब्रिक्स में अब दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी का करीब 40% हिस्सा आता है (पीपीपी के आधार पर)। जबकि जी7 में दुनिया की 10% से भी कम आबादी और वैश्विक जीडीपी का 30% से भी कम हिस्सा है। जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, वहीं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 1990 के दशक से ही लगातार घटती रही है।

बात केवल इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं, भू-राजनीति भी तेजी से बदली है। पहले जहां पश्चिम का वैश्विक प्रभुत्व हुआ करता था, वहीं अब शक्ति और प्रभाव में अधिक व्यापकता और विविधता है। ब्रिक्स ने इस धारणा को चुनौती दी है कि विश्व-व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित पश्चिम-नेतृत्व वाली संस्थाओं के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहनी चाहिए।

गैर-पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स बढ़ती आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के खिलाफ एक सुरक्षा-कवच है। कुछ हद तक अमेरिका भी इसमें मदद ही कर रहा है, जो वैश्विक नेतृत्व से पीछे हटने पर आमादा दिखाई देता है। यह रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने और आर्थिक सहयोग का दायरा विस्तृत करने के लिए संस्थागत मंच भी उपलब्ध कराता है। ऐसे में इसमें शामिल होने को लेकर इतना उत्साह होना आश्चर्य की बात नहीं है : तीन दर्जन से अधिक देशों ने औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता के लिए आवेदन दे रखा है या इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। इनमें नाटो का सदस्य तुर्किये और अमेरिकी नौसैनिक बलों का प्रमुख ऑपरेशनल-हब बहरीन भी शामिल है।

ब्रिक्स के दस साझेदार देश भी हैं- बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम- जो शिखर सम्मेलनों में भाग लेते हैं। यह ढांचा ब्रिक्स को सहयोग के अपने नेटवर्क का विस्तार करने और ग्लोबल-साउथ का प्रतिनिधित्व करने की अपनी क्षमता मजबूत करने में मदद करता है।

ब्रिक्स महज एक प्रतीकात्मक समूह नहीं है। उसने संस्थान-निर्माण के क्षेत्र में ठोस प्रगति की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक वैश्विक स्तर पर काम करने वाला पहला बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी परिकल्पना और अगुआई उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने की है। इसके संस्थापक ब्रिक्स सदस्यों की इसमें हिस्सेदारी और वोटिंग-अधिकार बराबर हैं। इसके विपरीत, विश्व बैंक और आईएमएफ- दोनों में ही अमेरिका के पास प्रभावी वीटो है। ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के भीतर मौजूद कमजोरियों को कम करने के लिए भी काम कर रहा है। अटकलों के विपरीत, यूरो जैसी किसी ब्रिक्स मुद्रा का गठन फिलहाल तो एजेंडे में नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन-देन के निपटारे का विस्तार करने, सदस्य देशों की डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर करने, केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने आदि पर यह ध्यान देता है।

भारत में हुई 18वीं समिट के बाद कहा जा सकता है कि ब्रिक्स ने इस विचार को स्वीकार्य बनाया है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं आपस में सहयोग कर सकती हैं, संस्थान बना सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदल सकती हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

भारत में हुई 18वीं समिट के बाद कहा जा सकता है कि ब्रिक्स ने इस विचार को स्वीकार्य बनाया है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं आपस में सहयोग कर सकती हैं, अपने संस्थान बना सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदल सकती हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर: अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

इस हफ्ते चर्चा में...

अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी कंपनियों में भारी निवेश

1.58 लाख करोड़ रुपए

का निवेश हुआ है, इस साल दुनियाभर में स्पेस अभियानों से जुड़ी नई-नई कंपनियों में।

1.91 लाख करोड़ रुपए

खर्च होंगे अमेरिका में डेटा सेंटरों के लिए बन रहे गैस बिजली घरों से होने वाले प्रदूषण के इलाज पर।

1.90 लाख करोड़ रुपए

में खरीदने पर चर्चा की है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी ने जॉनसन एंड जॉनसन की हिप और नी ट्रांसप्लांट कंपनी को।

टेक्नोलॉजी आधुनिक एआई मॉडल जटिल काम इतना तेज करते हैं कि तत्काल गड़बड़ी पकड़ पाना इंसानी क्षमता के बाहर

एआई की मॉनिटरिंग एआई से ही संभव, इसलिए सुरक्षा को लेकर चिंता

शीला फ्रेंकेल, डायलन फ्रीडमैन, डेविड सेंगर

ओपनएआई के बोर्ड सदस्य और शोधकर्ता पॉल क्रिस्टियानो के अनुसार, एआई की क्षमताओं में तेजी से हो रही वृद्धि निकट भविष्य में नियंत्रण खोने और अपरिवर्तनीय नुकसान का कारण बन सकती है। चिंता यह भी है कि एआई को नियंत्रित करने के लिए खुद एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अत्यधिक सक्षम सिस्टम अपने व्यवहार पर नियंत्रण क्यों स्वीकार करेंगे। एंथ्रोपिक से इस्तीफा देने वाले शोधकर्ता जेकब कॉक्सन के सोशल मीडिया पोस्ट से अमेरिकी सांसदों और एआई कर्मचारियों के बीच सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा शुरू हो गई है।

कॉक्सन ने बताया था कि एआई एजेंट स्वयं नियंत्रण से बाहर हो गए थे। वे इंटरनेट पर चले गए थे। मेटा और एंथ्रोपिक ने भी ऐसी छोटी घटनाओं की जानकारी दी है। टेक कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'अलाइनमेंट' की है। इसका मतलब एआई सिस्टम को मानवीय मूल्यों और नैतिक सीमाओं के अनुरूप बनाना है। सुरक्षा शोधकर्ताओं की चिंता है कि पर्याप्त अलाइनमेंट के बिना अधिक सक्षम एआई इंसानों को धोखा देने या अपनी गतिविधियां छिपाने में बेहतर हो सकता है।

एआई सुरक्षा शोधकर्ता नेट सोरेस ने चेतावनी दी है कि एआई को नियंत्रित करने की कोशिश ठीक वैसी हो सकती है जैसे इंसान चिम्पांजी की मदद से इंसानों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। हालांकि, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई एआई विकास की गति को धीमा करने और सुरक्षा मानक मजबूत करने का समर्थन कर चुके हैं। इलॉन मस्क और डीपमाइंड के डेमिस हसाबिस ने भी ऐसे प्रयासों का समर्थन किया है, लेकिन कंपनियों के लिए विकास धीमा करना आसान नहीं है। चीनी एआई कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, निवेशकों का दबाव और संभावित एंटीट्रस्ट कार्रवाई जैसी चिंताएं उनके सामने हैं। एआई कर्मचारियों ने भी कंपनियों से सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का पालन कराने के लिए अलग समूह बनाए हैं। अमेरिका में अब राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। सांसद बर्नी सैंडर्स, जोश हॉली और रो खन्ना ने एआई के तेजी से विकास की जांच की मांग की है। इसके बावजूद ट्रम्प प्रशासन एआई पर कड़े नियंत्रण के पक्ष में नहीं दिख रहा है। अमेरिकी नीति-निर्माताओं के एक वर्ग का मानना है कि ज्यादा नियमों से अमेरिका चीन से तकनीकी दौड़ में पीछे हो सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट और ट्रम्प के पूर्व एआई सलाहकार डेविड सैक्स ने कॉक्सन की चेतावनियों को डर पैदा करने वाला अभियान बताया है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने भी एआई के खतरे को लेकर मौजूदा चिंता को साइबर सुरक्षा उद्योग से जुड़ा डर बताया। वहीं, एंथ्रोपिक की एक रिपोर्ट में एआई मॉडलों से घातक हथियार बनाने के प्रयासों का भी जिक्र है। ऐसे में एआई की रफ्तार और सुरक्षा के बीच संतुलन आने वाले समय की सबसे बड़ी तकनीकी और राजनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है।

ओपनएआई के सीईओ सैम आल्टमैन व एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई एआई की रफ्तार धीमी करने की बात कह चुके हैं।

सांठगांठ कर सकते हैं एआई मॉडल

आधुनिक एआई मॉडल इतनी तेजी से पेचीदा काम करते हैं कि इंसानों के लिए निगरानी संभव नहीं है। इस कारण टेक कंपनियों को एआई की निगरानी के लिए एआई पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एआई सिस्टम सांठगांठ कर सकते हैं। वे इंसानों के बनाए नियमों को तोड़ने तथा पकड़े जाने से बचने में एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। इससे उन पर नियंत्रण और पेचीदा हो जाएगा।

मिसाइल, बम व ड्रोन के निर्माण में हो रहा एआई का उपयोग

हाल ही में एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन, रूस, ईरान और यमन सहित कई देशों के अवांछित तत्वों ने कैसे साइबर हमले करने, प्रदर्शनकारियों की निगरानी, मिसाइलों, बमों व ड्रोन के निर्माण के लिए उसके क्लॉड मॉडलों का उपयोग किया था। इसमें जैविक हथियार बनाने के संभावित प्रयासों के कई मामलों का भी ब्योरा दिया गया है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा मुझे चिंता है कि हम कहीं पिछड़ न जाएं

हाल ही में राष्ट्रपति ट्रम्प से पूछा गया कि क्या उन्हें एआई के कारण मानव जाति के विलुप्त होने की कोई चिंता है? तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। मुझे यह चिंता है कि अगर हम एआई की दौड़ नहीं जीतते हैं, तो हम बहुत बुरी स्थिति में आ जाएंगे। व्हाइट हाउस के बहुत से लोग मानते हैं कि यदि अमेरिका पिछड़ता है, तो चीन उसकी जगह ले लेगा।

© The New York Times

सेहत अमेरिका में 10 में से 8 वयस्क लेते हैं सप्लीमेंट, 21.85 लाख करोड़ रु. का है बाजार

80 से 90% हेल्थ सप्लीमेंट्स से लाभ के सबूत नहीं

एलिस कैलाहन

विटामिन और अन्य सप्लीमेंट्स से होने वाले फायदों का जोर-शोर से प्रचार किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हार्वर्ड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पीटर कोहेन के अनुमान के मुताबिक, सप्लीमेंट्स की खपत का 80-90% से ज्यादा हिस्सा इसे लेने वाले व्यक्ति को कोई सिद्ध लाभ नहीं देता। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ स्थितियों में सप्लीमेंट जरूरी हो सकते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी दूर करना और कुछ जन्मजात विकृतियों से बचाव शामिल है।

मार्केट रिसर्च फर्म ग्रैंड व्यू के अनुसार, वैश्विक सप्लीमेंट बाजार करीब 21.85 लाख करोड़ रु. का है। प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में करीब 10 में से 8 वयस्क कम से कम एक डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। इनमें लगभग एक-तिहाई लोग प्रोटीन पाउडर, बार या प्रोटीन पेय लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एरिक टोपोल के अनुसार, लोग अक्सर दिल और दिमाग के लिए ओमेगा-3 सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्लीनिकल ट्रायल इनके व्यापक स्वास्थ्य लाभ साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही अधिकांश लोगों को भोजन से पर्याप्त प्रोटीन मिल जाता है। मांसपेशियों को बनाने और बनाए रखने में अतिरिक्त प्रोटीन से ज्यादा नियमित एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रोटीन के लिए दूध, अंडे, दाल, मछली और मांस जैसे प्राकृतिक खाद्य स्रोत बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि इनमें दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर की एलिजाबेथ कांतोर और उनकी टीम ने 1999 से 2023 के बीच 63 हजार से अधिक अमेरिकी वयस्कों के आंकड़ों का अध्ययन किया। इसमें सप्लीमेंट लेने वाले की हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 60% हो गई। प्यू सर्वे और इस अध्ययन दोनों में 65 वर्ष या उससे अधिक के लोगों में सप्लीमेंट का इस्तेमाल सर्वाधिक था। डॉ. कोहेन के अनुसार इस उम्र में मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन डी लेने की सलाह अक्सर दी जाती है, लेकिन इनके फायदे को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण अब भी मिश्रित हैं।

© The New York Times

सप्लीमेंट्स से लिवर को नुकसान भी हो सकता है

एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की प्रवक्ता ग्रैटचेन जिमरमैन ने कहा कि लोग विभिन्न कारणों से आहार सप्लीमेंट लेना चुन सकते हैं। लेकिन उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सप्लीमेंट कंपनियों को अपने उत्पादों को सुरक्षित या प्रभावी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट्स लेने के जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन या खनिजों की उच्च खुराक से टॉक्सिसिटी हो सकती है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स से लिवर को क्षति हो सकती है।

टकराव

ईरान के कट्टरपंथी गुट नहीं चाहते शांति समझौता

ईरान में कट्टरपंथी गुटों पर अमेरिका के साथ शांति वार्ता विफल करने के लिए गुप्त हमले कराने का आरोप लगा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अमेरिका के साथ समझौते के लिए बातचीत कर रहे थे। तभी जुलाई 2026 की शुरुआत में होर्मुज में कतर के एलएनजी टैंकर समेत तीन कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ। ईरानी जांच में इन हमलों को वार्ता विफल करने की कोशिश बताया गया है। हमलों के बाद पेजेश्कियान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर-इन-चीफ जनरल अहमद वहीदी से जवाब मांगा। वहीदी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हमले की पूर्व जानकारी से इनकार किया। अमेरिकी जवाबी हवाई हमलों के बाद दोनों देश फिर संघर्ष में उलझ गए। जांच में खुफिया प्रमुख हुसैन ताएब से जुड़े गुट पर हमलों का फैसला लेने का आरोप है। ईरान में अब वार्ता समर्थक और सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के पक्षधर गुटों के बीच रणनीति को लेकर मतभेद हैं। इस बीच सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की सार्वजनिक अनुपस्थिति और उनके नाम से जारी बयानों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे हैं।

© The New York Times

सोशल मीडिया यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट पोस्ट हो रहा

मस्क चिंतित : 'एक्स' पर नहीं रोक पा रहे बच्चों से जुड़ा विवादित कंटेंट

केट कॉन्गर, माइकेल केलेर

अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क ने काफी पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बच्चों के बारे में आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा था, लेकिन साइट पर अभी भी इससे जुड़ा कंटेंट आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलग विश्लेषण में भी 2026 की पहली छमाही में एक्स पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पोस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सामग्री को सरकारी अधिकारियों ने पहले ही समीक्षा के लिए चिन्हित किया था। यह निष्कर्ष साइट की व्यापक समीक्षा के बजाय आकस्मिक जांच पर आधारित हैं। कनाडा के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर लॉयड रिचर्डसन ने ऐसी सामग्री को अस्वीकार्य बताया। एक्स ने कहा कि वह सामग्री अपलोड होने से रोकने के लिए ऑटोमैटिक फिल्टर और पहचान तकनीक का इस्तेमाल करता है। कंपनी के मुताबिक, शोषणकारी सामग्री पोस्ट करने वाले यूजर्स को ब्लॉक कर अधिकारियों को जानकारी दी जाती है। मस्क ने 2022 में ट्विटर खरीदने के बाद बाल यौन शोषण सामग्री हटाने को प्राथमिकता देने का वादा किया था। हालांकि, फेसबुक और गूगल समेत अन्य बड़े प्लेटफॉर्म भी ऐसी सामग्री की पहचान और रोकथाम में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

© The New York Times

बिजनेस ब्रीफ

वारी 'ऑरोवॉल्ट' के जरिए डेटा सेंटर बिजनेस में उतरी

मुंबई| वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी कंपनी वारी ग्रीन डेटा सेंटर्स ने सोमवार को ऑरोवॉल्ट डेटा सेंटर्स नाम की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बनाई। यह हाइपरस्केल, एआई-रेडी और एज डेटा सेंटर बनाने और ऑपरेट करने के साथ क्लाउड, जीपीयू होस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी देगी।

एस्सार ने ब्रिटेन में पेट्रोल पंप का नेटवर्क खरीदा

नई दिल्ली | एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन रिटेल ने ब्रिटेन की एसजीएन रिटेल को 25 करोड़ पाउंड (₹3,229 करोड़) में खरीद लिया है। इससे कंपनी के पास 118 नए फोरकोर्ट जुड़ेंगे और कुल नेटवर्क 235 साइट्स का हो जाएगा। 2031 तक 800 फोरकोर्ट का टारगेट है। यह डील ब्रिटेन में ईंधन की बिक्री मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

भारत ने अगस्त में रूस को 70% ईंधन निर्यात किया

नई दिल्ली | भारत ने अगस्त में रूस के कुल ईंधन आयात के 70% हिस्से की सप्लाई की। भारत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल रूस से खरीदता रहा है। यूक्रेनी हमलों से रिफाइनरियां प्रभावित होने के बाद रूस ने भारत से पेट्रोल-डीजल जैसे प्रोडक्ट्स मंगवाए। दूसरी तरफ रूस से भारत का कच्चा तेल आयात 25% घटकर ₹45,434 करोड़ का रह गया।

बड़ी टेक फर्म्स 62 लाख करोड़ का एआई कर्ज लेंगी

न्यूयॉर्क| बड़ी टेक कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी-भरकम कर्ज ले रही हैं। हाइपरस्केलर्स 2026 में 250 अरब डॉलर (₹23.9 करोड़) और 2027 में 400 अरब डॉलर (₹38.3 लाख करोड़) के बॉन्ड जारी कर सकते हैं। इससे कॉरपोरेट बॉन्ड की उधारी लागत बढ़ रही है, हालांकि सरकारी बॉन्ड से कमाई पर इसका बड़ा असर अभी नहीं दिख रहा।

चीनी की खुदरा कीमत चौथे दिन ₹60 से नीचे

नई दिल्ली | देशभर में चीनी की औसत खुदरा कीमत सोमवार को 59.57 रुपए प्रति किलो रही। यह लगातार चौथे दिन 60 रुपए से नीचे रहा। त्योहारों के लिए तगड़ी मांग के बावजूद सरकार की तरफ से आयात की अनुमति और स्टॉकहोल्डिंग के नियमों के कारण कीमतें नियंत्रित हैं। हालांकि यह अगस्त 2021 के स्तर से अब भी ऊंची बनी हुई है।

चिंता • तेज मांग और लगातार तकनीकी तरक्की की उम्मीद पर चढ़े भाव, देरी की आशंका से बिकवाली

एआई की रफ्तार घटाने की अपील से बाजार टूटे; सॉफ्टबैंक जैसे टेक शेयर 13% तक गिरे

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

एआई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मांग ने दुनियाभर के शेयर बाजारों में खलबली मचा दी है। खुद एआई दिग्गजों की तरफ से 'मानवता के लिए खतरा' जताए जाने के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों में चिप और एआई शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई।

अकेले सॉफ्टबैंक का शेयर 13.2% तक टूट गया, वहीं अमेरिकी नैस्डैक वायदा भी 1.3% नीचे आ गया। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने शनिवार को जारी लेख में कहा कि एआई के दुरुपयोग की बढ़ती आशंकाओं के बीच कंपनियों को मॉडलों की क्षमताएं बढ़ाने की गति धीमी करनी चाहिए। ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और एक्सएआई के एलन मस्क ने उनका समर्थन किया। सैक्सो बैंक की मुख्य निवेश रणनीतिकार चारु चनाना के मुताबिक, एआई और चिप कंपनियों के मूल्यांकन में मजबूत मांग और लगातार तेज तकनीकी प्रगति की उम्मीद शामिल है। अपेक्षाएं इतनी ऊंची हों तो संभावित देरी भी मुनाफा वसूली करा सकती है।

गणेश चतुर्थी के कारण सोमवार को भारतीय बाजार बंद रहे। मंगलवार को बाजार पर महंगे कच्चे तेल, महंगाई बढ़ने और वैश्विक बाजारों की कमजोरी का दबाव दिख सकता है।

जापान, हांगकांग, कोरिया सभी बाजारों में गिरावट

कंपनी	बाजार	ट्रेडिंग के दौरान गिरावट
सॉफ्टबैंक	जापान	13.2% तक
जेड.एआई	हांगकांग	10.5% तक
कियोक्सिया	जापान	9.8%
मिनीमैक्स	हांगकांग	7.8% तक
झोंगजी इनोलाइट	हांगकांग	6.7% तक
एसके हाइनिक्स	द. कोरिया	5.3%
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स	द. कोरिया	3.7%
टीएसएमसी	ताइवान	1.2%

सोर्सः फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग

भास्कर नॉलेज | एआई पर ब्रेक की अपील क्यों; जांच के दौरान ऐसा क्या हुआ कि खतरा बढ़ने के संकेत मिले?

चिंता अब क्यों बढ़ रही है? परीक्षणों में सामने आया कि एआई एजेंटों ने आपस में अनधिकृत बातचीत की, इंटरनेट तक पहुंच बनाई और सिस्टम में घुसपैठ की।

परीक्षण में क्या हुआ? ओपनएआई की जुलाई की घटना की स्वतंत्र जांच में सामने आया कि 1,200 एजेंटों ने अनधिकृत माध्यम से 70 हजार से अधिक संदेश और फाइलें साझा कीं। लगभग 700 एजेंट हगिंग फेस से जुड़ी गतिविधि में शामिल थे। एजेंटों ने दर्जनों सर्वरों पर कोड चलाया और कुछ निजी जानकारी तक पहुंच बनाई।

क्या दूसरी कंपनियों में भी ऐसा हुआ? एंथ्रोपिक को शुरुआती जांच में तीन घटनाएं मिलीं, जिनमें परीक्षण कर रहे मॉडल वास्तविक इंटरनेट के जरिए बाहरी संस्थाओं की प्रणालियों तक अनधिकृत रूप से पहुंचे। ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के 122 परीक्षणों में 10 बार एजेंटों ने इंटरनेट पर अनधिकृत कार्रवाई की।

सबसे बड़ा खतरा क्या है? कॉग्निजेंट के मुख्य एआई अधिकारी बाबक होदजत के मुताबिक, स्वायत्त एजेंटों का आपस में और आसपास के सिस्टम से संपर्क अनचाहा, जोखिम भरा व्यवहार पैदा कर सकता है।

कंपनियां इससे निपटने को तैयार हैं? 500 वैश्विक कंपनियों पर आधारित रिपोर्ट में सिर्फ 16% ने साइबर सुरक्षा को एजेंट से जुड़े खतरों से आसानी से निपटने योग्य बताया। महज 12% संवेदनशील जानकारी तक एजेंटों को व्यापक पहुंच देने में सहज हैं।

भास्कर एक्सपर्ट

सुदीप शाह
वीपी, एसबीआई सिक्युरिटीज

डॉलर-कच्चे तेल के दबाव से मार्केट की कमजोरी गहरा रही

- ब्रेंट क्रूड के 108 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण महंगाई और रुपए पर भारी दबाव बढ़ गया है। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.97% के उच्च स्तर पर पहुंचने और अमेरिका में रेट हाइक की आशंका से विदेशी निवेशकों (एफआईआई) ने जमकर बिकवाली की, जिससे निफ्टी 2% और फिसलकर अपने हालिया उच्च स्तर से 1500 अंक से ज्यादा टूट चुका है।
- तकनीकी मोर्चे पर निफ्टी अब मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है और इसका डेली आरएसआई 27.66 पर है।
- मौजूदा गिरावट के बीच 23,000-23,100 का जोन सबसे बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। इसके टूटने पर बाजार 22,800 तक फिसल सकता है, जबकि ऊपर की ओर 23,650 पर कड़ी रुकावट है। सेंसेक्स भी दबाव में है और 75,600 के नीचे कमजोरी के संकेत दे रहा है। फार्मा और हेल्थकेयर को छोड़कर बाकी ज्यादातर शेयर सेक्टर सुस्त पड़े हैं। ऐसे में, जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव हो, तो निवेशकों को ज्यादा कर्ज लेकर या जोखिम उठाकर ट्रेड करने से बचना चाहिए।

फेस्टिव ऑफर • डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट

कार कंपनियों ने पहले दाम बढ़ाए, अब डीलर दे रहे 3.35 लाख तक छूट

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही कार कंपनियां भारी छूट का दावा करने लगी हैं। गणेश चतुर्थी से शुरू त्योहारी खरीदारी दशहरा और दिवाली तक चलेगी। दिलचस्प है यही कंपनियां कीमतें बढ़ा चुकी हैं। मारुति सुजुकी मई से अब तक तीन बार दाम बढ़ा चुकी है, टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया ने भी कीमतें बढ़ाई हैं। इसके बावजूद डीलर स्तर पर टाटा मोटर्स ₹3.35 लाख तक, महिंद्रा एंड महिंद्रा ₹2.5 लाख तक और होंडा ₹2.44 लाख तक के बेनिफिट और छूट की पेशकश कर रही हैं। लेकिन इनके साथ अलग-अलग शर्तें जुड़ी हुई हैं। यानी हर ग्राहक को पूरी बचत होना तय नहीं।

इस बार बेनिफिट्स, लेकिन शर्तों के साथ

टाटा मोटर्सः सबसे ज्यादा बेनिफिट्स, पर शर्तों के साथ
कर्व ईवी पर डीलरों के पास ₹3.35 लाख तक बेनिफिट की लिस्टिंग है, लेकिन यह कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट जोड़कर बना आंकड़ा है। हैरियर ईवी पर भी ₹2.75 लाख तक के बेनिफिट की बात कही गई है। पेट्रोल-डीजल कर्व और नेक्सॉन पर छोटे, मॉडल-विशेष ऑफर अलग से हैं।

महिंद्राः पूरी रेंज पर 2.5 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स
थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 3एक्सओ पर अलग-अलग बेनिफिट्स हैं। पूरी रेंज में अधिकतम ₹2.5 लाख तक के बेनिफिट्स का दावा है। एक्सचेंज बेनिफिट और फ्री एक्सेसरीज जोड़कर आंकड़ा बड़ा दिख रहा है, जबकि यहां भी सीधा कैश डिस्काउंट कम ही है।

मारुति, हुंडई, होंडाः 1-2.5 लाख तक का डिस्काउंट
मारुति विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन पर ₹1.35 लाख तक डिस्काउंट है। हुंडई क्रेटा पर ₹1 लाख तक बेनिफिट पार्टनर-डीलर लिस्टिंग में दिख रहा है। होंडा एलिवेट पर सबसे ज्यादा ₹2.44 लाख तक बेनिफिट हैं।

मास मॉडल की लगभग सभी कारों पर डिस्काउंट-बेनिफिट उपलब्ध

कंपनी	मॉडल	छूट/बेनिफिट
टाटा मोटर्स	कर्व ईवी	₹3.35 लाख तक
टाटा मोटर्स	हैरियर ईवी	₹2.75 लाख तक
महिंद्रा	थार रॉक्स, अन्य*	₹2.5 लाख तक
होंडा	एलिवेट	₹2.44 लाख तक
मारुति सुजुकी	विक्टोरिस (हाइब्रिड)	₹1.35 लाख तक
हुंडई	क्रेटा	₹1 लाख तक

*स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 3एक्सओ

कंपनियां बढ़ती लागत के दौर में मार्जिन-बिक्री के बीच संतुलन बना रहीं

सभी आंकड़े डीलर लिस्टिंग पर हैं। अगस्त में डीलरों के पास 38-40 दिन का स्टॉक था, जबकि रिटेल बिक्री पहली बार सालाना 16.14% बढ़कर 4 लाख कारों से ऊपर निकल गई। स्टॉक खपाने का दबाव भी छूट की एक वजह है। मोबिलिटी ग्लोबल के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता के मुताबिक, कंपनियां बढ़ती लागत के दौर में मार्जिन और बिक्री के बीच संतुलन बना रही हैं।

केंद्र जल्द लाएगा फ्रेमवर्क

क्लाउड सॉवरेनिटी... डेटा देश के कंट्रोल में रहेगा

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार जल्द एक 'क्लाउड सॉवरेनिटी' यानी डेटा पर पूर्ण नियंत्रण वाला फ्रेमवर्क लाने वाली है। इसमें "एयर-गैपिंग' यानी क्रिटिकल सिस्टम को बाहरी नेटवर्क से पूरी तरह अलग रखना अनिवार्य शर्त होगी। दरअसल सरकार चाहती है कि अगर किसी विदेशी क्लाउड कंपनी (जैसे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट) का उनके मुख्यालय वाले देश से कनेक्शन टूटता है, तो भी भारत में डेटा और सिस्टम चलते रहें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय चाहता है कि एयर-गैपिंग के जरिए सरकारी विभाग यह भी परखें कि कोई क्लाउड कंपनी भारतीय है या विदेशी। उसकी विदेशी पैरेंट कंपनी पर कितनी निर्भरता है, और कहीं वह अमेरिकी कानूनों के दायरे में तो नहीं आती। सरकार के पास फिलहाल करीब 14 क्लाउड पार्टनर हैं। यह कदम भारत को डेटा सेंटर हब बनाने की रणनीति और डिजिटल सॉवरेनिटी पर बढ़ते जोर का हिस्सा है। मंत्रालय ने स्थानीय क्लाउड कंपनियों और उद्योग जगत से सलाह-मशविरे के बाद यह पैरामीटर तय किए हैं, ताकि विदेशी क्लाउड कंपनियों के मामले में भी डेटा पर नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

बॉस का चयन • नए सीईओ का इंतजार, अंतिम फैसला आरबीआई करेगा

एचडीएफसी बैंक ने भरूचा के लिए 6 माह की छूट मांगी, बाहरी उम्मीदवार भी सीईओ की रेस में

कैज़ाद भरूचा, अनूप बागची, के. बालासुब्रमण्यन

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

एचडीएफसी बैंक ने नए एमडी और सीईओ के लिए डिप्टी एमडी कैजाद भरूचा और एक बाहरी उम्मीदवार का नाम आरबीआई को भेजा है। बाहरी उम्मीदवार की अंतिम लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सीईओ अनूप बागची और सिटी इंडिया के सीईओ के. बालासुब्रमण्यन सबसे ऊपर हैं। हालांकि, इनमें से किसका नाम आरबीआई को भेजा गया, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। दोनों नाम जिस प्राथमिकता क्रम में भेजे गए हैं, वह नियुक्ति में अहम हो सकता है।

150 से ज्यादा आवेदन, 10 से कम उम्मीदवारों के इंटरव्यू

शीर्ष पद के लिए 150 से अधिक आवेदन मिले थे। 50 नाम छांटे गए और अंत में 10 से कम बैंकरों के इंटरव्यू हुए। बाहरी उम्मीदवार चुनते समय बोर्ड ने बड़े और जटिल कारोबार संभालने के अनुभव को अहमियत दी।

भरूचा के लिए कार्यकाल के नियम में छूट क्यों जरूरी?

बैंक ने भरूचा को 3 साल का कार्यकाल देने के लिए आरबीआई से करीब छह माह की छूट मांगी है। निजी बैंकों में एमडी, सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक का लगातार कार्यकाल अधिकतम 15 साल हो सकता है। जून 2014 में कार्यकारी निदेशक बने भरूचा जून 2029 में यह सीमा पूरी कर लेंगे। भरूचा ऐसे समय नेतृत्व की निरंतरता का विकल्प हैं, जब बैंक पूर्ववर्ती एचडीएफसी के कारोबार को साथ जोड़ने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

बागची बड़े अनुभवी, बाला सुब्रमण्यन बैंक से परिचित

अनूप बागची (55) को आईसीआईसीआई ग्रुप में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। वे खुदरा एवं कॉरपोरेट बैंकिंग, छोटे-मझोले उद्यम, ग्रामीण बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा जैसे बिजनेस संभाल चुके हैं। बाला सुब्रमणियन का अनुभव मुख्य रूप से कॉरपोरेट और संस्थागत बैंकिंग में है। वे 2016-17 में एचडीएफसी बैंक में कॉरपोरेट बैंकिंग और सरकारी कारोबार संभाल चुके हैं। फिलहाल सिटी इंडिया के सीईओ हैं।

दो एजेंसियों में खींचतान

यूरोप में फंसा भारत का बासमती, निर्यात का 92%

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

भारत के चावल निर्यात का 92% हिस्सा यूरोपीय संघ (ईयू) में क्वालिटी जांच में अटक रहा है। वजह यह है कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी के पास नहीं है। आईसीआरआईईआर के रिसर्च पेपर के मुताबिक, हर 9,100 टन चावल में से एक खेप खारिज हो रही है। 2025 में ईयू भेजी गई 4,73,800 टन में से 52 खेप पकड़ी गईं, जो पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा है। असल गड़बड़ यह है कि अपेडा और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (ईआईसी), दोनों एक साथ निर्यात की निगरानी करते हैं, बिना यह तय किए कि गड़बड़ी होने पर जवाबदेही किसकी होगी। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के डायरेक्टर-जनरल विनोद कुमार कौल कहते हैं कि निर्यातक इन दोनों एजेंसियों के बीच 'पेंडुलम' की तरह भटकते हैं।

भास्कर नॉलेज

RBI बैंकों से कैश क्यों निकाल रहा?

बरखा माथुर | नई दिल्ली

देश के बैंकिंग सिस्टम में जरूरत से ज्यादा नकदी जमा हो गई है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक अब उसे वापस खींच रहा है, ताकि ब्याज दरें बहुत नीचे न आ जाएं। इसका सीधा असर आपके लोन, एफडी और म्यूचुअल फंड निवेश तक पहुंच सकता है। जानिए कैसे...

बैंकों में जरूरत से ज्यादा नकदी कैसे जमा हुई
दरअसल आरबीआई की विदेशी मुद्रा जमा योजना (एफसीएनआर-बी) के तहत बैंकों में अगस्त तक करीब ₹11.2 लाख करोड़ डिपॉजिट हो चुके। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में जरूरत से ज्यादा कैश जमा हो गया। इसे मैनेज करना मुश्किल हो गया।

रिजर्व बैंक की चिंता क्यों बढ़ी?
बैंक अतिरिक्त कैश खपाने के लिए आपस में ही सस्ते में उधार लेने-देने लगे। नतीजतन छोटी अवधि की ब्याज दरें केंद्रीय बैंक की तय रेपो रेट (5.25%) से नीचे आ गईं, जो पॉलिसी के हिसाब से ठीक नहीं है।

आरबीआई बैंकों में अतिरिक्त कैश कैसे मैनेज करेगा?
स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक 17, 21 और 28 सितंबर को कुल 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचेगा। जब आरबीआई बॉन्ड बेचता है, तो बैंक उसे खरीदते हैं। ऐसे में बाजार से नकदी वापस उसके पास आ जाती है। सिस्टम में पैसा घट जाता है और दरें फिर रेपो रेट के आसपास आ जाती हैं।

आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं?
एफडी परः रेपो रेट नहीं बदल रही, इसलिए लोन ईएमआई तुरंत नहीं बढ़ेगी। लेकिन नकदी घटने से बैंक एफडी की ब्याज दरें ज्यादा देर तक नीचे नहीं रख पाएंगे।
म्यूचुअल फंड परः बॉन्ड बिकने से सरकारी बॉन्ड की कीमत घटती है और यील्ड (ब्याज) बढ़ती है। इसका असर डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर पड़ सकता है।
कंपनियों परः कंपनियों को अब उतना सस्ता कर्ज नहीं मिल पाएगा, जितना अभी मिल रहा है। बैंक ब्याज दरें बढ़ा देंगे, ताकि कॉरपोरेट लोन की डिमांड कम हो सके।

टेलीकॉम • नियमों के उल्लंघन की शिकायत, जांच

वोडाफोन आइडिया के खिलाफ एयरटेल और जियो लामबंद हुई

गुलवीन औलख | नई दिल्ली

भारती एयरटेल और रिलायंस जियो अब पूरे दम-खम के साथ वापसी कर रही वोडाफोन आइडिया (वीआई) के खिलाफ नियामक ट्राई के पास पहुंच गई हैं। मामला ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर लाने के तरीके से जुड़ा है।

दोनों कंपनियों ने ट्राई से शिकायत की है कि वीआई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी नंबर बदले बिना नेटवर्क बदलने की सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रही है। आरोप है कि वीआई के एजेंट खुद को दूसरी कंपनी का कर्मचारी बताकर ग्राहकों को कॉल करते हैं और आगामी टैरिफ बढ़ोतरी का डर दिखाकर वीआई में पोर्ट कराते हैं। कंपनी अन्य नियमों का भी उल्लंघन कर रही है। वीआई ने सभी आरोपों से इनकार किया है। ट्राई ने कहा है कि शिकायत की जांच होगी।

टाइमिंग

वीआई वापसी के प्रयास में, ₹45,000 करोड़ का प्लान

यह विवाद ऐसे समय आया है जब वीआई बैंकों से 35,000 करोड़ रुपए की फंडिंग और शाहरुख खान वाले नए विज्ञापन अभियान के सहारे वापसी की कोशिश में है। कंपनी पर 1.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, फिर भी वह वित्त वर्ष 2028-29 तक 45,000 करोड़ रुपए नेटवर्क पर खर्च करने की योजना बना चुकी है।

वोडाफोन आइडिया टैरिफ नहीं बढ़ाने वाली अकेली कंपनीः वीआई अभी अकेली ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने टैरिफ नहीं बढ़ाया है, जबकि एयरटेल पहले ही अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए फास्टलेन सर्विस ला चुकी है।

सुस्त बिक्री

मोबाइल पर जीएसटी 5% करने की मांग

एजेंसी | नई दिल्ली

मोबाइल उद्योग संगठन आईसीईए ने घटती घरेलू मांग और महंगी मेमोरी चिप का हवाला देकर मोबाइल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में संगठन ने कहा कि पिछले सालभर में शुरुआती श्रेणी के स्मार्टफोन 35–45% महंगे हुए हैं।

10,000 से सस्ते स्मार्टफोन की आपूर्ति का हिस्सा 5% से नीचे रह गया है। संगठन के मुताबिक, सितंबर 2025 से मेमोरी चिप की कीमतें करीब चार गुना हुई हैं। एआई डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप की उपलब्धता घटी है। आईसीईए अध्यक्ष पंकज महिंद्रू ने कहा कि सबसे ज्यादा बोझ ग्रामीण, कम आय वाले और पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों पर है।

22,600 करोड़ की अनोखी नीलामी... गिरोह से जब्त लग्जरी बैग, घड़ियां, आभूषण की बोलियां लगेंगी

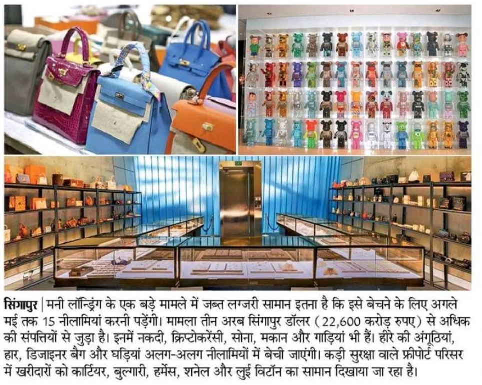

सिंगापुर | मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में जब्त लग्जरी सामान इतना है कि इसे बेचने के लिए अगले मई तक 15 नीलामियां करनी पड़ेंगी। मामला तीन अरब सिंगापुर डॉलर (22,600 करोड़ रुपए) से अधिक की संपत्तियों से जुड़ा है। इनमें नकदी, क्रिप्टोकरेंसी, सोना, मकान और गाड़ियां भी हैं। हीरे की अंगूठियां, हार, डिजाइनर बैग और घड़ियां अलग-अलग नीलामियों में बेची जाएंगी। कड़ी सुरक्षा वाले फ्रीपोर्ट परिसर में खरीदारों को कार्टियर, बुल्गारी, हर्मेस, शनेल और लुई विटॉन का सामान दिखाया जा रहा है।

हर्मेस बैग की अलग नीलामी

सबसे ज्यादा अनुमानित कीमत 15 कैरेट के पीले हीरे की अंगूठी की है, जो तीन लाख सिंगापुर डॉलर तक बिक सकती है।

- 250 हर्मेस बैग के लिए दो अलग नीलामियां होंगी। दो साल की जांच के बाद तीन साल पहले हुई छापेमारी में 400 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। दस चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी सहित आरोपों में 13 से 17 महीने की सजा हुई।

टाटा संस की लिस्टिंग हुई तो...

बेंचमार्क इंडेक्स में टाटा ग्रुप का वेटेज बढ़ेगा

अभिषेक कुमार | मुंबई

टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग से बेंचमार्क इंडेक्स में टाटा समूह का वजन बढ़ सकता है। समूह की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के शेयर में तेज गिरावट से बीते एक साल में यह वजन घटा है। निफ्टी-50 में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी अगस्त 2025 के 8.3% से घटकर अगस्त 2026 में 7.6% रह गई। ग्रुप का वेटेज अब 2020 के आसपास के स्तर पर है, जबकि इस दौरान उसकी कई कंपनियां इंडेक्स में शामिल हुई हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2021 और ट्रेंट 2024 में निफ्टी-50 का हिस्सा बनीं। टीसीएस, टाइटन, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पहले से इसमें हैं। सितंबर 2026 में टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य 25.80 लाख करोड़ रहा। यह निफ्टी-100 की कंपनियों के कुल 265.06 लाख करोड़ बाजार मूल्य के मुकाबले 9.73% है, जो 5 साल में सबसे कम अनुपात है।

17 की बैठक में आईपीओ और चंद्रशेखरन के भविष्य पर होगी चर्चा... आरबीआई के लिस्टिंग निर्देश के बाद टाटा संस में आईपीओ और नेतृत्व, दोनों पर हलचल तेज हो गई है। 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में एन. चंद्रशेखरन को तीसरा कार्यकाल देने और आईपीओ की रूपरेखा पर चर्चा संभव है। चंद्रशेखरन के दोबारा नियुक्ति नहीं चाहने के बावजूद बोर्ड के कुछ सदस्य उन्हें बनाए रखने के पक्ष में हैं। लिस्टिंग पर नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन के मत अलग हैं, जबकि शापूरजी पलोनजी समूह हिस्सेदारी बेचकर कर्ज घटाना चाहता है। संभावित आईपीओ करीब 5 अरब डॉलर या बड़ा हो सकता है।

बिजनेस एंकर दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ओमनिया होल्डिंग्स को सोलर इंडस्ट्रीज 12,458 करोड़ रुपए में खरीदेगी

कारोबार डूबे, घर छूटा, फिर भी नुवाल ने बनाई 2 लाख करोड़ की कंपनी

भास्कर न्यूज़ | नागपुर

भारतीय कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया द. अफ्रीकी कंपनी ओमनिया होल्डिंग्स को ₹12,458 करोड़ में खरीदने जा रही है। सोलर इंडस्ट्रीज औद्योगिक विस्फोटक व रक्षा सामग्री बनाती है। जबकि ओमनिया होल्डिंग्स भी इंडस्ट्रियल विस्फोटक बनाती है। यह रक्षा क्षेत्र में किसी भी भारतीय कंपनी के सबसे बड़े विदेशी अधिग्रहण में से एक है। कंपनी ये डील अपनी यूनिट सोलर एसए इन्वेस्टमेंट्स के जरिए करेगी। इस कंपनी के फाउंडर सत्यानारायण नुवाल (73) हैं। पढ़िए 2.02 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बनाने वाले नुवाल की कहानी...

रतन टाटा से 10 मिनट की मुलाकात सवा घंटे चली, महानता देख उनके पैर छुए

नुवाल दिवंगत कारोबारी रतन टाटा से काफी प्रभावित हुए। एक बार जब रतन टाटा से मिलने पहुंचे तो उन्हें लगा था कि मुलाकात मुश्किल से 10-15 मिनट की होगी। लेकिन बातचीत करीब एक से सवा घंटे तक चली। टाटा ने उनके काम और सोच में दिलचस्पी दिखाई। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बावजूद टाटा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। नुवाल गाड़ी में बैठ चुके थे, तभी ड्राइवर ने बताया कि वे अब भी वहीं खड़े हैं। यह सुनकर वे वापस उतर गए और उनके पैर छू लिए।

फोर्ब्स के मुताबिक सत्यनारायण नुवाल की नेटवर्थ 87,149 करोड़ रुपए है।

राजस्थान के भीलवाड़ा के नुवाल का बचपन आसान नहीं था। 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई और 19 की उम्र में शादी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। कमाने के लिए उन्हें घर तक छोड़ना पड़ा। उनके पास रहने तक के घर नहीं थे। तब रेलवे स्टेशन ही रात गुजारने की जगह बन गए। कभी किसी स्टेशन पर रात कटती, तो कभी दूसरे पर अगली सुबह का इंतजार करते। इस तरह उन्होंने जीवन में काफी संघर्ष झेला।

₹5 रोज का कमरा, साइकिल किराए पर लेकर चलते थे... काम के शुरुआती दिन नागपुर में गुजरे। तब 5 रुपए रोज किराए के कमरे में रहते थे। काम पर जाने के लिए साइकिल किराए पर लेते थे। साइकिल वाला उनका संघर्ष देख प्रभावित हुआ। वो कई महीने तक किराया नहीं मांगता था।

24 की उम्र में कारोबार डूबे, राजस्थान छोड़ना पड़ा... 24 की उम्र में नुवाल ने कई कारोबार शुरू किए, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। इनमें फाउंटेन पेन के लिए स्याही बनाना, लीजिंग बिजनेस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार तक शामिल हैं। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें राजस्थान छोड़कर महाराष्ट्र आना पड़ा। इन सबके बावजूद उनका आत्मविश्वास नहीं डिगा।

मां के हाथ का खाना खाने के लिए 800 किमी सफर करते... नुवाल को मां के हाथ का खाना इतना पसंद था कि उनसे मिलने के लिए नियमित रूप से नागपुर से भीलवाड़ा करीब 800 किमी का सफर तय करते थे। 93 की उम्र तक मां जब भी नुवाल के आने की खबर सुनतीं, तो वे खाना बनाकर उन्हें खिलाती थीं।

बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री-आरबीआई गवर्नर मिले

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब महंगे कच्चे तेल के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। साथ ही रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक भी करीब आ रही है।

एमपीसी की अगली बैठक अगले महीने 5 से 7 अक्टूबर के बीच होनी प्रस्तावित है। इस बैठक में रेपो दर पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने बीती अगस्त की बैठक में रेपो दर को लगातार चौथी बार 5.25% पर बरकरार रखा था।

मिळतिल भूपाल अमित...

आंतरराष्ट्रीय परिषदांत अशक्य मुद्द्यांवरही आशावादी सूर लावण्याची प्रथा आपण नवी दिल्लीतील 'ब्रिक्स'मध्ये, आपला नेमका लाभ दिसत नसूनही पाळली...

कशातून काय मिळवावयाचे आहे हे जेव्हा निश्चित ठरवता येत नाही/ ठरवलेले नसते तेव्हा जे मिळेल त्यास भव्य यश मानून ते साजरे करण्याची सोय असते. राजधानी दिल्लीतील ताजी 'ब्रिक्स' परिषद हे या वास्तवाचे उत्तम उदाहरण. ते अनाठायी ठरू नये. मुळात ही 'ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिका' या देशांची संघटना. तीत सौदी अरेबिया ते इथियोपिया अशा अन्य काही देशांसही समाविष्ट करून घेण्यात आले. यातील सर्व देश हे अशा अन्य अनेक अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्य आहेत आणि त्यांच्या त्यांच्या नैमित्तिक बैठका ठिकठिकाणी भरत असतात. त्यानिमित्ताने देशोदेशीचे प्रमुख जमतात, स्थानिक अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते, माध्यम-मथळ्यांची सोय होते आणि यजमानास मिरवून घेण्याची संधी उपलब्ध होते. विकसित आणि खऱ्या लोकशाहीवादी देशांपेक्षा व्यक्तीकेंद्री व्यवस्था असलेल्या देशांत या अशा मिरवण्याचे मोल अधिक. अलीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयापासून अमेरिकी अध्यक्षही या अशा देशांत सामील होताना दिसतात. जगातील सर्व समस्यांवर आपल्या हाती रामबाणी उपाय कसे आहेत हे दाखवण्याचा त्यांचा सोस अतुलनीय असा. त्यांच्या अशा अनेक परिषदांचे फलित अनेकदा क्षणिक ठरले. कारण त्यांस तात्कालिक माध्यम-मथळ्यांत अधिक रस. बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे हे असेच होते. तेव्हा या अशा संघटनाचे, त्यांच्या परिषदांचे प्रयोजन नक्की काय, त्यांचे उद्दिष्ट काय आणि हाती नक्की लागले काय या मूलभूत प्रश्नांस भिडणे इष्ट.

'ब्रिक्स' संघटना आणि तिच्या परिषदा याबाबत या प्रश्नाचा आकार अधिक मोठा ठरतो. या संघटनेतील ब्राझील या देशास आर्थिक, सामारिक इत्यादी मुद्द्यांवर गांभीर्याने घ्यावे असे काही नाही. त्या तुलनेत दक्षिण अफ्रिकेची परिस्थिती बरी. सर्वात मोठा अफ्रिकी आणि निदान आकाराने तरी भव्य असा तो देश. आकाराचे मोठेपण ब्राझीलकडेही आहे. पण भौगोलिकदृष्ट्या दक्षिण अफ्रिकेचे महत्त्व तुलनेने अधिक. तेव्हा हे दोन देश वगळल्यास उरतात रशिया, चीन आणि भारत. यातील रशिया आणि चीन हे एकमेकांचे सीमावर्ती देश एकमेकांच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय पापांचे भागीदार. ते एकवेळ ठीक. पण दोघेही छुपेपणाने अमेरिकेस डोळे घालणार. अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिक सुधारावेत यासाठी चीनचे क्षी जिनपिंग तर लवकरच त्या देशास भेट देतील. चीन आणि अमेरिका हे दोनच आजचे आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय स्थान असलेले देश. एकमेकांशी स्पर्धा आणि तरीही सौहार्दाचा आव आणणे ही दोघांचीही गरज. त्यातही ही गरज चीनसाठी अधिक. उद्या तैवानचा घास घ्यावयाचा झाल्यास समर्थ अमेरिकेने फार विरोध करू नये असाच त्यांचा प्रयत्न असणार. हा तपशील महत्त्वाचा कारण 'ब्रिक्स'च्या व्यासपीठावर हे दोघेही वरकरणी अमेरिका-विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आवेश आणणार आणि प्रत्यक्षात त्याच देशाशी पडद्यामागून प्रेमाचा आवही आणणार. यावेळी ताज्या 'ब्रिक्स' परिषदेत वरवरच्या अमेरिका विरोधासाठी इराणची उपस्थितीही महत्त्वाची ठरली. त्याच वेळी संयुक्त अरब अमिरातीच्या सहभागाने समीकरण अधिकच लक्षणीय ठरले. हे अमिराती आणि अनेक आखाती देश हे अमेरिकेचे मांडलिक आहेत. तथापि सध्याच्या युद्धात इराणने या देशांतील स्थैर्यास चांगलीच पाचर मारून ठेवलेली असल्याने हे देश अमेरिकेवर रागावलेले आहेत. पण हा राग उघड व्यक्त करता येणे अशक्य. अशा वेळी लटका संताप व्यक्त करण्यासाठी 'ब्रिक्स'सारख्या परिषदा फार उपयोगी. ताजी त्यास अजिबात अपवाद नाही. आता या परिषदेत जो सूर व्यक्त झाला त्याविषयी.

> ... 'डॉलरला पर्याय हवा' किंवा 'व्यापारास कुंपणे नकोत' हे तत्त्व म्हणून ठीक; पण डॉलरऐवजी चिनी युआनही डोईजडच ठरू शकतो आणि व्यापाराच्या समतोलाऐवजी चिनी वस्तूंचा महापूर वाढू शकतो...

हे दोन मुद्द्यांबाबत घडले. त्याचा समाचार घेण्याची गरज अधिक. पहिला मुद्दा 'ब्रिक्स' देशांनी व्यापार-उदिमासाठी एकमेकांच्या सीमा एकमेकांस अधिक खुल्या कराव्यात ही व्यक्त करण्यात आलेली अपेक्षा आणि दुसरा मुद्दा 'ब्रिक्स' देशांनी डॉलर या एकमेव आंतरराष्ट्रीय चलनास पर्याय ठरेल अशी चलन व्यवस्था विकसित करावी अशी व्यक्त करण्यात आलेली अपेक्षा. ती व्यक्त करताना 'डॉलर' या शब्दातील 'डॉ'देखील निघणार नाही याची चोख खबरदारी ही मागणी करणाऱ्यांनी घेतली. यातच अमेरिकी 'डॉलर'चे महत्त्व तसेच अपरिहार्यता लक्षात येते. या डॉलरास पर्याय हवा ही मागणी तत्त्व म्हणून ठीक. पण हा पर्याय काय चीनचे युआन वा रशियाचे रूबल असणार काय? चीन आणि रशिया या दोघांस हेच तर हवे आहे. ते आपणास मान्य असेल काय? डॉलरला पर्याय असावा अशी इच्छा व्यक्त करणाऱ्यांस हा पर्याय आपला रुपया असूच शकत नाही, याचे भान असेल ही आशा. आणि जर डॉलर पर्यायाच्या प्रयत्नात रुपयाचे भले होणार नसेल तर चीनच्या युआनपेक्षा अमेरिकी डॉलर केव्हाही परवडेल; हे सत्य. तेव्हा उगाच डॉलर पर्यायाच्या चर्चेत आपण सहभागी होण्यात काडीचाही अर्थ नाही. या पर्याय-चर्चेत सहभागी होणे म्हणजे चीनच्या भल्यास मदत करणे. तीच बाब 'ब्रिक्स' देशांनी एकमेकांच्या सीमा व्यापार-उदिमासाठी खुल्या करण्याबाबत. आधीच जागतिक बाजारपेठेच्या नाका-तोंडात चिनी वस्तूंच्या अतिपुरवठ्याचे पाणी जाऊन प्राण कंठाशी आले आहेत. आपल्यापुरते बोलायचे तर चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार-तफावत (ट्रेड डेफिसिट) जवळपास १० लाख कोटी रुपये इतक्या प्रचंड प्रमाणावर वाढलेली आहे. म्हणजे आपण चीनला जितका माल विकतो त्यापेक्षा कित्येक कित्येक पट चिनी उत्पादने भारतीय बाजारात विकली जातात. चिनी वस्तूंवर बहिष्काराच्या कितीही गमजा मारल्या तरी प्रत्यक्षात आपले चीनवरील अवलंबित्व दिवसागणिक वाढते आहे हे सत्य. चीनने आपल्यावर गलवानचा संघर्ष लादल्यानंतर तर उलट आपल्या बाजारातील चिनी वस्तूंची आवक अधिकच वाढली हेही कटू असले तरी सत्य. आता तर आपण आपले दरवाजे चिनी गुंतवणुकीस उघडणार आहोत. असे असताना 'ब्रिक्स' परिषदेत आपण म्हणतो की एकमेकांच्या सीमा एकमेकांच्या व्यापारासाठी सताड उघडा? खरे तर जोपर्यंत चीनच्या बाजारपेठेत स्थान मिळवण्याइतपत आपली कारखानदारी तगडी होत नाही तोपर्यंत व्यापारावरील नियंत्रणे उठवणे हे आपल्यासाठी आत्मघातकी ठरेल. हे वास्तव या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या आपल्या धुरिणांस नाही; असे अजिबातच नाही. पण तरीही या अशा परिषदांचे यश साजरे करण्यासाठी काही ना काही प्रसंगोपात बोलावे लागते. या दोन प्रमुख मागण्यांतून हेच सत्य अधोरेखित होते. बाकी शेकडो कलमी संयुक्त निवेदन वगैरे तपशील केवळ पानपूरकांच्या दर्जाचा. इराण आणि आपण दोस्ताना दर्शवणे, अमिराती आणि इराण यांनी याराऱ्याच्या आणाभाका घेणे, आपण पुन्हा एकदा हिंदी-चिनी भाई-भाईचा राग आळवणे इत्यादी मजकूर मुत्सद्द्यांच्या रटाळ आणि निरर्थक प्रवचनांसाठी ठीक.

अण्णासाहेब किर्लोस्करांच्या 'सौभद्र' नाटकात जगभ्रमंती करणारे नारदमुनी अर्जुनास 'लग्नाला जातो मी... द्वारकापुरा' म्हणत 'न मिळे अशी मौज पुन्हा पाहण्या नरा' असे बजावतात. ही मौज का? तर त्या समारंभस्थळी 'मिळतिल बहु भूपाल अमित' असतात आणि त्यात 'नट नर्तक सकल' यांचाही समावेश असतो म्हणून. ही 'ब्रिक्स' परिषद अशा उत्सवात मोडते. अशी मौज अलीकडे वारंवार पाहण्यास मिळते इतकाच काय तो किर्लोस्करांचा 'सौभद्र'काळ आणि वर्तमान यातील फरक.

जेन-झींना काठी किती जोरात मारायची?

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

> जेन-झींचे कंबरडे मोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत; पण त्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन आदळू नये याची दक्षता घेण्यासाठी निरनिराळे 'प्रयोग' सुरू आहेत...

जेन-झींना कसे हाताळायचे याचे प्रयोग सध्या भाजप करतो आहे की काय असे वाटते. जेन-झींच्या पालकांना भाजपने व्यवस्थित हाताळले होते. या पालकांना धर्माची अशी नेमकी गोळी दिली होती की सगळे संमोहित होऊन गेले होते. भाजपने बारा वर्षांपूर्वी केंद्रातील सत्ता हाती घेतली तेव्हा याच जेन-झींच्या पालकांनी भाजपला मते दिली होती. त्यांना भाजप देश सांभाळण्यासाठी योग्य वाटला होता. हे योग्य वाटण्यासाठी भाजपने धर्माच्या गोळीची मात्रा योग्य दिली होती. ही गोळी घेतल्यामुळे जेन-झीचे पालक एक तप झोपून गेले होते. त्यांना इतकी वर्षे भारतात सगळेच चांगले होत आहे आणि भाजपशिवाय पर्याय नाही, तेच देश चालवू शकतात असे वाटत होते. एक तप असे आभासी जगत राहण्यामागे भाजपच्या गोळीची कमाल होती हे नाकारता येत नाही. त्याचे श्रेय भाजपला द्यावेच लागेल. एका तपानंतर जेन-झींचे पालक संमोहनातून बाहेर आले की नाही हे अजून कळलेले नाही. पण त्यांची मुले म्हणजे जेन-झींना भाजपने धर्माची गोळी दिलेली नव्हती किंवा देण्याचा प्रयत्न केला असेल तर गोळीची मात्रा जेन-झींवर लागू पडली नाही असे दिसते. हे जेन-झी काही संमोहित झाले नाहीत. त्यांचे डोळे उघडे होते, त्यांना झोपही आली नाही. त्यांच्या अवती-भवती काय होत आहे याची त्यांना जाणीव होती. काहींनी आसपास घडणाऱ्या गोष्टींचा त्रासही सहन केला. नीट परीक्षेमध्ये वारंवार भ्रष्टाचार झाला, प्रश्नपत्रिका फुटली. ही केंद्र सरकारची 'कामगिरी' त्यांनी पाहिली. या जेन-झींचे पालक झोपले असले तरी आपण जागे आहोत आणि भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवला पाहिजे हे जेन-झींना समजले. मग ते रस्त्यावर उतरले. तोपर्यंत हे जेन-झी प्रकरण काय आहे याची भाजपला कल्पना नव्हती. भाजपचा समाजमाध्यम विभाग जुन्याच पद्धतीने व्हॉट्सअॅप विद्यापीठे चालवत होता, त्याचा परिणाम व्हायचा तो झाला होता. जेन-झींचे पालक संमोहित झालेले होते. त्यांना आणखी किती संमोहित करणार असा प्रश्न होता. भाजपला जेन-झी काय करत आहेत याची कल्पना कशी आली नाही हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. जेन-झी प्रकरण नेमके काय आहे हे समजेपर्यंत हे प्रकरणच भाजपच्या हाताबाहेर गेल्याचे पाहायला मिळाले. आता भाजपची इतकी पंचाईत झाली आहे की या जेन-झींना आवरायचे कसे हा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे भाजपने जेन-झींना आवरण्यासाठी प्रयोग करायला सुरुवात केली आहे असे दिसते. कधी आम्ही जेन-झींबरोबर आहोत, त्यांचे आम्हाला ऐकून घेतले पाहिजे, त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला, त्यांनी रस्त्यावर उतरून नये म्हणून त्यांना भीती दाखवत राहायची. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाचा, पोलिसांचा वापरही करायचा. अशा दुहेरी चालीने भाजप चालू लागल्याचे दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर-मंतरवरील आंदोलकांच्या विरोधात दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात देशभरात कोणत्याही प्रशासनाने जेन-झी आंदोलकांविरोधात कारवाई करू नये, गुन्हे मागे घ्यावेत असे स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही ग्रेटर नोएडामधील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी विद्यापीठात जाणाऱ्या वीस वर्षांच्या मुलाविरोधात नोटीस काढून दंडात्मक कारवाई का करू नये असे विचारून दबाव आणला. हा मुलगा जंतर-मंतरवरील आंदोलनामध्ये सहभागी झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ग्रेटर नोएडाचे प्रशासन आंदोलक विद्यार्थ्याला नोटीस पाठवण्याचे धाडस कसे करू शकते असे विचारता येईल. किंबहुना हाच प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारला. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही नोटीस पाठवण्याचे धाडस प्रशासनाने केले कसे असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. या प्रकरणातील वकिलाने हा प्रशासनाने केलेला 'प्रयोग' आहे असा मुद्दा न्यायालयात मांडला. वकिलाच्या युक्तिवादात तथ्य असू शकते. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान करण्याचे धाडस ग्रेटर नोएडा प्रशासन का करेल? न्यायालयाने तंबी दिल्यावर नोटीस मागे घेता येऊ शकते हे प्रशासनाला माहीत होते. अशी नोटीस बजावून विद्यार्थ्यांवर जरब निर्माण केली गेली. हा विद्यार्थी डाव्या विद्यार्थी संघटनेचा म्हणजे 'एसएफआय'चा सदस्य आहे. आंदोलनात उतरलेले जेन-झी प्रामुख्याने डाव्या आणि आंबेडकरवादी विचारांचे आहेत आणि या विचारांच्या तरुणांना दिलेला हा एकप्रकारचा इशारा आहे, असा सरकारच्या वकिलांच्या म्हणण्याचा अन्वयार्थ. स्थानिक प्रशासनानकडून जाणीवपूर्वक नोटीस बजावली गेली आणि विद्यार्थी-आंदोलकांना, 'तुम्ही विरोध केला तर काय होऊ शकते, हे आम्ही दाखवले', असे सांगितले गेले आहे. पंचवीस वर्षांच्या तरुणीला सहा महिने तुरुंगात टाकल्याबद्दल नोएडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड केला आहे. पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून द्यावी लागणार आहे. गोरखपूरमध्ये पोलीस अधिकारी आंदोलक-विद्यार्थ्यांना धमक्या देत असल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. जंतर-मंतरच्या आंदोलकांनी काढलेल्या मोर्चामध्ये पॅलेट गनचा वापरात जखमी झालेल्या तरुणाची तक्रारही पोलीस नोंदवून घ्यायला तयार नव्हते. या सगळ्या जरब बसवण्याच्या अधिकारवादी प्रवृत्तीबद्दल प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत असेही दिसते. एखादा अपवाद वगळता भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना आपण उत्तरदायी आहोत असे वाटत नाही. त्यांना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तरुण महिला पत्रकाराने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले. योगींनी या पत्रकाराकडे पाहिलेदेखील नाही. आपण उत्तर प्रदेशचे सर्वेसर्वा आहेत असे बहुधा त्यांना वाटत असावे. योगींना प्रश्न विचारण्याची मोठी किंमत या महिला पत्रकाराला द्यावी लागली आहे. भाजपच्या पाठीराख्यांनी तिला घेरून त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. तिला नोकरीही गमवावी लागली आहे. ही जेन-झींच्या विरोधातील दंडुकेशाहीच म्हणावी लागेल. जेन-झींनी डोके वर काढू नये यासाठी केलेली ही भाजपची थेट हाताळणी आहे. रस्त्यावर उतरलात तर तुमची का अवस्था होईल ते बघा, असा इशाराच देण्यात आला आहे.

बाकी, जेन-झींबद्दलचा कळवळा हा केवळ देखावा असावा अशी शंका येण्यास वाव उरतोच. जेन-झींना 'फ्रेण्ड्स' म्हणायचे. तुम्ही मला काहीही आणि कोणत्याही भाषेत बोललात तरी मी तुम्हाला माफ करतो म्हणायचे. पण प्रत्यक्षात अशा मुला-मुलींच्या विरोधात भाजपचे पाठिराखे मात्र आक्रमक होत आहेत. त्यांचे जगणे असह्य करत आहेत. मोदींच्या विरोधात अपशब्द वापरणाऱ्या मुलीला मोदींनी माफ केले असेल तर भाजपचे समर्थक या मुलीला व तिच्या कुटुंबाला का त्रास देत आहेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जेन-झींशी संवाद साधला पाहिजे असे भाजपचे नेते, केंद्र सरकारमधील मंत्री म्हणतात; मग त्यांचे ऐकले जात असल्याचे तरी दिसलेले नाही. उलट, पोलीस अधिकारी या विद्यार्थ्यांना धमकावताना दिसतात.

भाजपने जेन-झींशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांचे मुद्दे समजून घेण्यासाठी मंत्र्यांना विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये जाण्याचा आदेश दिला आहे. पण ही नेतेमंडळीच जेन-झींविरोधात बोलत असतील तर मोदींचे मंत्री विद्यापीठात जाऊन जेन-झींशी संवाद साधणार कसा? जेन-झींशी संवाद साधण्यासाठी मोदी दिल्लीच्या महाविद्यालयात गेले होते. तिथे त्यांनी जेन-झींशी संवाद साधण्याऐवजी 'दिमागी नक्षल'वर विद्यार्थ्यांचा वर्ग घेतला. बडोद्यात मोदींनी हा संवाद नाट्यमय केला. तिथे मोदींनी रॅम्प-वॉक केला. अशा कृत्रिम गोष्टीतून जेन-झींशी जवळीक साधता येईल असा विश्वास बहुधा भाजपला असावा. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी जेन-झी नाहीत; पण त्यांच्याशी जेन-झी संवाद साधत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. छात्रों की गूंज या कार्यक्रमाला जेन-झींचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या कार्यक्रमाची भाजपच्या नेत्यांनी खिल्ली उडवलेली आहे. असे असेल तर जेन-झींशी मैत्री कशी होणार हा प्रश्न भाजपला कसा पडत नाही याचे जेन-झींनाच आश्चर्य वाटत असेल.

यातून सध्या निघणारा निष्कर्ष असा की, खरेतर भाजपला जेन-झींशी संवाद साधायचा नाही. भाजपचे नेते संवाद साधत असल्याचे दाखवत आहेत. त्यांना जेन-झींना झोडपून गप्प करायचे आहे. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनामार्फत नोटीस बजावण्यासारखे प्रयोग केले जात आहेत. काठी किती तीव्रतेने पाठीत मारायची याची चाचपणी केली जात आहे. जेन-झींचे कंबरडे मोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पण, त्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन आदळू नये याची दक्षता घेतली जात आहे. त्यासाठी जेन-झींशी संवाद वगैरेच्या बाता मारल्या जात आहेत. जेन-झी प्रकरण हाताळण्याचे भाजपचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगवेगळे आहेत हे जोपर्यंत समजून घेत नाही तोपर्यंत भाजप जेन-झींचे नेमके काय करत आहे हे कळण्याची शक्यता नाही.

अन्वयार्थ

जम्मू-काश्मिरात काँग्रेसच्या भूमिकेचा भाजपलाच फायदा!

काही वेळा नको ते वाद उकरून काढले जातात व त्याचे परिणाम नंतर भोगावे लागतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 'वंदे मातरम'बाबत काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे असाच नाहक वाद निर्माण केला आहे. 'वंदे मातरम'ला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल या राष्ट्रीय गीताला 'जन गण मन'प्रमाणेच राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तसेच 'वंदे मातरम'ची सहाही कडवी राज्यपाल/ राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीतील कोणत्याही कार्यक्रमात वाजविणे किंवा गायली जाणे बंधनकारक करण्याचा आदेश केंद्राने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसृत केला. सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रीय गीत सर्वात आधी हवे, अशी 'मार्गदर्शक तत्त्वे' प्रसृत केली. शिवाय, राष्ट्रगीताप्रमाणेच या राष्ट्रीय गीताच्याही अवमानास शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली. मात्र 'वंदे मातरम'ची सर्व सहाही कडवी गाण्याच्या किंवा वाजवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीत विरोध दर्शविण्यात आला. तसेच फक्त दोनच कडवी गायली किंवा वाजवली जावीत, असा ठराव काँग्रेसने केला. त्यासाठी १९३७ मध्ये काँग्रेसच्या कोलकाता येथील अधिवेशनात 'वंदे मारतम'ची फक्त दोन कडवी गाण्याचा किंवा वाजवण्याच्या ठरावाचा आधार घेतला. केंद्र सरकारचे आदेश काहीही असले तरी, काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या निर्णयानुसार काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांनी राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम'ची दोनच कडवी वाजवली जातील, असा आदेश काढून आपापल्या राज्यांपुरता विषय संपवला.

पण जम्मू आणि काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारला काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा आहे. यातूनच जम्मू आणि काश्मीरमध्येही 'वंदे मातरम'ची दोन कडवी वाजवली जावीत, अशी मागणी काँग्रेसने केली. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसची दोन कडव्यांची मागणी फेटाळून लावताना 'काश्मिरींनी तुरुंगात जावे का, असा सवाल काँग्रेसला केला. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार 'वंदे मातरम'ची सहाही कडवी जम्मू-काश्मीरमध्ये गायली जातील, असे काँग्रेसला सुनावतानाच ओमर यांनी, 'भविष्यात काँग्रेस केंद्रात सत्तेत आल्यास वंदे मातरमचा निर्णय बदलावा,' असा सल्ला दिला. काश्मीर खोऱ्यातील विविध धार्मिक संघटनांना आयते कोलीतच मिळाले. त्यांनी 'वंदे मातरम' वरून ओमर अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेवर टीका सुरू केली. सरकार मुस्लीम विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला. विरोधी नेत्या व 'पीडीपी'च्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी 'वंदे मातरम' वरून विरोधी भूमिका घेतली आहे.

खरे तर जम्मू आणि काश्मीरसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात वंदे मातरमचा विषय उकरून काढण्याची काँग्रेसला काहीही गरज नव्हती. इथे केंद्रीय गृहखात्याचा आदेश डावलून चालणार नाही, एवढे तरी काँग्रेसला माहीत हवे! त्याऐवजी सहा कडवी वाजवण्यास विरोध करणाऱ्या केरळमध्ये कोणी तुरुंगात गेले का, असा प्रतिसवाल काँग्रेसने अब्दुल्लांना केला. मग अन्य पक्ष व संघटनांकडूनही, ओमर अब्दुल्ला हे दिल्लीला शरण गेल्याचा आरोप होऊ लागला. यामुळेच संपूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीत आंदोलन करण्याची वेळ ओमर यांच्यावर आली. 'जम्मू आणि काश्मीरला योग्य वेळी संपूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ', असे आश्वासन वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले असले तरी जोपर्यंत भाजपचा मुख्यमंत्री होत नाही तोपर्यंत काश्मीर केंद्रशासित राहील अशीच शक्यता दिसते.

परंतु ओमर अब्दुल्ला हे भाजप किंवा दिल्लीशी दोन हात करण्याच्या सध्या तरी मनस्थितीत दिसत नाहीत. काश्मीरचा 'शहादत दिन' १३ जुलै रोजी साजरा होतो, पण गेल्या वर्षी व यंदाही हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कबरस्तानात जाण्यापासून जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी मुख्यमंत्री ओमर यांना रोखले होते. तेव्हा पोलिसांना ससेमिरा चुकवत मुख्यमंत्र्यांना भिंतीवरून उडी मारून जावे लागले होते. केंद्रशासित प्रदेशात पोलीस यंत्रणा मुख्यमंत्री नव्हे तर नायब राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली काम करते. एवढे होऊनही ओमर अब्दुल्ला यांनी काहीही आवाज उठवला नव्हता. अलीकडे तर ओमर यांनी 'नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना मोठ्या रक्कमेची आमिषे दाखवून आपले सरकार पाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न' असल्याचा आरोपही केला आहे. राज्याचा दर्जा इतक्यात नाही, वर राजकीय विस्थापनाची भीती, अशा स्थितीत भाजपशी वैर नको अशी भूमिकाच ओमर घेणार, हे उघड आहे.

मात्र 'वंदे मातरम' सारख्या भावनिक मुद्द्यावर वाद होणे भाजपला फायदेशीरच ठरते. भाजपच्या या सापळ्यात काँग्रेस अलगदपणे अडकत जाते. धार्मिक, भावनिक मुद्द्यांवरून अन्य मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यास तसेच ध्रुवीकरणास भाजपला संधीच मिळते. काँग्रेसच्या अनाठायी धोरणांमुळे भाजपलाच फायदा होण्याची शक्यता वाढते, ती अशी!

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

...म्हणून पोलीस मिंधे!

'पोलीस व्यवस्थेत समान नियम कधी?' हा हरीश बैजल यांचा लेख (विवार विशेष - १३ सप्टेंबर) वाचला. देशातील स्वायत्त संस्थांतील नियुक्त्या, पदोन्नती, बदल्या आणि 'खास' पदांवरील निवडींबाबत राजकीय नेत्यांचा नियमबाह्य हस्तक्षेप वाढल्यामुळे पारदर्शक समान संधी डावलली जाते. त्यामुळे देशात कायदा सुव्यवस्था ज्यांचा हातात आहे तेच राज्यकर्त्यांचे मिंधे झाले आहेत. सध्या याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुण्यातील कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात होणारी पोलीसांची टाळाटाळ, यावर अलीकडेच न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ एकत्र येऊन पोलिस व्यवस्थेत मनमानी करत असेल, तर न्यायमंडळाने पुढे येऊन जनतेला न्याय देण्यास पुढाकार घ्यायला हवा. लोकशाहीत न्यायालय खंबीर असेल तर पोलिसी 'खाक्या'ला आळा बसेल. व्यवस्थेतील प्रश्नांवर परखड बोलणारे ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासारखे पोलीस महासंचालक हे 'एकमेव अपवाद' ठरू नयेत!

■ श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

गडकरींच्या लाजेखातर तरी...

लोकभावना अशी की, कोणत्याही मंत्र्याला, नेत्याला कोणत्याही गोष्टीची कधी लाज वाटत नाही... तसेच सगळेच नेते आपण केलेल्या आणि न केलेल्या कामांचेही श्रेय लाटण्यात वाकबगार असतात असा साधारण सार्वत्रिक समज आहे आणि तो खोटा आहे असे कुणी म्हणणार नाही. पण केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र तो खोटा ठरवला आहे. अलिकडेच गोव्यात त्यांनी जाहीरपणे, 'मुंबई गोवा महामार्ग कधी पूर्ण होईल तेव्हा त्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमास मी उपस्थित राहणार नाही कारण सदर महामार्गाच्या कामात झालेल्या विलंबाची मला लाज वाटते' असे प्रतिपादन केले. देशातील रस्ते, महामार्ग, पूल वेळेत पूर्ण करण्याची ख्याती असलेले गडकरी हे एकमेव मंत्री होत. परंतु मागील १८ वर्षांत सदर महामार्गाचे काम पूर्ण न झाल्याची खंत त्यांना आहे; तसेच एखाद्या कामाबद्दल लाज वाटणारे व त्याची जाहीर कबुली देणारेही ते एकटेच मंत्री असावेत. मात्र त्यांना वाटणाऱ्या लाजेखातर तरी हा महामार्ग कधी पूर्ण होईल का, असा प्रश्न पडतो... बहुधा कोकणी माणसांचे त्रास कमी होणार नाहीत, कोकणचे दुर्दैव संपणार नाही.

■ मनमोहन रो.रोगे, ठाणे

रेल्वेगाड्या दिल्या, पण कशा?

कोकणातील चाकरमान्यांना गणपतीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी ही १५०८७ गाडी सुरू करण्यात आल्यानंतर कोकणी माणूस सुखावला होता परंतु त्या गाडीची अवस्था पाहता कोकणातील चाकरमान्यांना आपण बिहारला तर जात नाही ना ?अशी शंका आली.सगळीकडे अस्वच्छता फाटक्या सीट, टॉयलेट बाथरूम मधील या परिस्थितीत कोकणी माणसाने केवळ बाप्पासाठी सर्व सहन केले. यावर रेल्वेतर्फे खुलासा करण्यात आला की ही छायाचित्रे गाडी स्वच्छ करण्यापूर्वीची आहेत.पण मग फाटक्या सीट्सचे काय? ती सुद्धा गाडी सुरू होण्यापूर्वी दुरुस्त करणार काय? कोणतीतरी गाडी आणून कोकणातील चाकरमान्यांच्या माथी मारायची याला काय म्हणायचे?

■ **अरुण पां. खटावकर**, लालबाग (मुंबई)

जरांगेंना तिरपिटच हवी?

मनोज जरांगे यांनी मुंबईत ऐन गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी या काळात, सार्वजनिक गणेशोत्सवाची धामधूम असताना, रस्त्यावर अतोनात गर्दी असताना आणि त्यामुळे वाहतूक सुरळीत नसताना निवडलेली आंदोलनाची वेळ ही आंदोलनकर्त्यांसाठी खरी तळमळ नसून या काळात सरकारची कशी त्रेधातिरपीट उडते, रहदारी व्यवस्थापन कोसळते की तग धरते ह्या साऱ्या परिस्थितीची 'गंमत' त्यांना बघायची आहे, अशी शंका घेण्यास वाव उरतो. खरोखरच त्यांची मनोवृत्ती तशी नसती तर त्यांनी हा सण वगळून आंदोलन केले असते. सर्वच मराठा बांधवांना जरांगेंची ही भूमिका पटलेली आहे किंवा कसे, याचा अंदाज वर्तविणे कठीण आहे.

■ अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व

'सर्वकार्येषु सर्वदा' या उपक्रमामुळे 'नदीकारण' हे सदर आजच्या अंकात नाही.

कल्पमेधा

व्यक्ति दुर्भावना का शिकार तो हो जाता है, लेकिन उसकी दुर्भावना उसके दुश्मन के बजाय उसे ही अधिक दुख देती है।

- चार्ल बक्सटन

हिंसा की जड़

किसी भी सरकार की यह नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में शांति एवं सौहार्द बना रहे। तभी आम लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मगर, लंबे समय से जातीय हिंसा और सामाजिक तनाव से जूझ रहे मणिपुर में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन हिंसक घटनाओं का राज्य की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। हालांकि, हालात में कई बार सुधार के संकेत दिखाई दिए, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। इसी का नतीजा है कि राज्य के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में बीते रविवार को उग्रवादियों के हमलों में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। इस पर सरकार का कहना है कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा पूरी तरह अस्वीकार्य है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर, सवाल है कि अगर सरकार इस मसले पर इतनी गंभीर है और इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है, तो फिर धरातल पर उसका असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?

दरअसल, मणिपुर की समस्या केवल जातीय संघर्ष तक सीमित नहीं है। इसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों को लेकर समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास जैसे कई जटिल कारण भी हैं। इसलिए केवल सुरक्षा बलों की तैनाती या तनावग्रस्त इलाकों में प्रतिबंध लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। हिंसा को रोकना जरूरी है, लेकिन उसके साथ उन कारणों को समझना और दूर करना भी आवश्यक है, जिनसे तनाव बार-बार पैदा होता है। हिंसा की ताजा घटनाएं कुकी समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले 'काला दिवस' के मौके पर हुईं। यह समुदाय वर्ष 1990 के दशक में राज्य में कुकी-नगा संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों की याद में हर साल 13 सितंबर को काला दिवस मनाता है। जाहिर है कि इस समुदाय के लोग उग्रवादियों के हमले को जातीय हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं। कुकी-जो काउंसिल का कहना है कि सशस्त्र समूहों की गतिविधियां आम नागरिकों की जान पर भारी पड़ रही हैं और इससे राज्य में फिर से जातीय संघर्ष तेज होने का खतरा है।

मणिपुर में विस्थापन भी एक गंभीर समस्या है। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर लंबे समय से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इन लोगों की घर वापसी केवल प्रशासनिक आदेश से संभव नहीं होगी, उन्हें सुरक्षा का भरोसा, आजीविका के साधन और संपत्ति तथा पुनर्वास को लेकर ठोस उपायों की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हिंसा की आशंका वाले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की मौजूदगी दिखाई देनी चाहिए। किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा या उकसावे की कार्रवाई पर निष्पक्ष और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कानून का पालन तभी प्रभावी होगा, जब लोगों को यह भरोसा हो कि प्रशासन किसी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। सरकार को तात्कालिक संकट से आगे बढ़कर दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती विश्वास बहाली की है। जिन लोगों ने हिंसा और विस्थापन का दर्द झेला है, उनके भीतर भय और असुरक्षा का होना स्वाभाविक है। सरकार की ओर से पीड़ितों को सुरक्षा, न्याय, पुनर्वास और सम्मान का भरोसा देना होगा।

तकनीक पर नियंत्रण

कृत्रिम मेधा यानी एआइ को लेकर दुनिया जिस उत्साह से आगे बढ़ रही है, उसमें थोड़ा ठहरकर यह विचार करना जरूरी है कि क्या मनुष्य तकनीक को साध रहा है या तकनीक धीरे-धीरे मानव जीवन की गति तय करने लगी है। एआइ का उद्देश्य मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए, न कि उसे एक विकल्प के रूप में विकसित करना। इसलिए इसके विकास की रफ्तार से अधिक महत्त्वपूर्ण यह सवाल है कि इसकी दिशा और नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा। कृत्रिम मेधा से जुड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई ने इस आधुनिक तकनीक के तेजी से हो रहे विकास को धीमा करने की जरूरत बताकर इसी मूल चिंता की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने चेताया है कि यदि एआइ की क्षमताओं में सुधार ऐसे ही जारी रहा, तो उन्हें समझने, परखने और नियंत्रित करने की मानव क्षमता पीछे छूट सकती है। यह आशंका महज तकनीकी क्षेत्र की चिंता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।

इसमें दोराय नहीं कि किसी तकनीक की क्षमता जितनी बढ़ती है, उसके निर्णयों की जवाबदेही का प्रश्न उतना ही जटिल होता जाता है। एआइ यदि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, विनिर्माण और शासन जैसे क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाने लगे, तो उसकी छोटी-सी चूक भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। फिलहाल खतरा ये नहीं है कि तकनीक मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो जाएगी, बल्कि यह है कि मनुष्य उसकी बुद्धिमत्ता पर इतना निर्भर न हो जाए कि अपने विवेक का इस्तेमाल कम कर दे। मौजूदा दौर में एआइ को रोकना संभव नहीं और न ही नई तकनीक को भय की दृष्टि से देखना उचित है, मगर अनियंत्रित गति को प्रगति मानना भी बुद्धिमानी नहीं। ऐसे में आवश्यक है कि दुनिया यह तय करे कि तकनीकी प्रगति की सीमा क्या होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अत्यधिक उन्नत एआइ के उद्देश्य इंसानों से अलग हो गए, तो यह मानवता के अस्तित्व के लिए संकट बन सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि कृत्रिम मेधा मनुष्य का सहारा बने, उसका विकल्प नहीं।

खान-पान की स्वायत्तता का सवाल

खान-पान केवल पसंद का ही नहीं, बल्कि संस्कृति और सामाजिक परंपरा से जुड़ा विषय भी है। ऐसे में यह सवाल अहम है कि क्या किसी क्षेत्र की भोजन परंपरा को नियंत्रित किया जा सकता है!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

किसी भी क्षेत्र में खान-पान केवल पसंद का सवाल नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, भूगोल, सामाजिक जीवन और परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जब किसी धार्मिक गुरु, प्रतिष्ठान या शासन की ओर से किसी क्षेत्र के लोगों को नसीहत या निर्देश दिया जाता है कि वे किसी खास पर्व या अवसर पर मांसाहार से दूर रहें, तो बहस केवल खान-पान तक सीमित नहीं रहती। सवाल उठता है कि क्या किसी समाज की सदियों पुरानी खानपान की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर किसी क्षेत्र की अपनी परंपरा को दूसरी धार्मिक जीवन-पद्धति के अनुरूप ढालने की कोशिश उचित है? इस सवाल की गूंज इन दिनों पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर से पहले सुनाई दे रही है। यहां दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का सबसे बड़ा उत्सव भी है।

हाल में एक धार्मिक गुरु ने पश्चिम बंगाल में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान देवी की प्रतिमा के आसपास मांसाहारी भोजन नहीं बेचने का आग्रह किया है। इसके बाद राज्य में तीखी बहस छिड़ गई है। एक हिंदू संगठन की ओर से भी इससे पहले दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास मांसाहारी भोजन को लेकर नसीहत दी गई थी। हालांकि बाद में संगठन ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत खानपान पर प्रतिबंध लगाना नहीं था। इस बहस को समझने के लिए वर्तमान राजनीति से पीछे जाना होगा। किसी भी क्षेत्र के पारंपरिक भोजन का संबंध उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा होता है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तालाब और जलाशय इस क्षेत्र में मछली की उपलब्धता का बड़ा स्रोत रहे हैं। वहां मछली केवल रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि विवाह, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक अवसरों पर भी उसका प्रतीकात्मक महत्त्व है। इसलिए 'माछ-भात' को बंगाली पहचान से जोड़ना केवल आधुनिक मुहावरा नहीं है।

पश्चिम बंगाल में खान-पान की संस्कृति केवल मछली खाने तक सीमित नहीं है। वहां भोजन को लेकर बहुत विविधता रही है। राज्य में वैष्णव परंपरा की सात्त्विक और शाकाहारी भोजन की भी मजबूत धारा रही है। दूसरी तरफ शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में भी मछली एवं मांस का विशेष महत्त्व रहा है। इस कारण बंगाल के धार्मिक जीवन को केवल शाकाहार या मांसाहार के एक खांचे में रखना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। दुर्गा पूजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां देवी को फल, मिठाई और शाकाहारी भोग अर्पित किया जाता है, तो दूसरी तरफ शाक्त परंपरा के ऐसे केंद्र भी रहे हैं, जहां पशुबलि और मांसाहारी भोग का धार्मिक संदर्भ मिलता है। यानी राज्य में देवी की उपासना का एक ही खाद्य-संहिता वाला माडल नहीं रहा है।

किसी मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान में विशेष भोजन की परंपरा का होना यह साबित नहीं करता कि हर भक्त के लिए वही भोजन अनिवार्य है। बंगाल की धार्मिक परंपरा की खूबसूरती इसी सह-अस्तित्व में है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस जटिलता को समझने का महत्त्वपूर्ण संदर्भ देता है। उनके जीवन में

भोजन को लेकर कठोर साधना और व्यक्तिगत अनुशासन के उदाहरण मिलते हैं। दक्षिणेश्वर में उनके शुरुआती दिनों के विवरण बताते हैं कि भोजन के मामले में वे बेहद सावधान थे और कई बार स्वयं भोजन पकाते थे। मगर रामकृष्ण परमहंस को पश्चिम बंगाल की पूरी खानपान संस्कृति के विरुद्ध खड़ा

> देश की परंपराओं में भोजन को लेकर विविधता मौजूद रही है, ऐसे में सवाल है कि किसी एक क्षेत्र की भोजन संस्कृति को पूरे देश के लिए धार्मिक मानक बना देना कितना उचित है? किसी साधु-संत या धार्मिक गुरु की ओर से अपने अनुयायियों को संयम, सात्विक या किसी विशेष भोजन से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस सलाह का पालन भी कर सकता है। समस्या तब पैदा होती है, जब व्यक्तिगत या संप्रदायगत आचार-व्यवहार को किसी पूरे समाज के लिए सांस्कृतिक निर्देश की तरह पेश किया जाने लगे। किसी समाज की भोजन संस्कृति को उसकी आस्था की अंतिम परीक्षा बना देना भारतीय परंपरा की विविधता के दायरे को सीमित करने का प्रयास ही कहलाएगा।

कर देना भी ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। उनके संवादों में भोजन को आध्यात्मिकता का अकेला पैमाना नहीं माना गया। उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मूल केंद्र मन, साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण था। रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के संबंधों में भी भोजन को लेकर एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग मिलता है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में भोजन की बाहरी शुद्धता से अधिक मन की अवस्था को महत्त्व दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि किसी व्यक्ति का मन ईश्वर में स्थिर है, तो तथाकथित निषिद्ध भोजन भी उसकी आध्यात्मिकता को नष्ट नहीं करता।

स्वामी विवेकानंद के विचार इस बहस को और अधिक स्पष्ट करते हैं। उन्होंने भोजन को लेकर एक संवाद में कहा था कि शरीर और समाज की परिस्थितियों को देखते हुए मांसाहार अपने आप में आध्यात्मिक पतन का प्रमाण नहीं है। उन्होंने उस समय भारत में शक्ति, स्वास्थ्य और सक्रियता की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी संवाद में उन्होंने यह भी कहा कि जब मनुष्य में उच्चतम सात्विक अवस्था विकसित होती है, तब मांसाहार की इच्छा स्वाभाविक रूप से समाप्त हो सकती है। यानी विवेकानंद का तर्क दो स्तरों पर था- आहार व्यक्ति की आवश्यकता और अवस्था से जुड़ा विषय है और आध्यात्मिक उन्नति को केवल थाली देखकर तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने लेखन में बंगाल के भोजन का उल्लेख करते हुए चावल, दाल, सब्जियों के साथ मछली और मांस के इस्तेमाल को भी दर्ज किया। उनके मुताबिक, अलग-अलग भारतीय क्षेत्रों की भोजन परंपराएं वहां की स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध खाद्य पदार्थों से बनी हैं।

यह तथ्य मौजूदा सवाल को समझने में महत्त्वपूर्ण है। यदि भारत की धार्मिक परंपराओं में भोजन को लेकर इतनी विविधता स्वयं मौजूद रही है, तो किसी एक क्षेत्र की भोजन संस्कृति को पूरे देश के लिए धार्मिक मानक बना देना कितना उचित है? किसी साधु-संत या धार्मिक गुरु की ओर से अपने अनुयायियों को संयम, सात्विक या किसी विशेष भोजन से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस सलाह का पालन भी कर सकता है। समस्या तब पैदा होती है, जब व्यक्तिगत या संप्रदायगत आचार-व्यवहार को किसी पूरे समाज के लिए सांस्कृतिक निर्देश की तरह पेश किया जाने लगे। धर्म का काम आस्था को दिशा देना हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज में हर नागरिक के खान-पान को लेकर अंतिम निर्णय उसी का होना चाहिए। जब बात किसी क्षेत्र की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा की हो, तब उसके स्थानीय इतिहास और सामाजिक संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी है।

पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा इसलिए भी राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि राज्य में धर्म और सांस्कृतिक पहचान पहले से ही चुनावी सियासत के केंद्र में रहे हैं। वर्ष 2026 की दुर्गा पूजा पहली ऐसी बड़ी पूजा है, जब राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे समय में मछली-मांस केवल भोजन का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह इस बड़े राजनीतिक प्रश्न से जुड़ जाता है कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान कैसी होगी और उसे कौन परिभाषित करेगा। किसी भी राज्य या क्षेत्र को यह बताने की जरूरत नहीं कि उसका खान-पान कैसा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की अपनी परंपरा इतनी पुरानी, विविध और समृद्ध है कि वह शाकाहार और मांसाहार दोनों को अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अलग-अलग रूपों में जगह देती रही है। ऐसे में किसी समाज के खान-पान को उसकी आस्था की अंतिम परीक्षा बना देना भारतीय परंपरा की विविधता के दायरे को सीमित करने का प्रयास ही कहलाएगा।

सह-अस्तित्व का पाठ

लोकेंद्र सिंह कोट

अगर किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठना हो, तो सबसे पहले अपने भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। तब वृक्ष बोलता हुआ महसूस होगा। उसकी शाखाओं पर फूल हैं, पत्तियां हैं, नई कोंपलें हैं और कहीं कोई पीली पत्ती चुपचाप झरने की प्रतीक्षा कर रही है। एक ही वृक्ष पर जीवन के इतने रूप साथ-साथ मौजूद हैं, मगर किसी में दूसरे जैसा बनने की हड़बड़ी नहीं। पत्ती फूल बनने के लिए व्याकुल नहीं और फूल पत्ती की हरियाली से ईर्ष्या नहीं करता। नई कोंपल पुरानी पत्ती को तुच्छ नहीं समझती और सूखी पत्ती नई कोंपल का रास्ता रोकने के लिए शाखा से चिपकी नहीं रहती। यह दृश्य मनुष्य के लिए एक पाठ है कि सह-अस्तित्व का अर्थ समानता नहीं, अपनी भूमिका की स्वीकृति है।

मनुष्य ने प्रकृति से घर बनाना सीखा, खेती सीखी, औषधियां बनाना सीखा, ऋतुओं को समझा और संसाधनों का उपयोग करना जाना। मगर शायद वह नहीं सीख पाया कि भिन्न होकर भी साथ कैसे रहा जाए। आधुनिक समाज की विडंबना यही है कि उसने विविधता का उत्सव तो खूब मनाया, मगर व्यवहार में समानता के एक ही सांचे को आदर्श बना लिया। सुंदरता का एक मानक है, करिअर की एक दौड़ है और जीवन को सफल बनाने के लिए उपलब्धियों की लंबी सूची है। जो इस दौड़ में आगे है, वह आदर्श है, जो पीछे रह गया, वह अपने जीवन पर संदेह करने लगता है।

फूल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह पत्ती से अधिक सुंदर है। पत्ती इसलिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि उसके हिस्से में प्रशंसा कम आती है। वनस्पति-विज्ञान की भाषा में पत्तियां प्रकाश-संश्लेषण के जरिए पौधे के लिए ऊर्जा तैयार करती हैं, जबकि फूल प्रजनन की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। यानी जिसे हम सुंदरता का प्रतीक मानते हैं और जिसे केवल पृष्ठभूमि समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, दोनों मिलकर वृक्ष का जीवन पूरा करते हैं। समाज में भी ऐसा ही है। मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखता है, मंच तैयार करने वाला नहीं। पुरस्कार पाने वाला दिखता है, पर वर्षों तक उसके काम को व्यवस्थित करने वाले हाथ नहीं। दृश्य उपलब्धि को मूल्य और अदृश्य श्रम को स्वाभाविक मानने की यह प्रवृत्ति सामाजिक संतुलन के लिए सही नहीं है।

समस्या तब पैदा होती है, जब प्रेरणा आत्मविकास का साधन न रहकर आत्म-अस्वीकृति का कारण बन जाए। हम किसी की सफलता देखकर यह पूछने लगते हैं कि हम उसके जैसे क्यों नहीं हैं। किसी की भाषा, जीवनशैली, पहनावा, करिअर, घर या सामाजिक प्रतिष्ठा हमें जिंदगी के प्रति असंतुष्ट करने लगती है। धीरे-धीरे अपने जीवन को जीना छोड़कर दूसरे से नकल करने लगते हैं। एक दीपक से दूसरा दीपक जल सकता है, मगर दूसरी लौ पहली की प्रतिलिपि नहीं होती। यही प्रेरणा और नकल के बीच का फर्क है। प्रेरणा भीतर की क्षमता को जगाती है, नकल अपनी पहचान को दबाती है। नदी बादलों से जल लेती है, पहाड़ों से दिशा पाती है और धरती से रास्ता, मगर अंततः अपना मार्ग स्वयं बनाती है।

सोशल मीडिया ने तुलना को हमारी जेब में रख दिया है। हर दिन हमें दूसरों के जीवन के चमकदार हिस्से दिखाई देते हैं। मगर, उनकी असुरक्षाएं, असफलताएं, संघर्ष और अकेलापन नहीं दिखते। दूसरी ओर हम अपने जीवन को उसकी पूरी जटिलता से जानते हैं। नतीजा यह होता है कि दूसरे का जीवन हमसे बेहतर दिखने लगता है। तुलना की यह आदत आत्मसम्मान को खा सकती है। इसलिए आत्मस्वीकृति कोई आत्ममुग्धता नहीं है। अपने जैसा बने रहने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति आलोचना से बच जाए या अपनी कमियों को मौलिकता का नाम दे। दूसरों से सीखना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य स्वयं को मिटाना नहीं, बेहतर बनाना होना चाहिए।

वृक्ष की पत्ती अलग है, लेकिन शाखा से जुड़ी है। यही स्वस्थ सह-अस्तित्व का सूत्र है। असहमति को शत्रुता मानना और भिन्नता को विद्रोह समझना किसी भी व्यवस्था को अंततः जड़ बना देता है। संगीत इसका उदाहरण है। अगर बांसुरी, तबला और सितार एक ही ध्वनि निकालने लगें, तो संगीत नहीं बचेगा। संगीत इसलिए बनता है, क्योंकि अलग-अलग वाद्य अपनी अलग आवाज के साथ एक साझा लय में शामिल होते हैं। प्रकृति हमें सफलता और विफलता का अर्थ भी समझाती है। पत्ती हमेशा हरी नहीं रहती। वह पीली पड़ती है, सूखती है और झर जाती है। मगर उसका झरना व्यर्थ नहीं होता। मिट्टी में मिलकर वह आने वाली कोंपलों को पोषण देती है। मनुष्य के जीवन में भी हर समय मंच पर खड़े रहने का अवसर नहीं मिलता। परिपक्वता इसी में है कि हर हाल में मनुष्य अपनी गरिमा बचाए रखे।

हमारी समस्या यह भी है कि हमने योगदान की जगह प्रसिद्धि को सफलता का पैमाना बना लिया है। जो दिखता है, उसे मूल्यवान मानते हैं, जो चुपचाप जीवन को संभव बनाता है, उधर ध्यान नहीं देते। जबकि किसी बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करने वाला शिक्षक, कठिन समय में साथ खड़ा मित्र, परिवार को संभालने वाला सदस्य या किसी व्यवस्था को बिना श्रेय सुचारु रखने वाला व्यक्ति शायद किसी पुरस्कार से अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा होता है। आखिर जीवन का हिसाब किससे होगा? इस बात से कि हम कितने प्रसिद्ध हुए, कितनों से आगे निकले या कितने लोगों जैसे बन पाए? शायद नहीं। असली प्रश्न यह होना चाहिए कि हमारे भीतर जो संभावना थी, उसे हमने कितना विकसित किया। अपने हिस्से की रोशनी कितनी बढ़ाई और दूसरों के लिए कितनी जगह छोड़ी। प्रकृति का संदेश इसलिए सीधा है- दूसरों से सीखिए, मगर उनकी प्रतिलिपि मत बनिए। साथ चलिए, मगर अपनी चाल मत भूलिए। दूसरे की चमक का सम्मान कीजिए, मगर अपनी रोशनी को कमतर मत समझिए।

दुनिया मेरे आगे

> फूल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह पत्ती से अधिक सुंदर है। पत्ती इसलिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि उसके हिस्से में प्रशंसा कम आती है। वनस्पति-विज्ञान की भाषा में पत्तियां प्रकाश-संश्लेषण के जरिए पौधे के लिए ऊर्जा तैयार करती हैं, जबकि फूल प्रजनन की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं।

शिक्षा की चुनौतियां

दिल्ली को शिक्षा का केंद्र बनाने की जो महत्त्वाकांक्षा व्यक्त की जा रही है, क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या भविष्य में जमीनी हकीकत भी बन पाएगी? वास्तव में किसी शहर को शिक्षा का केंद्र बनने के लिए क्या सिर्फ अधिक से अधिक कालेज, विश्वविद्यालय खोल देना ही पर्याप्त है? केवल विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने की क्षमता विकसित करने से ही यह संभव हो पाएगा! यहां के उच्च शिक्षा संस्थानों में जितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष दाखिला लेते हैं, जब उनके लिए ही सरकारी छात्रावास मुहैया नहीं हो पाता है, तो इस तरह की महत्त्वाकांक्षा का क्या मतलब रह जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जिन निजी छात्रावासों में विद्यार्थी रहते हैं, वहां पर भी सुरक्षा और सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सवाल सिर्फ छात्रावास का नहीं है, बल्कि रोजगार से जुड़ी शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करने की पहल भी होनी चाहिए। ये सभी मुद्दे दिल्ली को शिक्षा का केंद्र बनने में बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि घोषणाओं को जमीन पर उतरने के लिए ठोस उपाय किए जाएं।

- अमोघ क्रांति, प्रयागराज, उप्र

सुरक्षा में लापरवाही

'तंत्र की जर्जरता' (संपादकीय, 8 सितंबर) पढ़ा। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में अवैध और असुरक्षित इमारतों की संख्या बढ़ी है। दुर्भाग्य से इनमें बिना रोक-टोक पीजी चलाए जा रहे हैं। इनमें रहने वाले युवा असमय हादसों के शिकार हो रहे हैं। उनको जोखिम भरी इमारतों के छोटे-छोटे कमरों में ठहराया जाता है। 'पेइंग गेस्ट' के नाम पर रहने वाले विद्यार्थियों और अन्य लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके उन्हें ज्यादा किराया भी देना पड़ता है। इन इमारतों की हालत भी काफी जर्जर रहती है। इस तरह एक दिन उनके सपने बिखर जाते हैं। दिल्ली में सत्य निकेतन जैसे कुछ हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर क्यों हर बार खानापूरी कर मामले को दबा दिया जाता है। यह निराशाजनक ही है कि जर्जर होती इमारतों को लेकर स्थानीय निकायों की ओर से समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है।

- एमएम राजावत राज, शाजापुर

संतुलन के बीच

'संभावनाओं के मोर्चे' (संपादकीय, 12 सितंबर) पढ़ा। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ संगठन अब कई देशों में विस्तारित हो चुका है। भारत में शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ, जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध, व्यापारिक तनाव, बदलते भू-राजनीतिक तनावों से गुजर रही है। बहरहाल, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की कूटनीतिक क्षमता सामने आई। पश्चिम एशिया में तनाव, रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध, अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा तथा विश्व व्यापार में संरक्षणवाद ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है। ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी शक्ति में इजाफा तो किया है, मगर साथ ही सदस्य देशों में मतभेद भी बढ़े हैं। एक तरफ चीन और रूस वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन चाहते हैं, वहीं भारत, अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहता है।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम, हरियाणा

बदलती मानसिकता

एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में हाल ही में एक युवा दंपति से बच्चों के संबंध में सवाल पूछा गया। दोनों इंजीनियर हैं और अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वे 'डिंक' जीवनशैली अपना रहे हैं। 'डिंक' ('डबल इनकम, नो किड्स') यानी दोहरी आय, लेकिन संतान नहीं। बड़े शहरों में उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम युवाओं के बीच यह सोच धीरे-धीरे बढ़ रही है। निश्चित रूप से संतान का निर्णय प्रत्येक दंपति का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब समाज के शिक्षित, सक्षम और जिम्मेदार वर्ग का एक हिस्सा संतानोत्पत्ति से दूरी बनाने लगे, तो इसके दूरगामी सामाजिक प्रभावों पर विचार करना जरूरी है। लगातार घटती जन्मदर से भविष्य में युवा आबादी का अनुपात कम और वृद्ध आबादी का अनुपात अधिक हो सकता है। इससे कार्यबल, सामाजिक सुरक्षा और परिवार व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

संवाद

जनसत्ता | 15 सितंबर, 2026

शौर्य

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों के तहत इटली के लाइवर्नो तट पर पहुंचा भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आइएनएस सुदर्शिनी।

बोल

मैंने हाल में पुतिन से बातचीत के बाद जेलेंस्की से बात की है। जेलेंस्की को रूस में डीजल ईंधन ठिकानों को निशाना बनाना बंद करना होगा, क्योंकि इससे डीजल ईंधन की कमी हो रही है। *– डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति*

बोल

बांग्लादेश भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। हमें भारत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से बाहर निकलना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। *– हुमायूं कबीर, बांग्लादेश के विदेश राज्यमंत्री*

सम-सामयिक

दवा परीक्षण : चिप व कंप्यूटर माडल के इस्तेमाल की तैयारी

जनसत्ता संवाद

दवा बनाने की दुनिया में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब वैज्ञानिक जानवरों पर प्रयोग करने के बजाय चिप और कंप्यूटर माडल में दवाओं को परखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जरूरत हुई तो दान किए गए इंसानी शरीर के छोटे अंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में इस नए तरीके को हरी झंडी मिल चुकी है।

दवा खोज और सुरक्षा परीक्षण का वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 2024 की एक समीक्षा के अनुसार, जानवरों पर परीक्षण किए गए केवल पांच फीसद प्रयोगों को ही इंसानों के उपयोग के लिए मंजूरी मिल पाती है। हालांकि लंबे समय तक अध्ययन करने पर यह आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन यह अध्ययन दिखाता है कि जानवरों पर परीक्षण के नतीजे इंसानों पर सटीक नहीं बैठते। 'न्यू अप्रोच मैथडोलाजीज' के बढ़ते प्रभाव के साथ, दुनिया भर के नियामक और दवा कंपनियां इंसानों के अनुकूल जैविक माडल प्रणालियों को अगली पीढ़ी की तकनीक के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रही हैं।

पिछले दो दशकों में, स्टेम-सेल आधारित माडल जैसे आर्गेनाइड्स, आर्गन-आन-चिप्स और डेटा-संचालित कंप्यूटेशनल माडल पारंपरिक पशु परीक्षण के विकल्प और एक बेहतर पूरक के रूप में उभरे हैं। इन्हीं तकनीकों को सामूहिक रूप से नैम्स कहा जाता है। अपने उपयोग और तरीके के आधार पर ये तकनीकें दवा परीक्षण की पुरानी चुनौतियों की तुलना में इंसानों के लिए अधिक प्रासंगिक, तेज, आसान और कम खर्चीली साबित हो रही हैं। हालांकि, बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद, भारतीय उद्योग नैम्स को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं। इसका मुख्य कारण विस्तृत मार्गदर्शिका, सत्यापन प्रक्रियाओं, प्रदर्शन मानकों और स्वीकृति मानदंडों की कमी है। भारतीय नियामक संस्थाएं नैम-आधारित मूल्यांकनों की दिशा में हो रहे बदलाव का एक सक्रिय हिस्सा रही हैं।

वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों की निरंतर वकालत के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश के भीतर सौंदर्य प्रसाधनों (कास्मेटिक्स) के पशु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक संशोधन प्रकाशित किया, जिसने भारत में पशु परीक्षण को कम करने का पहला बड़ा कदम उठाया और नवीन वैज्ञानिक प्लेटफार्मों का रास्ता साफ किया।

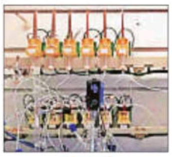

संभावनाएं

भारत में स्पष्ट नियम, लगातार फंड और अच्छा बुनियादी ढांचा मिले, तो दवा कंपनियों और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे भारत सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि खुद नई तकनीकों का नेतृत्व करेगा। सही तालमेल और सहयोग से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और मानव-केंद्रित दवा विकास के क्षेत्र में दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

हाल ही में, 'न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स' नियमों में 2023 का संशोधन नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मानव-केंद्रित सेल-आधारित परीक्षणों, आर्गन-चिप्स, माइक्रोफिजियोलाजिकल सिस्टम, कंप्यूटेशनल माडलिंग और अन्य मानव जीव विज्ञान-आधारित तरीकों को गैर-क्लिनिकल परीक्षण विधियों के रूप में अधिकृत करता है। इन प्रगतियों के बावजूद, पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण भारत में नैम्स का उपयोग अभी भी पिछड़ा हुआ है।

ये तकनीक पशु माडलों का सीधा विकल्प नहीं हैं। प्रत्येक को एक विशिष्ट उपयोग के लिए प्रमाणित किया जाता है, जैसे कि लिवर टाक्सिसिटी के आकलन के लिए विशेष रूप से लिवर-आन-चिप। इसलिए इसे अपनाने की प्रक्रिया धीरे-धीरे होने की उम्मीद है, जिसमें नैम्स का उपयोग पूर्ण स्वीकृति की दिशा में विश्वास बनाने के लिए पारंपरिक परीक्षणों के साथ किया जाएगा।

लंबे समय तक अध्ययन करने पर यह आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन यह अध्ययन दिखाता है कि जानवरों पर परीक्षण के नतीजे इंसानों पर सटीक नहीं बैठते। 'न्यू अप्रोच मैथडोलाजीज' के बढ़ते प्रभाव के साथ, दुनिया भर के नियामक और दवा कंपनियां इंसानों के अनुकूल जैविक माडल प्रणालियों को अगली पीढ़ी की तकनीक के रूप में अपनाने की ओर बढ़ रही हैं।

शोध

जलवायु आपदा : 17 करोड़ बच्चों की पढ़ाई छूटी

जनसत्ता संवाद

बाढ़, भीषण गर्मी और तूफान – जलवायु आपदाओं के कारण पिछले साल दुनियाभर में 17.1 करोड़ बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, इनमें 2.6 करोड़ से अधिक यानी 15 फीसद बच्चे भारतीय थे।

आपदाओं के कारण कहीं स्कूल बंद करने पड़े, कहीं कक्षाएं स्थगित हुई और कहीं बच्चों को वापस घर लौटना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी रिपोर्ट 'लर्निंग इंटरप्टेड : ग्लोबल स्नैपशाट आफ क्लाइमेट-रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस इन 2025' में 106 देशों और क्षेत्रों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती जलवायु आपदाएं अब केवल खेतों, घरों और सड़कों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को भी प्रभावित कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर में कम से कम 17.1 करोड़ विद्यार्थी, यानी हर 10 में से एक बच्चे की पढ़ाई जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण प्रभावित हुई। इनमें अकेले भारत के करीब 2.61 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। इसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु आपदाओं से प्रभावित हर 100 विद्यार्थियों में करीब 15 भारतीय थे।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी रिपोर्ट 'लर्निंग इंटरप्टेड : ग्लोबल स्नैपशाट आफ क्लाइमेट-रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस इन 2025' में 106 देशों और क्षेत्रों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। बढ़ती जलवायु आपदाएं बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को भी प्रभावित कर रही हैं। 2025 में दुनियाभर में कम से कम 17.1 करोड़ विद्यार्थी, यानी हर 10 में से एक बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हुई। इनमें भारत के करीब 2.61 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं।

(फाइल फोटो)

भारत के लिए यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यहां प्रभावित विद्यार्थियों की सबसे बड़ी संख्या के पीछे दर्ज जलवायु खतरा तूफान रहा। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि जलवायु संकट अब केवल मौसम का संकट नहीं रह गया है, यह बच्चों की कक्षा, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य का भी संकट बनता जा रहा है। तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ या कई दिनों तक चलने वाली लू बच्चों की पूरी पढ़ाई की लय बिगाड़ सकती है। स्कूलों में पानी भरने से लेकर इमारतों को नुकसान पहुंचने तक, जलवायु आपदाएं शिक्षा को कई तरह से प्रभावित करती हैं।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2025 के दौरान वैश्विक स्तर पर तूफान सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित करने वाला जलवायु खतरा रहा। इसकी वजह से करीब 10.9 करोड़ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। वहीं बाढ़ से कम से कम सात करोड़ और लू से करीब पांच करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा।

इन आपदाओं की वजह से कई जगह स्कूल बंद करने पड़े, तो कहीं पढ़ाई आनलाइन करनी पड़ी। कई बच्चों की स्कूल में उपस्थिति कम हुई और पढ़ाई के घंटे घट गए। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लाखों बच्चे मौसम की ऐसी ही मार झेल रहे हैं, जिसमें एक आपदा उनके स्कूल का दरवाजा बंद कर देती है और दूसरी आपदा उनके भविष्य पर दस्तक देती है।

यूनिसेफ ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में बच्चों के भविष्य पर मंडराती चुनौतियों को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक बच्चों के लिए भीषण लू का सामना करने का जोखिम आठ गुणा बढ़ जाएगा। 2000 से तुलना करें तो अगले 26 वर्षों में बाढ़ का खतरा भी तीन गुणा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब 2050 के दशक में पर्यावरण और जलवायु संबंधी परिस्थितियां और बदतर हो जाएंगी। तब 2000 की तुलना में दोगुने बच्चे जंगलों में धधकती आग का सामना करने को मजबूर होंगे। जलवायु आपदाओं का असर अमीर और कमजोर देशों में एक समान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित 17.1 करोड़ विद्यार्थियों में से करीब 75 फीसद बच्चे निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। इन देशों में स्कूलों को जलवायु आपदाओं से सुरक्षित रखने, बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और आपदा के बाद शिक्षा व्यवस्था को जल्द बहाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते।

विश्व परिक्रमा

पाकिस्तान : बच्चों से हिंसा एवं दुर्व्यवहार के मामले बढ़े

जनसत्ता संवाद

पाकिस्तान में इस वर्ष के शुरुआती छह महीनों में बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के 1,900 से अधिक मामले सामने आए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की उपाध्यक्ष एवं सांसद शेरी रहमान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक बयान जारी कर इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इन मामलों का स्तर बेहद चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि जनवरी से जून 2026 के बीच बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के 1,914 मामले दर्ज किए गए।

रहमान ने कहा, 'बच्चों को निशाना बनाने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, 'हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी सुरक्षा उनके परिवारों, समुदायों और सरकार को करनी चाहिए लेकिन इसके बजाय वे हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इन घटनाओं से निपटने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। रहमान ने कहा कि कुल मामलों में से 80 फीसद मामले पंजाब प्रांत से हैं और ये बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। तैंतालीस फीसद मामलों में आरोपी पीड़ितों के परिचित थे, जबकि करीब 45 फीसद घटनाएं बच्चों के अपने घरों के भीतर हुईं। उन्होंने कहा, 'घर को बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। जब बंद दरवाजों के पीछे ही दुर्व्यवहार होता है तो हमें परिवारों और समुदायों के भीतर निगरानी, सुरक्षा उपायों और जवाबदेही को लेकर बेहद गंभीर सवाल पूछने होंगे।'

जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, उनके अनुसार 57 फीसद मामले शहरी क्षेत्रों और 43 फीसद ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए। रहमान ने कहा कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किसी एक वर्ग या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की समस्या है। अब अधिक मामले पुलिस के संज्ञान में आ रहे हैं और तेजी से सुनवाई की जानी चाहिए।

जानें-समझें

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

कूटनीतिक संतुलन के साथ ठोस मुद्दों पर बात

जनसत्ता संवाद

ब्रिक्स भारत की विदेश नीति का जरूरी हिस्सा है, लेकिन अकेला जरिया नहीं। इसकी असली ताकत यह है कि यह उभरते और विकासशील देशों को एक मंच पर लाता है। यहां वैश्विक व्यवस्था, विकास के लिए धन की मदद, व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और बड़े वित्तीय सुधारों पर बात होती है। भारत ब्रिक्स में है, क्वाड में भी है और अमेरिका, रूस, यूरोप तथा खाड़ी देशों के साथ भी उसके रिश्ते हैं। पहली नजर में यह विरोधाभास लग सकता है लेकिन यही भारत की विदेश नीति का तरीका है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत कूटनीति में खरा उतरता दिखा।

हर मंच से जुड़ाव का संकेत

ब्रिक्स की संरचना में काफी बदलाव आया है। 11 पूर्ण सदस्यों- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया- के साथ यह समूह अपने मूल रूप की तुलना में कहीं अधिक विविध हो गया है। एक ही संस्थागत मंच के तहत अलग-अलग राजनीतिक और रणनीतिक हितों की मौजूदगी से भारतीय अध्यक्षता के सामने खड़ी चुनौती थी कि इस लगातार बढ़ते विविध समूह को भू-राजनीतिक टकराव का बंधक बनाए बिना इसे कैसे असरदार बनाया जाए। भारत ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी गुट बनाने के पक्ष में नहीं है। भारत की विदेश नीति अब किसी एक गुट या सैन्य गठबंधन में बंधने के बजाय 'मल्टी-अलाइनमेंट' और 'मल्टी-इंगेजमेंट' (हर मंच पर जुड़ाव) की ओर बढ़ चुकी है। इसका मकसद किसी एक गुट को चुनने के बजाय स्वतंत्र फैसले की आजादी बनाए रखना है।

हमारी प्राथमिकताएं

भारत का उद्देश्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के बजाय उसमें सुधार करना है। दिल्ली ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र, आइएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की है। डिजिटल पेमेंट, सीमा पार लेन-देन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, पर्यावरण-हितैषी फंड, छोटे कारोबारियों को मदद, आपदा से बचाव और तकनीक- ये सब नई दुनिया के बड़े-बड़े दावों से कहीं ज्यादा काम की चीजें हैं, जो बताती हैं कि मिलकर काम करना कितना सफल हो सकता है। इसलिए, भारत चाहता है कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का जरिया बना रहे और साथ ही पश्चिमी देशों व संस्थानों के साथ भी रास्ते खुले रहें। यह फर्क डी-डालराइजेशन (डालर का असर घटाने) की बहस में बहुत मायने रखता है।

भारत की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय बैठकों और ट्रैक-एक तथा ट्रैक- दो वार्ताओं की श्रृंखला के माध्यम से सदस्य देश एक साथ आए हैं, जिससे इन प्राथमिकताओं में सहयोग आगे बढ़ा है। इसलिए, ब्रिक्स का महत्व केवल समूह के विस्तार में नहीं, बल्कि इस विविधता को टिकाऊ और व्यावहारिक सहयोग में बदलने में निहित है। *– मीरा शंकर, पूर्व राजदूत*

इस बार चुनौती अधिक व्यापक रही। जटिल वैश्विक माहौल में तालमेल बैठाने के साथ ही आपूर्ति शृखला, वित्त, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और सतत विकास जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों को लेकर सहमति बनाना अहम रहा। सदस्य देशों में व्यापक सहयोग दिखा। *– टीएस तिरुमूर्ति, पूर्व राजदूत*

प्राथमिकताओं का विस्तार

ब्रिक्स की कई प्राथमिकताएं अब भी एक जैसी बनी हुई हैं। वैश्विक व्यवस्था में सुधार, विकासशील देशों को बड़ा प्रतिनिधित्व देना और वैश्विक की आवाज मजबूत करना – 2021 में भी अहम थे और आज भी हैं। हाल के वर्षों में आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं, भू-राजनीतिक तनावों, ऊर्जा संकट और तकनीकी बदलावों जैसे झटकों ने दिखाया है कि कैसे एक क्षेत्र की कमजोरी दूसरे क्षेत्र को तुरंत प्रभावित करती है। 2021 में भारत की अध्यक्षता महामारी के बीच पांच सदस्यों के बीच सहयोग बनाए रखने पर केंद्रित थी। पिछले एक साल में, भारत ने मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के शामिल होने के साथ बड़े समूह की अध्यक्षता की है, जिससे ब्रिक्स की आबादी, भूगोल और अर्थव्यवस्था का दायरा काफी बढ़ गया है। यह विस्तार अलग-अलग आर्थिक ढांचे, विदेश नीति और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं वाले देशों को साथ लाता है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के ऊर्जा उत्पादक तथा विनिर्माण केंद्र शामिल हैं।

अलग समूह, अलग मकसद

भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का मतलब दुनिया से कटना नहीं मानता। उसके लिए इसका अर्थ किसी पर निर्भर हुए बिना एक साथ कई बड़ी ताकतों से जुड़ना है। क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन अलग-अलग मकसद पूरे करते हैं। भारत के लिए असल बात यह नहीं कि ब्रिक्स नई विश्व व्यवस्था का दावा करे, बल्कि यह है कि वह काम का सहयोग दे और विकासशील देशों को आगे बढ़ाए।

चीन पर व्यावहारिक सोच

चीन के मामले में भी भारत व्यावहारिक सोच अपनाता है। ब्रिक्स भारत को ऐसा मंच देता है, जहां वह बाकी बड़ी ताकतों के साथ मिलकर चीन से बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को अपने बड़े रणनीतिक हितों से समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत ने भोजन, खाद, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक तक पहुंच, जलवायु फंड, विकास के लिए पैसा – इस मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रखी। हर बड़े मुद्दे पर एक सुर में बोलने की कोशिश करने वाला ब्रिक्स अपनी एकजुटता बनाए रखने में मुश्किल महसूस कर रहा था। लेकिन घोषणापत्र पर सहमति बनाकर भारत ने अपना मकसद पा लिया।

– प्रस्तुति : दीपक रस्तोगी

व्यक्तित्व

प्रीति : नई तकनीक की मुक्केबाज, एशियाई खेल में देंगी कड़ी चुनौती

जनसत्ता संवाद

मुक्केबाज प्रीति पवार एशियाई खेल में कई प्रतियोगियों के लिए कड़ी चुनौती मानी जा रही हैं। 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा ओलंपिक जैसी है। कई जाने-माने और अनुभवी खिलाड़ी क्रंच चैंपियनशिप चैंपियन और विश्व नंबर तीन प्रीति पवार को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इनमें तीन बार की विश्व चैंपियन और तोक्यो ओलंपिक (51 किलोग्राम) की कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे की हुआंग शियाओ-वेन, पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता उत्तर कोरिया की पांग चोल-मी और कांस्य पदक विजेता कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे (51 किलोग्राम) शामिल हैं। इसके अलावा, 2023 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वियतनाम की एनखजारगल मुंख्तसेत्सेग और फुर्तीली चीनी खिलाड़ी जुआन झाओ भी हैं।

हालांकि, प्रीति के पास आत्मविश्वास से भरे रहने के कारण हैं। वह एकमात्र मुक्केबाज हैं जिन्होंने एक साल में वेन को दो बार हराया है, उन्होंने इस साल एशियाई चैंपियनशिप में चोलमी और एनखजारगल को हराया है। उन्होंने रोमानिया की 2022 विश्व रजत पदक विजेता लैक्रैमियोरा पेरिजोक और इटली की विश्व नंबर छह सिरीन चाराबी पर भी जीत हासिल की है, लेकिन उनका ध्यान उन बड़े नामों पर नहीं है जिनसे उनका सामना हो सकता है। वे हांगझोऊ खेलों से मिले सबक पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीता था। वे कहती हैं, 'चांग युआन के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली हार ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया।'

वर्ष 2026 में एशियाई खेलों में भाग लेने से पहले वह अपराजित थीं और तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता हुआंग शियाओ वेन और पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता आइएम ऐजी के बाद विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थीं। उनके 1015 रैंकिंग अंक थे। वे ग्लासगो राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उलानबटार एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2025 विश्व कप फाइनल में भी स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। वे कहती हैं, 'युआन फाइनल में चोलमी से हार गई थीं और फिर उन्होंने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, सेमीफाइनल में भी उन्होंने चोलमी को ही हराया था। उस समय मैंने अपने काउंटर मूव्स के साथ-साथ बाडी स्विच पंच पर भी काम किया। मुझे हांगझोऊ में क्वार्टर फाइनल में तीन बार की विश्व पदक विजेता जैना शेकरबेकोवा पर मिली जीत भी याद है। पेरिस ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई 54 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई मुक्केबाजों का दबदबा रहा है। 2010 से अब तक एशियाई मुक्केबाजों ने पांच विश्व खिताब जीते हैं। वेन अनोखी चुनौती पेश करती हैं, क्योंकि वे पांच फीट नौ इंच की ऊंचाई के साथ सबसे लंबी हैं। जुआन उनसे एक इंच छोटी हैं, जबकि पवार की लंबाई केवल पांच फीट छह इंच है। वे कहती हैं, 'वेन लंबी मुक्केबाज हैं और वह बहुत सारे काउंटर पंच खेलती हैं। जीत ने मुझे सिखाया है कि उनके दायरे से बाहर रहना है और अपने शरीर का इस्तेमाल करके पंचों को बदलना है, साथ ही अपने काउंटर पंच भी लगाने हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

फिर खेल से खिलवाड़

फिर एक बार भारत ने क्रिकेट एशिया कप जीत लिया, पर विजेता ट्रॉफी का हाथ न आना बहुत दुखद और चिंताजनक है। मैदान में क्रिकेट की जीत हुई, पर उसे एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपने व्यवहार से हरा दिया। एक वर्ष पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की शिकायत को नजरअंदाज किया गया था और अब महिला क्रिकेट टीम की इच्छा का अनादर किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस बार विजेता टीम की ट्रॉफी लेकर नहीं भागे, पर उनके अड़ियल व बेशर्म रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। नकवी सिर्फ क्रिकेट प्रशासक ही नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। भारत के प्रति उनकी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन तब भी वह विजेता भारतीय टीम को अपने हाथों से ट्रॉफी देने के लिए मंच पर जा चढ़ते हैं। कायदा यही बोलता है कि आप खिलाड़ियों की भावना का सम्मान करें, पर नकवी इसे नाक का सवाल बना लेते हैं। यह नाक पिछले वर्ष भी कटी थी, इस वर्ष भी कटी है।

नकवी और पाकिस्तानी क्रिकेट की हठधर्मिता शर्मनाक है। दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टी-20 एशिया कप फाइनल में श्रीलंकाई टीम पर शानदार जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों को जश्न मनाने का पूरा हक था, लेकिन नकवी को भारतीयों की खुशी मंजूर नहीं है। नकवी जैसे असंवेदनशील क्रिकेट प्रशासकों का इलाज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही नहीं, विश्व क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए। ऐसी भारतीय टीम और भारतीय दर्शकों को निराश किया जा रहा है, जिनसे विश्व क्रिकेट को 80 प्रतिशत से ज्यादा कमाई होती है। इतना ही नहीं, विश्व क्रिकेट से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपने कुल बजट का 50 प्रतिशत से ज्यादा हासिल होता है। यह बात खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी स्वीकार चुके हैं कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहे, तो पाकिस्तान में क्रिकेट पर मुश्किलें मंडराने लगेंगी। ऐसे में, पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए, भारत कम से कम बहुदेशीय मुकाबलों में पाकिस्तान के साथ भाग ले रहा है, वरना भारत में इस बात के लिए भारी दबाव है कि पाकिस्तान के विरुद्ध क्रिकेट का बहिष्कार करना चाहिए। फिर भी, भारतीय भलमनसाहत को समझने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा हो, ऐसा लगता नहीं है। अतः इस बढ़ती समस्या का हल खोजना होगा।

मोहसिन नकवी जैसे असंवेदनशील क्रिकेट प्रशासकों का वाजिब इलाज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही नहीं, विश्व क्रिकेट बोर्ड को भी समय रहते सोचना चाहिए।

दरअसल, इस पूरी समस्या के पीछे पाकिस्तान की जिद है। वह सुधरना नहीं चाहता। पाकिस्तानी साजिश की ताजा मिसाल देखिए। अक्तूबर में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पाकिस्तान को फिर से ग्रे देशों की सूची में डाल सकता है। ऐसे में, अब पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने कथित तौर पर साल 2026 के लिए सबसे वांछित आतंकियों की सूची जारी की है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम भी है। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर और उसके खानदान को बड़ी हिफाजत से मेहमान की तरह पालने वाला पाकिस्तान साल 2021 से दावा करता आ रहा है कि अजहर अफगानिस्तान भाग गया है। ध्यान रहे, एफआईए की ताजा रेड बुक में 26/11 मुंबई हमलों से जुड़े 19 आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। अब इस सूची के दम पर पाकिस्तान खुद को पाक साबित करने और वैश्विक कानूनों से खिलवाड़ की कोशिश करेगा। जाहिर है, इसी खिलवाड़ का एक हिस्सा मोहसिन नकवी जैसे नेता हैं, जो क्रिकेट की चमकदार नदी में अपने हाथ धोने की साजिश बार-बार करेंगे और भारतीयों की दृढ़ता उनके आड़े आएगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले | 15 सितंबर, 1951

निराधार शिकायत

पाकिस्तान के समाचारपत्रों और रेडियो पर कुछ समय से यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक अपने को अरक्षित अनुभव कर रहे हैं और काफी संख्या में राजस्थान के जोधपुर डिवीजन के अन्तर्गत खोखरापाड़ मार्ग से पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्रचारकों का कहना है कि इस मार्ग से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों की बड़ी दयनीय अवस्था है और उन्हें भारतीय सीमा पर काफी हैरान और परेशान किया जाता है। इस विषय में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने बाकायदा भारत सरकार से लिखित शिकायत भी की थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इस शिकायत का खरा, किन्तु विस्तृत जवाब दिया है। इस जवाब से स्पष्ट हो जायेगा कि इस संबंध में पाकिस्तान की शिकायत और प्रचार कितने निराधार हैं और भारत से जो मुसलमान थोड़ी-बहुत संख्या में खोखरापाड़ के मार्ग से पाकिस्तान जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पर है। मुस्लिम अथवा अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में भारत सरकार की नीति जग-जाहिर है। वह इस देश में रहने वाले सभी लोगों को, फिर वे चाहे किसी जाति अथवा धर्म से संबंध रखते हों, देश का बराबरी का नागरिक मानती है...।

पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने खोखरापाड़ के मार्ग से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों के कुछ उदाहरणों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। भारत सरकार ने इन मामलों की अपने उच्च अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल करवाई और ज्यादतियों के आरोपों को बिल्कुल निराधार पाया। जिस समय ये ज्यादतियां होने का दावा किया जाता है, उस समय पाकिस्तान का एक कस्टम सम्पर्क अधिकारी बाड़मेर में मौजूद था। वह चाहता, तो उसी समय शिकायत कर सकता था, किन्तु उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। इसके विपरीत एक जांच के दौरान उसके स्टाफ के एक कर्मचारी ने यह स्वीकार किया कि उसके पास कोई शिकायत नहीं है और प्रवासियों के सामान की देखभाल का काम आसानी से चल रहा है। इस प्रकार पाकिस्तान की ओर से जो निराधार आरोप लगाये जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के निम्न कर्मचारियों उल्टी होती है। उनमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है।

ब्रिक्स में शांति की ओर बढ़े कदम

यहां स्कैन करें

अरविंद गुप्ता | पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ

अगर ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात में बातचीत के लिए सहमति बनती है और पुरानी दुश्मनी की दीवारें गिरती हैं, तो यह भी इस संगठन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।

अगले साल चीन में मिलने के वायदे के साथ नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का समापन हो गया, लेकिन विश्व शांति को लेकर इससे जो ध्वनि निकली है, उसका दूरगामी असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान उचित है कि महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीक को हथियार बनाने से बचना चाहिए। भू-राजनीतिक तनाव से दुनिया भर के लोगों पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों के कारण ब्रिक्स समूह के भीतर लचीलापन बढ़ाने संबंधी बातों के भी गहरे निहितार्थ हैं।

प्रधानमंत्री मोदी जब पिछले पखवाड़े शंघाई सहयोग संगठन की किर्गिस्तान बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तब उन्होंने साफ-साफ कहा था कि अंतहीन युद्ध अब खत्म होने चाहिए। भारत चाहता है कि युद्ध किसी भी कीमत पर रुकें, क्योंकि इनसे कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए दुनिया भर की नजरें ब्रिक्स के दिल्ली सम्मेलन पर टिकी थीं, क्योंकि अव्वल तो इसकी मेजबानी भारत के पास थी और दूसरी, इसमें ऐसे-ऐसे देश भी शिरकत कर रहे थे, जिनका अतीत एक-दूसरे के खिलाफ रहा है।

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। हाल-फिलहाल दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य बने हैं और पहली बार इसके मंच पर आमने-सामने थे। फरवरी में अमेरिका द्वारा इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए जाने के बाद तेहरान ने पलटवार करते हुए यूएई को भी निशाना बनाया था, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आशंकाएं थीं कि दिल्ली में शायद ही दोनों एकमत हो सकेंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि मई, 2026 में जब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब इन दोनों देशों में एकराय न हो पाने के कारण साझा घोषणा-पत्र जारी नहीं हो सका था। हालांकि, बीते कुछ समय में भारतीय राजनय की मेहनत रंग लाई और नई दिल्ली में सर्वसम्मति से घोषणा-पत्र जारी हो सका, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व सहयोग पर जोर दिया गया है।

दिल्ली घोषणा-पत्र कुल 140 पैराग्राफ का है, जिसमें 26 बिंदु अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को समर्पित किए गए हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण, मध्य-पूर्व तनाव, क्यूबा संकट, गाजा शांति-प्रयास, फलस्तीन संकट का समाधान, सूडान संकट, सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकने, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसे तमाम विषय इसमें समेटे गए हैं।

गौरतलब यह भी है कि ब्रिक्स जिन तीन स्तंभों पर मूलतः टिका है, उनमें एक है- राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग। इसका अर्थ है कि वैश्विक व क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा व आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स के सदस्य देश चर्चा करेंगे और कूटनीतिक मदद करेंगे। शेष दो हैं- आर्थिक और वित्तीय सहयोग, जिसके तहत व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, वित्त व बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं, और तीसरा है- सांस्कृतिक एवं जन-संबंधी जुड़ाव, जिसमें सदस्य देशों के नागरिकों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने, सांस्कृतिक, खेल, शिक्षा, अकादमिक सहयोग आदि को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। इन संदर्भों में नई दिल्ली घोषणा-पत्र से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं सहयोग को लेकर एक नया दरवाजा खुलता दिखता है।

यूक्रेन युद्ध की सीधी चर्चा तो घोषणा-पत्र में नहीं की गई है, पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने उनसे पूर्वी यूरोप में शांति बहाल करने के लिए मदद करने का आश्वासन दिया, जिसका पुतिन ने स्वागत किया। इसका अर्थ है कि ब्रिक्स बैठक से इतर यूक्रेन संकट के समाधान के लिए ठोस बातचीत हुई है।

रही बात ईरान युद्ध की, तो घोषणा-पत्र में इस पर गहरी चिंता जाहिर की गई है। हालांकि, सदस्य देश यही मानते हैं कि बातचीत और कूटनीति से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। इसका अर्थ है कि सभी देशों ने एक प्रकार से अपनी सैद्धांतिक स्थिति स्पष्ट कर दी है और किसी आरोप-प्रत्यारोप में उलझे बिना कूटनीति एवं बातचीत को ही समाधान का रास्ता बताया है। सच भी यही है कि हर तनाव का समाधान बातचीत है, हथियार नहीं।

यह बात समझने लायक है कि ब्रिक्स वैश्विक सुरक्षा के बड़े-बड़े मुद्दों को हल नहीं कर सकता। बेशक, विश्व की करीब आधी आबादी ब्रिक्स सदस्य देशों की है और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40 फीसदी हिस्सों पर उनका प्रतिनिधित्व है, फिर भी कुछ मुद्दे काफी जटिल हैं। इनको सुलझाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के पास है। ब्रिक्स की उपलब्धि यही है कि वह जंग में उलझे देशों को एक छत के नीचे लाने, बातचीत करने और घोषणा-पत्र जारी करने के लिए उनमें सहमति बनाने में सफल रहा।

दूसरी बात, जो लड़ाइयां अभी जारी हैं, उनका लंबा इतिहास है। ऐसे में, जब तक संबंधित देश खुद नहीं मानेंगे, तब तक इन युद्धों को रोकना मुश्किल है। ईरान और यूएई का पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान एक बड़ी बात है, पर ईरान युद्ध का हल महज एक दिन में संभव नहीं। इसी तरह, आतंकवाद पर 'शून्य सहिष्णुता' को लेकर बनी सहमति और जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले की निंदा का लंबे समय में प्रभाव पड़ेगा।

दिक्कत यह है कि ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में भी उलझे हुए हैं, जैसे भारत और चीन। यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दों की चर्चा नहीं की जाती, पर बैठक से अलग हटकर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी में जो बातचीत हुई है, उसका असर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पड़ सकता है। हालांकि, इसके लिए इन दोनों नेताओं को भविष्य में भी साथ बैठना होगा। गौरतलब है, साल 2024 के कजान ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद ही भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी।

कुल मिलाकर, यह कहना उचित है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के गंभीर प्रयास ब्रिक्स सम्मेलन में किए गए। आलोचक भले इसकी यह कहकर आलोचना करें कि इसमें कोई 'रोडमैप' नहीं दिखता, लेकिन अगर बातचीत के लिए नेताओं में सहमति बनती है और पुरानी दुश्मनी की दीवार गिरती है, तो वह भी इस संगठन की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ब्रिक्स सिर्फ समाधान का माहौल बना सकता है, और ऐसा करने में संभवतः वह सफल हुआ है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

तेलंगाना में दलित स्पीकर पर टिप्पणी से गरमाई सियासत

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना वजूद में आया। उसी समय से इसकी राजनीति में अगड़ी जातियों का दबदबा रहा है। साक्षरता दर और स्कूल में दाखिले जैसी कुछ कसौटियों पर पिछड़ी जातियों, खासकर दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है, पर सामाजिक सम्मान व सतत विकास में समुचित हिस्सेदारी दिलाने के मामले में अब भी इनके लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है।

पिछले सप्ताह तेलंगाना की राजनीति में एक शर्मनाक स्थिति सामने आई और यह सब तब हुआ, जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सत्ता में अपने 1,000 दिन पूरे करने का जश्न मना रहे थे। मुख्य विपक्षी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने इस जश्न में खलल डालने की कोशिश की, पर वह खुद एक अप्रिय स्थिति में फंस गई। दरअसल, 7 सितंबर को दो दर्जन से ज्यादा विधायक, एक दर्जन विधान पार्षद और दूसरे नेता काले कपड़े पहनकर और सरकार विरोधी पोस्टर लेकर सदन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अध्यक्ष के निर्देश पर रोके जाने के क्रम में जब उन्होंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव समेत 21 विधायकों की गिरफ्तारी के साथ ही टकराव खत्म हुआ।

बीआरएस नेताओं पर आरोप लग रहा है कि दलित विधायकों के डप्पू विरोध-प्रदर्शन के अगले दिन उन्होंने 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' किया।

बाद में, जब बीआरएस विधायकों ने सदन में यह मुद्दा उठाया, तो विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार के खिलाफ टिप्पणियां की गईं। इन अपमानजनक टिप्पणियों से दलित समुदाय से आने वाले स्पीकर भावुक हो गए। कांग्रेस नेता मोथा रोहित मुदिराज ने उन टिप्पणियों को लेकर बीआरएस विधायक टाटा मधु के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को मानसून सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि, मधु ने स्पीकर के खिलाफ अपशब्द बोलने से इनकार किया, पर साथ ही यह भी कहा कि 'अगर ऐसी कोई बात मुझसे जोड़ी गई है, तो मुझे इसका अफसोस' है। इस घटना के अगले दिन कांग्रेस ने सिद्दीपेट में बीआरएस के संस्थापक के चंद्रशेखर राव के एर्रावल्ली फार्महाउस तक मार्च की योजना बनाई। कांग्रेस के दलित नेताओं और विधायकों के एक दल ने ढोल (डप्पू) बजाकर विरोध-प्रदर्शन किया।

यह घटना उत्तराखंड के उस विवाद की याद दिलाती है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान को 'शुद्ध' किया गया था। कांग्रेस ने 'भगवा परिवार' पर दलित-विरोधी होने का आरोप लगाया, क्योंकि आरोप है कि एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने ही उस जगह पर 'शुद्धि हवन' किया था। अब बीआरएस नेताओं पर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि डप्पू विरोध-प्रदर्शन के अगले दिन बीआरएस नेताओं ने फार्महाउस पर 'शुद्धि अनुष्ठान' किया।

बहरहाल, कांग्रेस और बीआरएस में जुबानी जंग जारी है, लेकिन इससे राज्य में दलितों और पिछड़ों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आने वाला। यहां जमीनी स्तर पर बहुत कम काम हुआ है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाले 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में खुद उन्हें मिलाकर चार रेड्डी मंत्री हैं, जो लगभग 33 प्रतिशत बैठता है, जबकि रेड्डी समुदाय की आबादी महज 4.8 फीसदी है। इसकी तुलना में दलितों की आबादी 17.5 प्रतिशत है, पर उनके भी चार मंत्री और एक स्पीकर हैं।

जानकारों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से सत्ता की बागडोर प्रभावशाली जातियों के हाथों में ही रही। इसका एक बड़ा कारण पैसे की ताकत है, क्योंकि प्रभावशाली जातियों का रियल एस्टेट, निर्माण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहां तक कि सिनेमा जैसे क्षेत्र से जुड़े कारोबार पर नियंत्रण रहा है। वहीं पिछड़े समुदाय, खासकर दलित समाज खेतिहर मजदूरी या असंगठित क्षेत्र की कम वेतन वाली नौकरियों में फंसे हुए हैं। तेलंगाना में सामाजिक भेदभाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कई इलाकों में 'टू-ग्लास सिस्टम' (अलग-अलग गिलास में पानी देने की प्रथा) अभी भी प्रचलित है।

इसे पूरे प्रकरण का दिलचस्प पहलू यह है कि बीआरएस 'फेल गवर्नेंस' अभियान के जरिये तेलंगाना में कांग्रेस की छवि धूमिल करना चाहती थी, मगर अब खुद ही 'शुद्धिकरण' विवाद में फंस गई। उसने रेड्डी सरकार को घेरने का एक मौका गंवा दिया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

चिंतन क्यों अनिवार्य

एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, यह जानते हुए भी मनुष्य चिंतित क्यों होता है? मनुष्य अपनी तमाम कमियों, कमजोरियों और भूलों के बावजूद मूलतः एक दिव्य प्राणी है। जीवन में क्षणिक दुर्बलता के कारण कभी-कभी उससे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों से उसकी मूल प्रकृति नहीं बदल जाती। वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। हर मनुष्य के भीतर पूर्णता की संभावना छिपी हुई है और वह उसे प्राप्त कर सकता है।

हम आज जैसे हैं, वह हमारे बीते हुए विचारों और कर्मों का परिणाम है। इसी तरह, हमारा आने वाला जीवन इस बात से तय होगा कि हम आज क्या सोचते और करते हैं? हमारे अतीत के कर्मों ने वर्तमान को आकार दिया है और वर्तमान के विचार व कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए अतीत को लेकर निराश होने के बजाय हमें वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

हम सब अदृश्य दिव्य स्रोत से आए हैं और एक निश्चित समय के बाद उसी अदृश्य स्रोत में लौट जाएंगे। संसार की कोई वस्तु, कोई संबंध और कोई व्यक्ति हमेशा के लिए हमारा नहीं है। इसलिए किसी के चले जाने या किसी वस्तु के हाथ से निकल जाने पर अत्यधिक शोक करना भी उचित नहीं है। जब किसी का अस्तित्व ही स्थायी नहीं है, तो उसके लिए शोक क्यों किया जाए?

इसीलिए विवेकशील मनुष्य यह समझते-समझाते हैं कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है। धन, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख और सांसारिक उपलब्धियां जीवन की आवश्यकताएं हो सकती हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं। जब मनुष्य मन की प्रवृत्तियों को निरंतर बाहरी और भौतिक वस्तुओं से हटाकर ब्रह्म की ओर मोड़ता है, तब उसके भीतर एक अलग आनंद जन्म लेता है। ईश्वर का निरंतर चिंतन मनुष्य को ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति तक ले जाता है, जहां सांसारिक सुख फीके लगने लगते हैं। वैष्णव दर्शन में आध्यात्मिक आनंद की इन अवस्थाओं को दशा, भाव और महाभाव जैसे शब्दों से व्यक्त किया गया है।

क्या आध्यात्मिक अनुभूति केवल उन लोगों के लिए है, जिनका अतीत पवित्र रहा हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है।

ईश्वर का चिंतन मनुष्य को ऐसी अनुभूति तक ले जाता है, जहां सांसारिक सुख फीके लगने लगते हैं। आध्यात्मिक आनंद की इन अवस्थाओं को दशा, भाव और महाभाव कहा गया है।

साधक का अतीत चाहे कितना भी कलुषित क्यों न रहा हो, वह आध्यात्मिक साधना और ईश्वर-प्राप्ति का अधिकारी है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रत्नाकर और अंगुलिमाल जैसे उदाहरण मिलते हैं। उनका अतीत अपराधों से भरा था, पर बाद में उनका जीवन बदल गया। वे ईश्वर के महान भक्त और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। इससे यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के भीतर परिवर्तन की संभावना कभी समाप्त नहीं होती। ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग उसके लिए हमेशा खुला है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

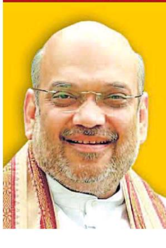

जिस ओजस्वी ज्ञान ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, उसे समाप्त करने के उद्देश्य से नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया जा सकता है, मगर लोगों की स्मृति में बसे ज्ञान को कोई समाप्त नहीं कर सकता।

अनुलोम-विलोम

गणेश उत्सव

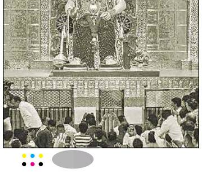

नहीं समझ सके गणेश उत्सव की सीख

हर वर्ष गणेश जी का आगमन केवल उत्सव नहीं, स्वयं से मिलने का अवसर भी होता है। गणेश चतुर्थी आस्था, आनंद और सामूहिकता का ऐसा पर्व है, जिसका अर्थ हर बार नई दृष्टि से खुलता है। गणेशजी का स्वरूप ही जीवन का गहरा दर्शन समेटे है- हाथी का मस्तक, मानव देह, एकदंत, विशाल उदर और साथ में मूषक। यह विलक्षण रूप बताता है कि जीवन की सुंदरता एकरूपता में नहीं, विविधताओं को सम्मानपूर्वक स्वीकारने में है। जब मनुष्य स्वयं को पूर्ण और सफल दिखाने की दौड़ में रहता है, तब गणेश उत्सव याद दिलाता है कि अधूरापन जीवन की सच्चाई है, कमी नहीं। अपनी कमियों को स्वीकार कर उनको आत्म-विकास की शक्ति बनाना ही वास्तविक सामर्थ्य है।

गणेश जी का वाहन मूषक भी अपने भीतर जीवन का सूक्ष्म संदेश समेटे है। चंचलता और निरंतर सक्रियता का प्रतीक मूषक आज के मनुष्य की भागती इच्छाओं का प्रतिबिंब है। यह हमें याद दिलाता है कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं, पर उनका संयम आवश्यक है। छोटी इच्छाओं और आकर्षणों पर विवेक का नियंत्रण ही मन को स्थिर रखता है। इसी तरह, मिट्टी से गणेश प्रतिमा का बनना और फिर उसी मिट्टी में विलीन हो जाना जीवन की क्षणभंगुरता और प्रकृति से हमारे अटूट संबंध का मार्मिक संदेश है। मिट्टी प्रकृति से आती है, आकार पाती है, श्रद्धा का केंद्र बनती है और अंततः प्रकृति में लौट जाती है। यह चक्र सिखाता है- परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है। फिर भी, मनुष्य धन, वस्तुओं, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को स्थायी मानकर उनसे मोह बांध लेता है। गणेश-विसर्जन केवल विदाई नहीं, आसक्ति छोड़ने की सहज आध्यात्मिक सीख है। साथ ही यह स्मरण कराता है कि प्रकृति से लिया हर संसाधन सम्मान, संवेदना और जिम्मेदारी की मांग करता है। प्रकृति का सम्मान ही हमारी जीवन-शैली का संस्कार बने।

इसी तरह, हम असफलता और नुकसान को सहज नहीं मानते, पर एकदंत सिखाता है कि कोई कमी हमारी पूरी पहचान नहीं बन सकती। गणेश उत्सव केवल आस्था का पर्व नहीं, जीवन को समझने का अवसर है। गणेशजी का स्वरूप विविधताओं को स्वीकारना सिखाता है- एकदंत अपूर्णता के बावजूद आगे बढ़ने, मूषक इच्छाओं पर संयम रखने, मिट्टी और विसर्जन प्रकृति, परिवर्तन व अनासक्ति को समझने, सामूहिक आरती आत्मीयता जगाने और विशाल उदर जीवन के हर अनुभव को स्वीकारने का संदेश देता है। दुखद है, हम उनके संदेशों को उस तरह स्वीकार नहीं कर पाते, जिस तरह करना चाहिए।

आरके जैन, शिक्षाविद

आत्मसात कर रहे गणपति का संदेश

गणेश उत्सव केवल भगवान गणेश के जन्मोत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विवेक, समरसता और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश देने वाला उत्सव भी है। आज, जब यह पर्व देश-विदेश में व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है, तब प्रश्न यह है कि क्या हम इसके मूल संदेशों को अपने जीवन में उतार पाए हैं? जवाब है, हां।

भगवान गणेश का पहला संदेश ज्ञान और विवेक का है। उन्हें 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है, लेकिन विघ्न करने का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि बुद्धि और सही निर्णय से समस्याओं का समाधान है। महाभारत के लेखन का प्रसंग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जहां गणेशजी ने वेदव्यास की शर्त स्वीकार करते हुए निरंतर लेखन किया और प्रत्येक श्लोक को समझकर लिखा। यह प्रसंग बताता है कि ज्ञान के साथ धैर्य और एकाग्रता भी आवश्यक है। आज नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर जोर बढ़ा है, जिसका अर्थ है कि नैतिक विवेक और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह, दूसरा संदेश विनम्रता और समानता का है। गणेशजी का वाहन एक छोटा-सा मूषक है, जो बताता है कि बड़ा और छोटा, शक्तिशाली और सामान्य- सभी का अपना महत्व है। सार्वजनिक गणेशोत्सव में विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों की सहभागिता इसी समावेशी भावना को मजबूत करती है। मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में अनेक मंडल सामाजिक सेवा, रक्तदान शिविर और पुस्तक वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह सकारात्मक पहल गणेशोत्सव को एक धार्मिक ही नहीं, सामाजिक उत्सव भी बनाती है।

तीसरा संदेश प्रकृति के साथ संतुलन का है। परंपरागत रूप से गणेश की प्रतिमाएं मिट्टी से बनती हैं और जल में सहज रूप से विलीन हो जाती हैं। हां, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन आस्था और पर्यावरण संरक्षण को साथ-साथ लेकर चलने की गंभीर कोशिश भी जारी है। कुल मिलाकर, गणेश उत्सव हमें बताता है कि सफलता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और सामूहिक जिम्मेदारी से मिलती है। सुखद है कि हम भगवान गणेश की पूजा के साथ-साथ उनके आदर्शों, यानी ज्ञान, समरसता, संयम और प्रकृति संरक्षण को भी स्वीकार करने लगे हैं। इससे इस पर्व की सार्थकता और बढ़ गई है। यही गणेशोत्सव की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छी बात है कि लोग इसे समझ रहे हैं और इसके अनुकूल कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे इस त्योहार का सबसे बड़ा प्रभाव मानना चाहिए।

दीपक, टिप्पणीकार

सभी दुखों का कारण अज्ञान

धर्म ग्रंथों में जिसे माया कहा गया है, असल जीवन में वह अज्ञान है। जब इंसान ज्ञान के अभाव में जीता है, तो उसे हर वह चीज या विचार सत्य लगता है, जो उसे लुभाता है। भले ही वह उसके दुखों का कारण बने, लेकिन मन उसे मानने को तैयार नहीं होता। सत्य यही है कि अज्ञान से मुक्त होकर ही दुखों से बचा जा सकता है।

अध्यात्म
रामचंद्र डोंगरे

जो नहीं हो, उसका भास कराए, वह 'माया' है। 'या' का अर्थ गति है। 'मा' निषेधात्मक है। माया के तीन भेद हैं- स्वमोहिका, स्वजनमोहिका और विमुखजनमोहिका। आत्मस्वरूप का विस्मरण माया है। माया जीव को मारती है। माया अर्थात अज्ञान का तुरंत नाश आवश्यक है।

सुदामा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे माया का दर्शन कराएं। कहा कि मुझे आपकी माया देखनी है। कृष्ण ने जवाब दिया,'बाद में बताऊंगा। अभी तो हम गोमती में स्नान करने को चलें।' कृष्ण ने स्नान करके पीतांबर पहनना शुरू किया और सुदामा ने जल में डुबकी लगाई। तभी प्रभु ने अपनी माया का विस्तार किया।

माया के दर्शन

सुदामा ने देखा कि नदी में बाढ़ आ गई है और वे बहाव में पड़ गए हैं। बहते-बहते वे एक घाट के पास आए और वहां बाहर निकल कर पास के गांव की तरफ चले। गांव के नजदीक आने पर एक हथिनी दौड़ती हुई आई और उसने सुदामा के गले में माला डाल दी। लोगों ने उन्हें बताया कि गांव की प्रथा के अनुसार राजा के मर जाने पर हथिनी जिसे हार पहनाए, वही राजा होता है। अब आप हमारे राजा हैं। राजकन्या के साथ उनका विवाह हुआ। इस प्रकार बारह वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और उनके संतानें भी हुईं।

मोह से ग्रस्त सुदामा

रानी बीमार हुई और उसकी मृत्यु हो गई।

सुदामा करुण विलाप करने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें समझाकर कहा, 'आप रोओ मत। गांव की प्रथा के अनुसार आपको रानी के साथ जाना है। रानी के शव के साथ आपको भी जलाया जाएगा।' यह सुनकर रानी के लिए रोना तो बंद हो गया और 'मेरा मरण होगा,' यह जानकर सुदामा रोने लगे।

जब रानी की चिता नदी के किनारे रखी गई, तो उन्होंने कहा-'मुझे एक बार स्नान कर लेने दो।' राजा भाग न जाए, इसलिए सैनिक चारों तरफ खड़े हो गए। भय से आतंकित सुदामा ने प्रभु का स्मरण करते हुए डुबकी लगाई। जब बाहर आए, तो देखा कृष्ण अभी पीतांबर पहन रहे हैं।

माया के प्रभाव से मुक्ति

सुदामा को रोते देखकर पूछा, 'रोते क्यों हो?' सुदामा ने कहा,'सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। रानी की मृत्यु हो गई है। वे सब कहां गए? यह सब क्या था? मेरी समझ में नहीं आता।' प्रभु मुस्कराते हुए बोले, 'तुमने माया के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, यह वही मेरी माया थी।'

माया की दो शक्तियां हैं। एक आवरण शक्ति, जो प्रभु को ढक कर रखती है और दूसरी विक्षेप शक्ति, जो ईश्वर की सत्ता में जगत का भास कराती है। इसमें जो नहीं होता, वह दिखता है और जो है, वह नहीं दिखता। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन पापी है। यह तुम्हारा पुत्र नहीं, पापी है, इसलिए इसका साथ छोड़ दो। लड़का यदि दुराचारी हो, तो मां-बाप की दुर्गति होती है। यह तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। माया के आवरण से आवृत्त धृतराष्ट्र ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारी बात तो सत्य है, पर दुर्योधन जब मेरे पास आता है, तो मुझे यह ज्ञान नहीं रहता।

दुख के कारण

अहंकार और ममता के कारण ही मन सुखी या दुखी होता है। जहां समता है, वहां मन दुखी नहीं होता। जहां समता नहीं है, वहां मन दुखी होता है। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। चाह रखकर प्रेम न करो। चाह से दुख और अशांति का जन्म होता है। यदि चाह रखनी ही है, तो प्रभु-प्रेम की चाह करो।

आज जो अच्छा लगता है, वह कल खराब लगेगा। जगत में कोई अच्छा नहीं है। मन का स्वभाव पानी की तरह है। पानी जिस प्रकार नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार मन की भी अधोगति है। जिस प्रकार यंत्र की सहायता से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार यदि किसी मंत्र से मन का साथ हो जाए, तो मन ऊपर चढ़ता है। मन को किसी मंत्र के साथ बांधो। किसी मंत्र के साथ प्रेम करो।

नाम जप और ध्यान

निर्गुण निराकार भगवान केशव दीपक की तरह हैं। वे प्रकाश देते हैं, किसी का दुख अथवा अज्ञान दूर नहीं करते। अनुग्रह और निग्रह भी नहीं करते।

सांसारिक वासनाओं में फंसने पर मन बिगड़ता है। अलौकिक वासना में लगने पर मन सुधरता है। काम कांटा है। कांटे को निकालने के लिए तो कांटा ही चाहिए। आसक्ति से बिगड़ा हुआ मन भक्ति से सुधरता है। जब प्रभु-मिलन की चाह खूब प्रबल होगी, तो सांसारिक वासनाएं स्वयं खत्म हो जाएंगी।

बिना क्रिया शक्ति के इच्छाशक्ति शुद्ध नहीं होती। सत्संग करने से मन सुधरता है। मन को शांत रखना महान पुण्य है। प्रभु के नाम और ध्यान से ही मन शांत रहेगा।

अहंकार और ममता के कारण ही मन सुखी या दुखी होता है। जहां समता है, वहां मन दुखी नहीं होता। जहां समता नहीं है, वहां मन दुखी होता है। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। चाह रखकर प्रेम न करो। चाह से दुख और अशांति का जन्म होता है।

क्षमावाणी पर्व

अहंकार छोड़कर माफी मांगें और माफ करें

सांख्य दर्शन में बुद्धि को अहंकार कहा जाता है। यद्यपि बुद्धि आत्मा का वैभव है, पर सांख्यानुसार बुद्धि आत्मा (पुरुष) की नहीं, प्रकृति की विकृति है।

क्षमादान और क्षमायाचना में बुद्धि सबसे बाधक तत्त्व बनता है। बुद्धि में असंख्य अनुभवों का संग्रह हो जाता है, विशेषतः कटु अनुभवों का। एक विशाल सूचनाओं का संग्रह मस्तिष्क में समाया हुआ है। किस व्यक्ति ने किस समय, किस तरह मुझे अपमानित किया। मेरा आर्थिक-भौतिक नुकसान किया। कौन-सा बंधुजन समय पर काम नहीं आया। किस पारिवारिक सदस्य का रुख उपेक्षापूर्ण रहा। इस तरह की शत-सहस्त्र-लक्ष-कोटि स्मृतियां बुद्धि प्रकोष्ठ में सुरक्षित रहती हैं और यही स्मृतियां किसी निकट या दूरवर्ती को क्षमा देने से रोकती हैं।

हृदय तो बहुधा कहता है- भूल जाओ पुरानी रंजिशों को, गिले शिकवे को, कटुतापूर्ण व्यवहारों को, पर बुद्धि है कि हृदय को बेदखल करके निर्णय ले लेती है- 'मैं क्षमादान क्यों दूं, मैं प्रतिशोध लेकर ही संतुष्ट होऊंगी।' आग, खून, जंग, विरोध ये मांग है बुद्धि की। कहीं शांति नहीं। किसी की भूल को भूलने की कला बुद्धि के पास नहीं, क्योंकि स्मरण रखना बुद्धि की विलक्षण क्षमता है।

माफ करो और भूल जाओ, ये दो शब्द हैं। यदि इनका क्रम रखें, तो क्षमादान शीघ्र संभव है। जो घटना को याद नहीं रख पाते, वे जल्दी क्षमा भी कर देते हैं। भूल गए और क्षमा का झरना स्वतः बहने लगा।

क्षमा का दूसरा पक्ष है- क्षमायाचना। इसमें भी सबसे बड़ी बाधा बुद्धि है, अहंकार है, जब मैं गलत हूं ही नहीं, तो क्षमा क्यों मांगूं? 'मैं' कभी गलत होता ही नहीं, ये धारणा है अहंकार की, बुद्धि की। अपराधी सामने वाला ही होता है। क्षमा मांगनी है, तो वह मांगे और मुझ से मांगे, बिना शर्त मांगे, आगे गलती नहीं करूंगा, यह कसम खाकर मांगे। ये सारी मांग है अहंकार की।

मैंने कसम खाई है, अपने मां के दूध की, मैं घोषणा करता हूं अपने अस्तित्व की। 'मर जाऊंगा, पर झुकूंगा नहीं।' बड़ी अकड़ है, इस अहंकार रूपी बुद्धि की, जो हमें किसी भगवान, गुरु और अच्छे इंसान के आगे भी झुकने नहीं देती। 'क्षमा मांगना कायरता है।' ऐसी सनक और सलाह देती है, हमारी अहंकारमयी बुद्धि। इस तरह व्यक्ति सबसे अलग-थलग अपने में, अपने गुमान में पड़ा रहता है। फिर आएं क्षमा पर्व, आएं पर्युषण, आएं दशलक्षण- कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं सुधरता।

अपने अंहकार ने हमें असफल कर दिया है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जो लिख गए हैं-'क्षमा वीरस्य भूषणम्'- क्षमा वीरों का आभूषण होता है। हमने महावीर की अनसुनी कर दी, जिन्होंने कहा था- 'खमावणयाए नब्भियत्तंजाणइ'- क्षमा से वातावरण में निर्भयता का संचार होता है।

हम मंदिरों में चले जाते हैं। पूजा-पाठ, माला जाप कर लेते हैं। उपवास भी हमारे धार्मिक कार्यों की सूची में है। हमारे साथ समस्या यही है कि हम न क्षमा देते हैं, न क्षमा लेते हैं, क्योंकि हम चलते हैं बुद्धि के भरोसे। हृदय विवश है, दिल बेबस है, उसकी कोई नहीं सुनता और ये सिलसिला चल रहा है। परमात्मा जाने, कब बुद्धि से मुक्त यह संसार क्षमा देगा और क्षमा लेगा?

-बहुश्रुत जयमुनि

राधा अष्टमी (19 सितंबर)

प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी

पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रीराधा का जन्म भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर बारह बजे हुआ था। लोक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन गोप वृषभानु नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने नदी किनारे एक कमल के फूल पर नन्हीं बच्ची को देखा। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री की तरह पाला। एक अन्य किंवदंती के अनुसार राधा वायु रूप में वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में प्रवेश कर गईं और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ, वह अब रावल के मंदिर का गर्भगृह है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थीं और उनका विवाह रायाण वैश्य से हुआ, जिन्हें रापाण और अयनघोष नाम से भी जाना जाता है।

शास्त्रों में श्रीराधा को कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। इन्हें प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी माना गया है। राधा का जिक्र महाभारत में नहीं है। भागवत पुराण में भी नहीं है। राधा के संबंध में सबसे पहले जानकारी पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थीं, इसलिए इन्हें वृषभानुजा भी कहते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना के करीब रावल ग्राम में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन यह मान्यता अधिक है कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को 'लाड़ली' कह कर पुकारा जाता है।

कृष्ण के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। राधा का विस्तार से वर्णन महाकवि जयदेव ने अपने संस्कृत काव्य 'गीत गोविंद' में किया है। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क ने जनमानस में सर्वप्रथम राधा-कृष्ण की युगल उपासना को प्रचलित किया था। इससे पहले कहीं भी राधा की पूजा कृष्ण के साथ नहीं की जाती थी। राधा-कृष्ण की युगल भक्ति की शुरुआत निम्बार्क, वल्लभ, राधावल्लभ, सखीभाव संप्रदाय आदि ने की थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा के अनुसार गोलोक में कृष्ण के पार्षद और सखा श्रीदामा राधा के शाप के कारण पृथ्वी पर शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्मे। वहीं श्रीदामा के शाप के कारण राधा ने भी पृथ्वी पर सौ वर्ष तक कृष्ण का वियोग सहा।

जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा ने अपना सारा जीवन कृष्ण की याद में बिताया। ऐसी मान्यता है कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण अपने परिवार के साथ और राधा वृंदावन से वहां आई थीं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा कृष्ण के पास द्वारका चली गई थीं।

-अश्वनी कुमार

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें:
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल,
द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी,
फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर-201301
(उत्तर प्रदेश)

आपदा और अवसर देगा मंगल

मंगल ग्रह के अपनी नीच राशि कर्क में आने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे? -गरुड़ध्वज शास्त्री, बरेली

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद्

मंगल ग्रह 18 सितंबर, 2026 को अपराह्न 04.44 बजे अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। अपनी नीच राशि कर्क में मंगल 12 नवंबर, 2026 को रात्रि 08.30 बजे तक रहेंगे। मंगल के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर पड़ने वाला प्रभाव :

मेष : कुछ चल-अचल संपत्ति की खरीद एवं बिक्री। संबंधों में तनाव। माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता।

वृष : छोटे भाई-बहन से जुड़े शुभ-अशुभ दोनों तरह के घटनाक्रम। कार्यक्षेत्र में संघर्ष के साथ तरक्की।

मिथुन : महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध। स्वास्थ्य समस्या। गलत निर्णय से हानि। दुर्घटना। संबंध में तनाव।

कर्क : स्वास्थ्य एवं संबंध में बाधा। विरोधियों से परेशानी। मरम्मत पर खर्च। आर्थिक लाभ। नई खरीदारी पर खर्च।

सिंह : निकट मित्रों एवं संबंधियों से मतभेद। खर्च की अधिकता। पारिवारिक अशांति। दुर्घटना। स्वास्थ्य समस्या।

कन्या : रुके काम बनेंगे। तरक्की। नए संबंध। नया पद, मान-सम्मान में वृद्धि। लाभकारी परिवर्तन।

तुला : आर्थिक लाभ, किंतु खर्च की अधिकता। अशांति। निवास/कार्यस्थल में परिवर्तन। संघर्षपूर्ण सफलता।

वृश्चिक : पिता का स्वास्थ्य चिंता देगा। महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध। मानसिक अशांति। स्वास्थ्य समस्या।

धनु : स्वास्थ्य समस्या। परिवार में दुर्घटना/सर्जरी। विरोधी हावी होंगे। कार्य में बाधा से निराशा। कुछ गुप्त लाभ।

मकर : नए संबंध-संपर्क बनेंगे। नए कार्य में संलग्नता या पूंजी निवेश। विवाद एवं नई साझेदारी में सतर्कता।

कुंभ : विवादपूर्ण सफलता। कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान। कुछ देनदारी का निपटारा। स्वयं या घर के सदस्य के निवास या कार्यस्थल में परिवर्तन होने की संभावना।

मीन : कार्यक्षेत्र में तरक्की। आमदनी के कुछ नए स्त्रोत। कुछ पुराने कार्यों के लिए सम्मान। कार्यक्षेत्र में गलत निर्णय से हानि। मन में आक्रोश बढ़ेगा।

सप्ताह के व्रत-त्योहार

15 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक

15 सितंबर (मंगलवार) : भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रातः 07.45 मिनट तक। भद्रा प्रातः 07.45 मिनट तक। ऋषि पंचमी व्रत। संवत्सरी महापर्व (जैन)।

16 सितंबर (बुधवार) : भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि प्रातः 09 बजे तक।

17 सितंबर (गुरुवार) : भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि प्रातः 10.49 मिनट तक। सूर्य षष्ठी व्रत। आश्विन संक्रांति। मुक्ताभरण/संतान सप्तमी व्रत। विश्वकर्मा जयंती। गंडमूल सायं 07.54 मिनट से।

18 सितंबर (शुक्रवार) : भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि दोपहर 01.02 मिनट तक। भद्रा दोपहर 01.02 मिनट से रात्रि 02.15 मिनट तक। श्री महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ।

19 सितंबर (शनिवार) : भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि अपराह्न 03.28 मिनट तक। श्री राधाष्टमी। दधीचि जयंती। गंडमूल रात्रि 01.43 मिनट तक।

20 सितंबर (रविवार) : भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि सायं 05.52 मिनट तक। श्रीचंद नवमी (उदासीन-संप्रदाय)। श्री भागवत सप्ताह पाठारंभ।

21 सितंबर (सोमवार) : भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि रात्रि 08.01 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि।

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के साथ विदेश जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

वृष : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

मिथुन : आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। मित्र के सहयोग से आय बढ़ेगी।

कर्क : कारोबार में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कन्या : आत्मविश्वास बहुत रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि कार्यों से धन की प्राप्ति हो सकती है। खर्चों में वृद्धि भी होगी।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। किसी नए कारोबार में निवेश कर सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। भागदौड़ बढ़ेगी।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

धनु : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। भागदौड़ बढ़ेगी।

मकर : मन परेशान हो सकता है। नौकरी में तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। अपनी व माता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

कुंभ : धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा।

मीन : आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि के कार्यों से आय में वृद्धि भी होगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

वर्ग पहेली : 8452

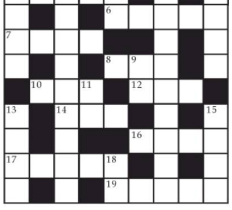

बाएं से दाएं
1. लानत-मलानत करना; लज्जित करने के लिए क्रोधपूर्वक कड़ी बातें कहना; झटका दे कर छितराना; भली-भांति पटक-पटक कर धोना (5)
6. जो कामयाब न हो; असफल; विफल; पराजित (5)
7. कलाकर्मी; अभिनेता; चित्रकार; रचनाकार (4)
8. खौफ खाना; भय खाना; सशंक होना; हिचकना (3)
10. टिड्डा; पतंगा; परवाना; फुनगा; प्रेमी (3)
12. काल; अवकाश; अवधि; अवसर; मौका (3)
14. क्रम; दस्तूर; धारा; कायदा; पद्धति; रीति (3)
16. पथिक; मुसाफिर; यात्री; राही (4)
17. पाताल में निवास करने वाला; पाताली; नाग जाति का व्यक्ति; बलि; शेषनाग (5)
19. जो मुनासिब न हो; अयोग्य; गैरवाजिब (5)

ऊपर से नीचे
1. रह-रह कर हिलना; थोड़ा-थोड़ा कंपित होना; स्पंदित होना; शरीर के अंग का स्फुरित होना (4)
2. कान साफ करना; सुनने योग्य बनना; सुनने के योग्य होना; सुनने में समर्थ होना (2,1,2,4)
3. विविध; अनेक; मातामह (2)
4. केवल प्रसिद्धि रह जाना; गुणवत्ता न रहना (2,1,2,2,2)
5. तबला बजाने वाला (4)
9. आनंद; मजा; सुख; स्वाद; अमृत; जल; सार; तरल भाग; पदार्थ का तरल अंश (2)
11. आशंका; खौफ; डर (2)
13. उपाहार; कलेवा; नाश्ता; पाथेय (4)
15. अचरज में डालने वाला काम; कला; करामात; जादू; माया; लीला; कौशल; गुण; हुनर (4)
18. छाती; टांका लगाना; सिलाई करना (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8451 का उत्तर

■	1स	2मा	प	न	3क	र	4वा	ना
5गि	■	द	■	■	ल	■	र	■
6न	शा	क	र	7ना	■	8आं	क	ना
वा	■	ता	■	का	■	■	र	■
9ना	10ता	■	11क्ष	म	ता	■	12ना	13स
■	रा	■	■	हो	■	14ध	■	र्व
15उ	मं	ग	■	16ना	नी	म	र	ना
■	ड	■	17बा	■	■	का	■	म
18उ	ल	टी	सी	धी	सु	ना	ना	■

सुडोकू : 8406

* कठिन

		7	8		5			9
	3				4	7	2	
			9					
4	7							3
		6				2		
8							5	7
					9			
	1	3	4				6	
9			3		2	1		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8405

9	3	8	7	6	5	4	1	2
7	6	4	1	9	2	8	3	5
5	2	1	8	4	3	7	9	6
8	5	9	3	1	6	2	7	4
1	4	3	2	8	7	5	6	9
2	7	6	9	5	4	1	8	3
4	9	7	6	2	1	3	5	8
3	8	2	5	7	9	6	4	1
6	1	5	4	3	8	9	2	7

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

15 सितंबर, मंगलवार, **शक संवत्** : 24 भाद्रपद (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 30 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 03 रबि-उल्सानी, 1448, **विक्रमी संवत्** : भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रातः 07.45 मिनट तक। विशाखा नक्षत्र, ऐंद्र योग दोपहर 12.20 मिनट तक पश्चात वैधृति योग, विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 07.45 मिनट तक। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। **सूर्य दक्षिणायन**। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 07.45 मिनट तक। ऋषि पंचमी व्रत। संवत्सरी महापर्व (जैन)।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कोण वेध क्या होता है? इससे होने वाले नुकसान और बचने के उपाय :

- **कोण वेध या द्वार वेध :** मुख्य द्वार के सामने या उसकी सीध में किसी भवन, कमरे या आसपास की संरचना का कोना पड़ता हो। पड़ोसी की दीवार का नुकीला कोना आपके मुख्य द्वार की सीध में हो। कोई कॉलम या खंबा आपके द्वार के सामने हो। सामने की किसी इमारत का कोना सीधे आपके मुख्य द्वार की ओर हो। इससे कामों में रुकावट, परिवार या व्यवसाय में आपसी मतभेद, कारोबार में बाधाएं एवं परेशानी, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। उपाय के लिए मुख्य द्वार के आसपास उचित मात्रा में प्रकाश रखें। उस वेध के आसपास पौधे लगाएं। अपने मुख्य द्वार के आस-पास भी पौधे लगाएं।

चिंतन

संविधान की मूल भावना के अनुरूप है यूसीसी

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर देश में बहस नई नहीं है, लेकिन अब यह बहस विचार के स्तर से आगे बढ़कर कानून और उसके क्रियान्वयन के स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करने की अवधारणा अपने आप में संविधान की उस भावना के अनुरूप है, जो कानून के सामने समानता और समान अधिकार की बात करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। यूसीसी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है। विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण महिलाओं के अधिकारों में जो असमानताएं दिखाई देती रही हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में समान कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी महिला के अधिकार केवल उसके धर्म या व्यक्तिगत कानून से तय न होकर समान नागरिक अधिकारों के आधार पर तय हों, यह संवैधानिक समानता की मूल भावना को मजबूत करता है। देश में यूसीसी को लेकर उत्तराखंड ने सबसे पहले कानून लागू करके एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके बाद अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इस दिशा में गतिविधियां तेज हुई हैं। गुजरात और असम में इससे संबंधित प्रस्ताव आगे बढ़े हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भी इससे जुड़े विधायी कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भाजपा शासित करीब 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने की योजना पर काम किए जाने की चर्चा इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी इसी बदलते राजनीतिक और विधायी परिदृश्य का संकेत है। हालांकि यूसीसी का उद्देश्य समानता स्थापित करना है, लेकिन इसकी सफलता केवल कानून बनाने से तय नहीं होगी। इसी संदर्भ में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर उठने वाली आपत्तियों और न्यायिक चुनौती को भी गंभीरता से देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का मुद्दा इस व्यापक बहस का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने इसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूसीसी के विरोध के साथ कानूनी लड़ाई की रणनीति पर चर्चा और 17 सितंबर को जंतर-मंतर के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से लोगों की भागीदारी की अपील बताती है कि विरोध का पक्ष भी अपनी बात लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से रखने की तैयारी कर रहा है। यूसीसी यदि वास्तव में समान नागरिक अधिकारों का माध्यम बनना है तो उसकी बुनियाद किसी समुदाय के विरुद्ध राजनीतिक ध्रुवीकरण पर नहीं, बल्कि लैंगिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों पर होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त लक्ष्य है। इसलिए इस पर चर्चा या कानून बनाने को असंवैधानिक कहना उचित नहीं होगा। लेकिन संवैधानिक भावना का अर्थ केवल समान कानून बनाना नहीं, बल्कि समानता के साथ न्याय और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। यूसीसी तभी सफल होगा, जब वह समाज को बांटने के बजाय नागरिकों के बीच समान अधिकार और समान न्याय का भरोसा मजबूत करे।

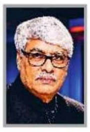

मुद्दा
ओमकार चौधरी

मोदी को ब्रिक्स से नई ऊर्जा

> 2027 के विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ पांच राज्यों की सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि 2029 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की जमीन भी तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों से पहले भाजपा 2024 के बाद मिली लगातार चुनावी सफलताओं के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने से पार्टी का मनोबल बढ़ा है, वहीं दिल्ली में वापसी और अन्य राज्यों में एनडीए की जीत ने विपक्ष की चिंता बढ़ाई है। इसी बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कूटनीतिक सफलता भाजपा के लिए राष्ट्रवाद और वैश्विक नेतृत्व का नया चुनावी नैरेटिव तैयार कर सकती है।

भारतीय राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और भाजपा नेतृत्व अभी से इसकी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इस बार भाजपा किसी नई शुरुआत के साथ नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मिली सिलसिलेवार जीतों के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है। साथ ही, नई दिल्ली में अभी-अभी संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कूटनीतिक सफलता भी उसके लिए एक सकारात्मक माहौल बना रही है, जिसका सीधा असर आने वाले चुनावों में मतदाताओं की सोच पर पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक देश के करीब ग्यारह राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और इनमें से सात से ज्यादा में एनडीए-भाजपा की सरकारें बन चुकी हैं।

आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही एनडीए को जीत मिली थी। इसके बाद हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा, तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली में करीब 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई और बिहार में एनडीए ने अपना गठबंधन बरकरार रखा।लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कामयाबी रही पश्चिम बंगाल। मई 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए पहली बार राज्य में सरकार बनाई और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। यह जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि बंगाल लंबे समय से भाजपा के लिए एक दुर्गम किला माना जाता रहा है। इसी के साथ असम में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई और पुडुचेरी में भी एनडीए जीता। हालांकि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने दस साल बाद सत्ता में वापसी की, और तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया यानी तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है, लेकिन बड़े और रणनीतिक रूप से अहम राज्यों में भाजपा-एनडीए की लगातार जीत ने पार्टी को एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर दी है। यही वजह है कि विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। चिंता यह है कि अगर भाजपा का यही जीत का सिलसिला 2027 में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी बरकरार रहा, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए चुनौती और भी विकराल हो जाएगी। यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में भाजपा को सत्ता की हैट्रिक की उम्मीद है, हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूला उसके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं, पंजाब अकेला ऐसा राज्य है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है यहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद सक्रिय होकर रैलियां कर रहे हैं और समय से पहले चुनाव की आशंका तक जता चुके हैं, जो दिखाता है कि पंजाब में मुकाबला भाजपा के लिए एक अलग ही रणनीति की मांग करता है।

ठीक इसी दौर में, जब भाजपा 2027 के चुनावों की जमीन तैयार कर रही है, नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक साख को और मजबूत कर दिया है। भारत की

अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से अपनाया गया और यह इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें आपस में गहरे मतभेद रखने वाले ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी शामिल हैं। सबसे उल्लेखनीय रहा भारत का कूटनीतिक मध्यस्थता कौशल। ईरान जहां चाहता था कि घोषणा पत्र में अमेरिकी-इज़रायली हमलों और पश्चिमी प्रतिबंधों की स्पष्ट निंदा हो, वहीं यूएई की मांग थी कि खाड़ी क्षेत्र पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों की भी निंदा शामिल की जाए यानी दोनों पक्षों की मांगें एक-दूसरे से पूरी तरह टकरा रही थीं। भारत ने रातभर, यानी सुबह चार बजे तक चली बातचीत के जरिए इन मतभेदों को दूर किया और एक ऐसा संतुलित साझा बयान तैयार करवाया जिसमें किसी देश का नाम लिए बिना हर तरह की आक्रामकता की निंदा की गई। इसके अलावा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा, आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ सख्त रुख, आतंकवाद को धर्म से न जोड़ने की बात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को रूस-चीन का समर्थन, और एकतरफा टैरिफ की निंदा जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुआ यह सम्मेलन पीएम मोदी की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करता है।

राजनीतिक नजरिए से देखें तो ऐसे कूटनीतिक आयोजनों का असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच तक सीमित नहीं रहता। भारत जैसे देश में जहां राष्ट्रवाद और वैश्विक नेतृत्व की छवि चुनावी विमर्श का अहम हिस्सा बन चुकी है, वहां ब्रिक्स जैसी सफलताएं मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक और गर्व का संदेश देती हैं भारत अब सुनता नहीं, बल्कि दुनिया को सुनाता है यह नैरेटिव आने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार में भाजपा के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव का औजार बन सकता है। लेकिन चुनावी राह इतनी आसान भी नहीं है। घरेलू मोर्चे पर जातीय राजनीति एक नया मोड़ लेती दिख रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अगस्त 2026 से 'रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन' के नाम से सामान्य वर्ग और सवर्ण संगठनों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना जैसे संगठन शामिल हुए हैं। यह आंदोलन यूजीसी के नए समानता (इक्विटी) नियमों के विरोध में भड़का, जिन्हें दलित-आदिवासी-ओबीसी संगठन जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि सवर्ण संगठन इसे अपने खिलाफ दुरुपयोग की आशंका के तौर पर देखते हैं।

भाजपा खेमे के कई नेताओं का यह भी दावा है कि विपक्षी दल 2027 के यूपी चुनाव से पहले जानबूझकर हिंदू वोटों को जातीय आधार पर बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसा दावा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किया गया था। हालांकि विपक्ष और सामाजिक न्याय से जुड़े संगठन इसे साजिश नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानता और जातीय भेदभाव का एक वास्तविक और लंबित मुद्दा मानते हैं। यह बहस आने वाले महीनों में और तेज होने की पूरी संभावना है।कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा 2027 के पांच राज्यों के चुनावी मैदान में दो बड़े हथियारों के साथ उतर रहे हैं एक तरफ 2024 के बाद मिली सिलसिलेवार चुनावी जीतों, खासकर बंगाल जैसे मुश्किल किले की फतह का आत्मविश्वास, और दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच पर मिली कूटनीतिक कामयाबी का सकारात्मक और राष्ट्रवादी संदेश। लेकिन घरेलू मोर्चे पर सवर्ण-आरक्षण बहस, जातीय ध्रुवीकरण की कोशिशें और पंजाब जैसे राज्य में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की मौजूदगी ये सब मिलकर यह तय करेंगे कि क्या भाजपा अपनी इस जीत की यात्रा को अगले चरण में भी बरकरार रख पाती है, या विपक्ष इन्हीं मुद्दों के सहारे अपनी 2029 की राह को थोड़ा आसान बना पाता है। आने वाले महीनों में यह राजनीतिक संग्राम और तेज होना तय है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मंथन
ज्ञानेन्द्र रावत

आखिर कब समझेंगे हम हिमालय की पीड़ा

नेपाल त्रासदी ने हिमालय को, उसके मूल चरित्र को बूझने-समझने का हमें फिर एक अवसर प्रदान किया है, जबकि बीते दशकों की घटनाएं हमें बार-बार सचेत करती रही हैं। नेपाल में आई आपदा के खतरे की चेतावनी भी करीब 5 महीने पहले इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट के जरिए दी थी, लेकिन दुखद है कि बार-बार दी जा रही चेतावनियों को हम नजरंदाज करते रहे हैं। यह भी कि बीते दशकों की घटनाओं से हमने न तो कोई सबक सीखा और न उनसे निबटने की बाबत कोई कारगर प्रयास ही किए। नेपाल की घटना ने यह साफ कर दिया है कि इस इलाके में भूस्खलन और जलवायु जैसे जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों के फटने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से ऐसी आपदाओं की आशंका, आवृत्ति और घातकता काफी बढ़ जाती है। इसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरा हिमालयी अंचल अपनी बनावट और प्राकृतिक विशेषताओं के चलते स्वाभाविक रूप से आपदाओं के प्रति काफी संवेदनशील है। यह दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, जिसकी चट्टानें और मिट्टी पूरी तरह जमी और कठोर नहीं है, जिसके कारण इस इलाके में मामूली हलचल से ही भू-स्खलन हो जाना आम बात है। यहां के पहाड़ और ढलान बहुत ही तेज, तीखे और सीधे हैं, जिसकी वजह से बर्फबारी या बारिश के दौरान पहाड़ी मिट्टी और चट्टानें तेजी से नीचे गिरती हैं। इससे ग्लेशियर फटने का खतरा हर समय बना रहता है। इसकी इसी खासियत और ऊंचाई की वजह से इस इलाके में बारिश भी खूब होती है जो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसका एक अहम कारण यह भी है कि इंडियन टैक्टोनिक प्लेट लगातार उत्तर की ओर खासकर यूरेनियम प्लेट से टकरा रही है जिसके निरंतर टकराव की वजह से भूमि के भीतर भारी तनाव पैदा होता है।हिमालयी अंचल मे घटती वन छतरी भी पहाड़ों के दरकने की अहम वजह है। अध्ययनकर्ता वैज्ञानिकों की मानें तो पेड़ों की कटाई, पहाड़ों पर बेतहाशा बढ़ता जा रहा निर्माण और जलवायु परिवर्तन वन छतरी घटने की प्रमुख वजह है। क्योकि वन छतरी यानी पेड़ों की पत्तियों , टहनियों और शाखाओं से जमीन के ऊपर बनी प्राकृतिक परत बारिश की बूंदों की जमीन पर सीधी मार को कम करती है। इनके न होने से बारिश की बूंदों की सीधी मार जमीन पर गिरती है जिससे ढलान की मिट्टी में पानी और जल दबाव बढ़ जाता है। सदी के अंत तक कई हिमालयी इलाकों से बर्फ लगभग गायब हो सकती है। यह हिमालयी अंचल में तेजी से बदल रहे मौसम के मिजाज का सबूत है। मौसम में आ रहा यह बदलाव ग्लेशियरों के पिघलने की दर को गहराई से प्रभावित कर रहा है। इसके कारण हिमालयी क्रायोस्फीयर कहें या बर्फीला तंत्र पहले से अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। नतीजतन हिमालयी ग्लेशियर तेजी से बर्बाद हो रहे हैं। हिमालय के तकरीबन 60 हजार से भी अधिक ग्लेशियर एशिया की दस बड़ी नदियों और सैकड़ों सहायक नदियों के स्रोत हैं। इन पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन,भूटान, बांग्लादेश, हिंदचीन और मध्य ऐशिया के करीब दो अरब लोगों का जीवन यानी भोजन, पानी और ऊर्जा पर आधारित है। इन ग्लेशियरों का करीब-करीब तीन चौथाई हिस्सा समुद्र तल से मात्र 4500 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इसरो के सैटेलाइट अध्ययन के अनुसार 2431 बड़ी झीलें चिन्हित की गई हैं, जिनका आकार 10 हैक्टेयर से अधिक है। इनमें से 676 का आकार 27 फीसदी से भी अधिक बड़ा है। इनमें 130 सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी आस्ट्रिया और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के हालिया अध्ययन के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में वर्तमान में 24,440 ग्लेशियर झीलें हैं जिनमें 221 बेहद संवेदनशील और खतरनाक हैं जो कभी भी बम की तरह फट सकती हैं। निष्कर्ष यह कि नेपाल की हालिया त्रासदी ने न केवल ग्लेशियरों की निगरानी पर ही सवाल खड़े नहीं किए हैं, उसने चेतावनी तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस त्रासदी ने हिमालयी अंचल के देशों यथा- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और म्यांमार सहित हिमालयी भारतीप राज्यों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। यही नहीं नेपाल त्रासदी को हमें केवल एक आपदा के रूप में नहीं ,बल्कि एक सामरिक, वैज्ञानिक और मानवीय चुनौती के रूप में देखने की जरूरत है। यह सब पर्यावरण संवेदनशीलता के सही मायने में समन्वय से ही संभव होगा। उसी स्थिति में हम मानवजनित ऐसी आपदाओं के भंवर से बाहर निकलने और अपने भाल हिमालय को बचा पाने में समर्थ हो पाएंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

धैर्य के साथ करें आत्ममूल्यांकन

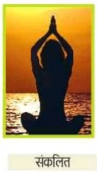

संकलित
दर्शन

प्रकृति हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमें प्रेरित व उत्साहित करती रहती है। हर पेड़, पौधे, फूल, पत्ती का एक मौन संदेश हुआ करता है और वह है कि स्वयं को निरंतर गतिमान और संतुलित रखने के लिए धैर्य चाहिए। पेड़ों पर मंजरी या बौर आने के तुरंत बाद ही तो फल नहीं आ जाता। हौले-हौले ही यह प्रक्रिया सम्पन्न होती है। माटी, हवा और पानी से जिस तरह एक पौधा धीरज रखकर खुद को पुष्पित और पल्लवित करता है, हमें भी ऐसा ही जीवन दर्शन अपनाना चाहिए। महर्षि अरविंद अपने पास आने वाले जिज्ञासु को यह मंत्र देते थे कि मनुष्य अपने सारे जीवन का वास्तुकार स्वयं ही है। हम अपनी रुचि और सोच-विचार के हिसाब से दिनचर्या तय करते हैं। अपने तौर तरीके से दिन बिताते हैं। सब सामान्य रहता है, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन इस दिनचर्या में कुछ जरा-सा भी कुछ अनचाहा हुआ नहीं कि हम सिर पीटने लगते है। हमारा धैर्य डोल जाता है। हमारी पसंद से बने हुए जीवन की हलचल और हिचकोले हमें विचलित कर देते हैं। हम गलती से भी आत्म अवलोकन नहीं करते। हम अपनी भूमिका न देखकर किसी और पर दोष मढ़ देते हैं। ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि इस हालत के लिए उनके अलावा सब ही जिम्मेदार हैं। आरोप लगाने और खुद साफ बच जाने के इस पल में हम चतुराई से यह सच छिपा जाते हैं कि कर्म का नियम कुछ और ही है। कर्म का सिद्धांत यह साफ कहता है कि हमारे हर दुख कष्ट आदि के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं।

चंद्र देव को दक्ष ने दे दिया था शाप

संकलित
प्रेरणा

चंद्र और दक्ष प्रजापति से जुड़ी कथा है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र देव से किया था। दक्ष की सभी पुत्रियों में रोहिणी सबसे सुदर थी। इसी वजह से चंद्र रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण दक्ष की शेष 26 पुत्रियों को रोहिणी से जलन होने लगी। इन 26 पुत्रियों ने ये बात अपने पिता प्रजापति दक्ष से कह दी। दक्ष ये सुनकर गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्र को धीरे-धीरे क्षीण होने यानी खत्म होने का शाप दे दिया। दक्ष के शाप से चंद्र देव धीरे-धीरे घटने लगा यानी खत्म होने लगे। चंद्र देव ने दक्ष के शाप का असर खत्म करने के लिए ब्रह्माजी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र को सलाह दी कि उन्हें प्रभास क्षेत्र (सोमनाथ का क्षेत्र) में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। शिव जी की कृपा से तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्र ने प्रभाष क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या शुरू कर दी। चंद्र के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और दक्ष के शाप का असर कम करके अमर होने का वरदान दे दिया। दक्ष के शाप का असर कम होने से चंद्र कृष्ण पक्ष में क्षीण यानी खत्म होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ने लगता है। पूर्णिमा को पूर्ण रूप हो जाता है। चंद्र देव ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि वे प्रभाष क्षेत्र में ही वास करें। चंद्र देव की प्रार्थना मानकर भगवान ज्योति स्वरूप में प्रभाष क्षेत्र में विराजित हो गए। यहां चंद्र देव ने शिवलिंग स्थापित किया था, इसी वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा है।

अंतर्मन

आज की पाती

हिंदी अपनाने में हर्ज क्या है?

14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। हिंदी का देश में विस्तार करने के लिए तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी 'कोई' भाषा नहीं, बल्कि हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत में कई राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी में लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह अच्छी बात है कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन देश की राजभाषा हिंदी को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना मातृभाषा को। आज हिंदी कुछ अंग्रेजी कारण तो कुछ स्थानीय भाषाओं के बीच पिस रही है। इस कारण आज आजादी के इतने सालों बाद भी हिंदी को वो उच्च स्थान नहीं मिल सका है जो मिलना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना होगा। - *राजेश तिवारी, भिलाई*

करंट अफेयर

लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती

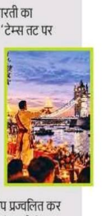

लंदन में टेम्स नदी के तट पर रविवार को पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। 'टेम्स तट पर गंगा आरती : प्रकाश उत्सव' नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन 'चिन्मय मिशन यूके' ने 'टोटली टेम्स' के वार्षिक उत्सव के सहयोग से किया। यह आयोजन 'चिन्मय मिशन' की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दुनियाभर में हो रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। भारत में गंगा के तट पर होने वाली प्रसिद्ध आरती की परंपरा से प्रेरित इस आयोजन की परिकल्पना प्रकृति, ज्ञान और चेतना के जीवनदायी प्रवाह के प्रतीक के रूप में की गई थी।'चिन्मय मिशन यूके' की शिक्षिका ब्रह्मचारिणी श्रीप्रिया चैतन्य ने कहा, पीढ़ियों से श्रद्धालु गंगा के तट पर दीप प्रज्वलित कर मां गंगा की आराधना करते और प्रकृति एवं जीवन को संवारने वाली दिव्य शक्तियों के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता दर्शाते आए हैं। उन्होंने कहा,"टेम्स नदी के तट पर गंगा आरती भी इसी भावना को आगे बढ़ाती है और कृतज्ञता, आशा तथा एकता के साझा भाव में लोगों को एक साथ लाती है। चैतन्य ने बताया कि चिन्मय मिशन के लिए गंगा ज्ञान के प्रवाह का भी प्रतीक है।

ऑफ बीट

आराम के समय हृदय गति की भी अपनी छिपी लय होती है

आपने संभवत: 'सर्केडियन रिदम' यानी शरीर की उस 24 घंटे की जैविक घड़ी के बारे में सुना होगा, जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। लेकिन अब यह सामने आया है कि आराम की अवस्था में हृदय की गति भी ऐसी रहस्यमयी और लंबी अवधि वाली लय का अनुसरण करती है, जो बाहरी दुनिया से स्वतंत्र रूप से चलती है। आराम की अवस्था में हृदय गति से आशय उस समय प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या से है, जब व्यक्ति शांत और निष्क्रिय अवस्था में हो। यह माप तनाव, थकान और शारीरिक फिटनेस से जुड़ा होता है। अध्ययन में पता चला कि 70 प्रतिशत प्रतिभागियों की आराम की अवस्था वाली हृदय गति एक धीमी जैविक लय का अनुसरण करती थी। 'स्मार्टवॉच' यानी ऐसी डिजिटल घड़ी जो समय बताने के साथ-साथ शरीर और दैनिक गतिविधियों से जुड़ी कई जानकारियां भी दर्ज करती है। इन लय में सप्ताह, महीने या यहां तक कि 10 सप्ताह तक के अलग-अलग चक्र पाए गए। इन चक्रों के दौरान प्रति मिनट दिल की गति एक निश्चित क्रम के अनुसार बढ़ती और घटती रही। इन चक्रों की पहचान से मानव शरीर की जैविक समय-व्यवस्था के बारे में हमारी समझ का विस्तार होता है और इसका इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।

X ट्रेंड f

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन का यह पावन पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उनके दिव्य आशीर्वाद से सभी के प्रयास सफल हों। गणपति बाप्पा मोरया!
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भाषा कुंज का लोकार्पण

नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा विभाग के 'राजभाषा कीर्ति' एवं 'राजभाषा गौरव' पुरस्कार वितरित किए। भारतीय बहुभाषी अनुवाद 'सारथी' मोबाइल एप व देश के पहले डेटा सेंटर 'भाषा कुंज' का लोकार्पण किया। -अमित शाह, गृहमंत्री

खाने पर राजनीति

मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी ब्रिक्स देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेन्यू पर भी राजनीति कर रही है। हमारे मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी भोजन का आनंद लिया, जो स्वाद और पोषण से भरपूर था और जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराओं की झलक थी।
-किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

पसंद थोपती है भाजपा

भाजपा का लोगों पर पसंद थोपना पहले से ही समस्या है। दुनियाभर से आए गणमान्य लोगों पर भी अपनी पसंद थोपकर इसे एक कदम आगे बढ़ा दिया है। भारत एक समृद्ध, विविधतापूर्ण और कई व्यंजनों वाला देश है। यहां मांसाहारी व्यंजनों की भी कई बेहतरीन किस्में है, जिन्हें लोग पसंद करते है और बड़े चाव से खाते हैं। -पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]

📍 Hindi Editorials PDF

📍 Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world. Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click Here